राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 61

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 10 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

नीरज बोले, मेरा यह पदक पूरे देश के लिए >> 12

टोक्यो से घर लौटे देश के हीरो

- हवाईअड्डे के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़
- कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ीं
- खेल मंत्रालय ने किया भारतीय एथलीटों का स्वागत

टोक्यो से नई दिल्ली पहुंचने के बाद प्रशंसकों के स्वागत से अभिभूत नीरज चोपड़ा। ● रायटर

जागरण टीम, नई दिल्ली: भारत माता की जय, वंदेमातरम...टोक्यो में इतिहास रचने वाले भारतीय हीरो को लेकर जैसे ही हवाई जहाज देश की राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा वैसे ही ये नारे गुंजायमान होने लगे। यहां से इन हीरो का काफिला अशोका होटल की तरफ चला तो मीडिया की गाड़ियों के साथ रिश्तेदार और प्रशंसकों ने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी। हालांकि, इस दौरान अफरातफरी भी मची और कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां भी उड़ीं। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पदक विजेता एथलीटों को सम्मानित किया।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया, कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, कांस्य पदक विजेता पुरुष हाकी टीम और चौथे नंबर पर रही महिला हाकी टीम के साथ बाकी एथलीटों का स्वागत किया। हवाईअड्डे के बाहर परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में प्रशंसक और कुछ स्थानीय नेता मौजूद थे। यह प्रशंसक भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और ढोल व बैंड की धुनों पर गाने व थिरकने के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों का जयघोष कर रहे थे। कुछ प्रशंसक हवाईअड्डे के बाहर पुश-अप्स भी कर रहे थे।

बजरंग पूनिया ने एसयूवी के 'सनरूफ' से बाहर निकल कर हाथ हिलाते हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया तो नीरज चोपड़ा कह रहे थे उनकी गाड़ी का पीछा न करें। यातायात नियमों का पालन करें। भारत ने टोक्यो ओलिंपिक में सात पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू और कांस्य पदक विजेता शटलर पीवी सिंधू पहले ही टोक्यो से लौट आईं थीं, क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकाल के कारण खिलाड़ियों को पदक वितरण समारोह के 48 घंटों के भीतर टोक्यो छोड़ना था।

संबंधित खबरें >> पेज 12

बजरंग को कंधे पर उठाए साथी ● एएनआइ

स्वतंत्रता के सारथी — महामारी से आजादी

तकनीक के सहारे दिखाई टीकाकरण की राह

कानपुर: स्वतंत्रता पर्व की तैयारियों के बीच ऐसे नायकों की चर्चा जरूरी है जिन्होंने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कोरोना महामारी से आजादी की अलख जगाई। आज कानपुर के दो दोस्तों के बारे में जानते हैं जिन्होंने टीका लगवाने में आम जनता की अनूठे तरीके से मदद की। (पेज-6)

जज हत्याकांड की जांच पर नजर रखेंगे झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जिले न्यायाधीश की कथित हत्या के मामले में सीबीआइ को हर सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की जांच की निगरानी करने का अनुरोध भी किया है। (पेज-3)

देश को इस हफ्ते मिल सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन

नई दिल्ली : देश को इस हफ्ते कोरोना रोधी छठी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। भारत के दवा नियामक (डीसीजीआइ) से इस हफ्ते जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने इस मंजूरी के लिए पिछले महीने आवेदन किया था। यह तीन डोज की वैक्सीन है। अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जायडस ने इस टीके के लिए देश में सबसे ज्यादा 50 केंद्रों पर परीक्षण किया है। (पेज-6)

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन

बड़ा कदम ▶ तीन आर्थिक विधेयक संसद से पारित, उपभोक्ताओं के हितों की होगी रक्षा

केयर्न एनर्जी, वोडाफोन समेत 17 कंपनियों से जुड़े इस टैक्स के सभी केस होंगे खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तीन महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयकों को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। ये बिल देश के आर्थिक विकास में मददगार होने के साथ आम लोगों की बचत की सुरक्षा करेंगे। इनमें डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त करने के लिए टैक्सेशन संशोधन बिल और कारोबार को आसान करने के लिए ट्रिब्यूनल बिल शामिल हैं। टैक्सेशन संशोधन बिल पर संसद की मुहर के साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन हो गया। इस विधेयक से पूर्व काल से लागू टैक्स का अंत हो जाएगा।

टैक्सेशन संशोधन बिल को संसद की मंजूरी से भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी। केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले समाप्त हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बिल से वर्ष 2012 से जारी रहने वाले भूत का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से टैक्स लेने से विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे में मैं सदन से भारत को पारदर्शी व निष्पक्ष टैक्स वाला देश बनाने में समर्थन की मांग करती हूं। इस बिल के पारित होने पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत ली गई राशि की वापसी में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। टैक्स से जुड़े सभी केस वापस ले लिए जाएंगे।

भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश में बढ़ोतरी होगी

लोकसभा में सोमवार को बोलती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

2012 से पहले के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले वापस लिए जाएंगे

सरकार ने 2012 से पहले के सभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले वापस लेने का फैसला किया है। इस मद में वसूले गए टैक्स भी सरकार वापस करेगी। इसके तहत 28 मई, 2012 से पहले परोक्ष रूप से भारतीय संपदा के ट्रांसफर पर लगने वाले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म हो जाएंगे।

संप्रग सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स

संप्रग सरकार के कार्यकाल में लागू किए गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर विधेयक में कहा गया है कि इससे आकर्षक निवेश वाले स्थान के रूप में भारत की छवि को धक्का लगा है। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन के लिए कई पहल की गई। इसके बावजूद निवेशकों के मन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की शंका कायम रही, जो कहीं न कहीं निवेश को प्रभावित कर रही थी।

एयर इंडिया के विनिवेश में होगी आसानी

- टैक्सेशन संशोधन बिल पारित होने से एयर इंडिया और शिपिंग कारपोरेशन के विनिवेश में भी आसानी होगी।
- केयर्न एनर्जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों में भारत की संपदा पर अपना दावा कर रही है।
- इनमें एयर इंडिया और शिपिंग इंडिया की संपदा भी शामिल है।

बैंक के डूबने पर मिलेगी पांच लाख तक की राशि : डिपोजिट इंश्योरेंस बिल के पारित होने से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक समेत 23 ऐसे सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जो वित्तीय दबाव झेल रहे हैं, लेकिन वे मोरेटोरियम में नहीं हैं। इन बैंकों के जमाकर्ता को भी अगले 90 दिनों के भीतर पांच लाख तक की जमा राशि मिल जाएगी। अभी बैंक में जमा सिर्फ एक लाख रुपये तक की राशि का ही इंश्योरेंस है। यानी बैंक के डूबने पर चाहे जमाकर्ता की रकम कितनी ही क्यों न हो, उसे सिर्फ एक लाख रुपये वापस मिलते हैं। डिपोजिट गारंटी के नए नियम के तहत सभी प्रकार के बैंक में जमा पांच लाख तक की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस बिल के लागू होने से बैंकों के 98.3 फीसद जमा खाते (डिपोजिट एकाउंट) पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे।

कारोबार में आसानी के लिए ट्रिब्यूनल बिल पारित : कारोबार को और सुगम बनाने और विवाद को लंबा खींचने से बचाने के लिए ट्रिब्यूनल बिल भी रास से पारित हो गया। इसके साथ ही फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण समेत नौ प्रकार के ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएंगे। विपक्ष ने कहा कि यह बिल न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। इस पर सीतारमण ने कहा, सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है।

समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए बढ़ाएं सहयोग

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने समुद्री व्यापार व विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत पांच सिद्धांत पेश किए। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है।

पीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावाः अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर परिचर्चा के दौरान आतंकवाद व अपराध के लिए समुद्री मार्ग के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने जोर दिया कि महासागर दुनिया की साझा विरासत हैं और समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवनरेखा हैं। समुद्र विरासत साझा करने वाले देशों के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मोदी ने पांच सिद्धांत पेश किए।

मोदी ने पहले सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। वैश्विक समृद्धि समुद्री व्यापार के सहज संचालन पर निर्भर करती है। समुद्री व्यापार के समक्ष कोई भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है। दूसरे सिद्धांत को लेकर कहा, समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। यह पारस्परिक विश्वास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र रास्ता है जिसके जरिये हम वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

- पीएम ने संरा सुरक्षा परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता कर पांच सिद्धांतों पर जोर दिया
- खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से यूएनएससी में खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। एएनआइ

पांच सिद्धांत

- वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना
- विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर हो
- प्राकृतिक आपदाओं व आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे
- समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए
- समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए

समुद्री अपराधों से निपटने को संरा के भीतर विशेष ढांचा बने : पुतिन

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक विशेष ढांचा स्थापित करने का आह्वान किया जो विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री अपराधों से लड़ने के मुद्दे से सीधे तौर पर निपटेगा। समुद्री सुरक्षा पर चर्चा में पुतिन ने रेखांकित किया कि कुछ देशों के क्राइम सिंडीकेट,डाकुओं व आतंकियों के खिलाफ लड़ न पाने से समुद्री डकैतियों और बंधक बनाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पुतिन ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रमुख मानदंडों व सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का पक्षधर है। निस्संदेह, हमारा लक्ष्य फारस की खाड़ी के क्षेत्र और अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है, जहां समुद्री डकैतियों और बंधक बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं।

तीसरे सिद्धांत के बारे में पीएम ने कहा, वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं व आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का मिलकर सामना करना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण और समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना, मोदी द्वारा सुझाए गए चौथे व पांचवें सिद्धांत रहे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक. यूएनएससी की परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार के प्रमुख व संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर पूर्व में चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किए हैं। यह पहली बार था जब खुली बहस में विशेष एजेंडे के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र चर्चा की गई। (संबंधित खबर पेज-3 पर)

बांग्लादेश में चार मंदिरों पर हमला, मूर्तियां तोड़ीं

- मस्जिद के सामने से भजन गाते हुए जा रहे हिंदुओं को बनाया निशाना
- कट्टरपंथियों ने घरों और दुकानों में भी की जमकर लूटपाट

ढाका, प्रेट्र: पाकिस्तान में हाल ही में गणेश मंदिर को तहस नहस करने की गंभीर घटना के बाद अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने मंदिरों को निशाना बनाया है। उन्मादी भीड़ ने पहले मस्जिद के सामने से कीर्तन करते हुए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला बोला, उसके बाद चार मंदिरों पर धावा बोल दिया और वहां स्थापित भगवान की दस प्रतिमाओं को तोड़ दिया। यही नहीं कट्टरपंथियों की भीड़ के रास्ते में जो भी हिंदुओं के घर व दुकान दिखे, उनमें लूटपाट की गई।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, खुलना जिले के रूपसा उप नगर के शियाली गांव में कट्टरपंथियों ने शनिवार को इन घटनाओं को अंजाम दिया। पीड़ितों के अनुसार शियाली में कुछ श्रद्धालु कीर्तन करते हुए महाश्मशान मंदिर की ओर भजन गाते हुए जा रहे थे। जैसे ही श्रद्धालु मस्जिद के सामने से निकले, कट्टरपंथी मुस्लिमों ने घेर लिया और बुरी तरह मारा-पीटा। इसके बाद भीड़ ने महाश्मशान मंदिर पर धावा बोला और वहां जमकर तोड़फोड़ की। रास्ते में जो भी हिंदुओं के घर पड़े उनमें लूटपाट की गई। छह दुकानों को भी लूटा।

मामला यहीं नहीं रुका, कट्टरपंथियों की भीड़ शियाली पुरबापारा पहुंच गई। यहां हरि मंदिर, दुर्गा मंदिर व गोविंदा मंदिर को निशाना बनाया। रूपसा उप जिले के पूजा उद्यापन परिषद के महासचिव ने बताया कि कट्टरपंथियों ने दस प्रतिमाओं को तोड़ दिया। रूपसा थाने के पुलिस अधिकारी सरदार मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। घटना के संबंध में 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के संबंध में पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष शक्तिपाद बसु ने 25 नामजद सहित सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रूपशा की मुख्य प्रशानिक अधिकारी रुबैया तसनीम ने कहा कि मंदिरों की मरम्मत की जाएगी और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

पाकिस्तान में आठ वर्षीय हिंदू लड़के पर ईशनिंदा का आरोप पेज>>11

तिरंगा रैली में शामिल रहे सरपंच-पंच दंपती की आतंकियों ने की हत्या

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- अनंतनाग में किसी मामले पर चर्चा के बहाने घर में घुसकर गोलियों से भूना
- भाजपा किसान मोर्चा के कुलगाम जिला प्रधान थे गुलाम रसूल डार
- आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित

कुलगाम जिले के भाजपा किसान मोर्चा के प्रमुख व सरपंच गुलाम रसूल डार की फाइल फोटो। श्रोत : स्वजन

कश्मीर में शांति, विकास व सामान्य होते हालात से बौखलाए आतंकियों ने फिर कायराना हरकत की है। अनुच्छेद-370 हटने के दो साल पूरे होने के उत्सव पर निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल रहे भाजपा किसान मोर्चा के कुलगाम जिले के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा बानो की सोमवार को आतंकियों ने अनंतनाग में घर गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल सरपंच थे और उनकी पत्नी पंच। हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। कश्मीर के आइजीपी विजय कुमार ने कहा कि दंपती की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है।

गुलाम रसूल और उनकी पत्नी जवाहिरा मूलतः कुलगाम के रहने वाले थे। पति-पत्नी ने वर्ष 2018 में हुए पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था। उसमें गुलाम रसूल सरपंच व जवाहिरा पंच चुनी गई थीं। दोनों ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी गुलाम रसूल ने बीते साल जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन हार गए थे।

जानकारी के अनुसार, हत्या दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे हुई। उस समय गुलाम रसूल और जवाहिरा घर में थे। उन्हें बतौर अंगरक्षक प्रदान किया गया पुलिसकर्मी उस समय कथित तौर पर वहां मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि दो से तीन आतंकवादी किसी मामले पर चर्चा के लिए उनके घर में दाखिल हुए। जवाहिरा बानो उनके लिए पानी लेने गईं तभी उन्होंने गुलाम रसूल डार को गोली मार दी। जवाहिरा भाग कर वापस आई तो आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी मोटरसाइकिल पर आए थे। गोलियों की आवाज सुनकर आस-पास मौजूद लोग और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

सुरक्षित आवासीय सुविधा छोड़कर कहीं और रहने लगे थे दोनों पेज>>5

खतरे के मुहाने पर धरती

जलवायु परिवर्तन पर यूएन की रिपोर्ट में सामने आई चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर, दुनियाभर के 234 विज्ञानियों ने तैयार की 3,000 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट, बढ़ रहा है समुद्र का स्तर, दुनियाभर में सूखा, बाढ़ और तूफान का खतरा बढ़ेगा

संभलिए, मानवता के लिए कोड रेड अलर्ट

जेनेवा, एपी : 'वातावरण लगातार गर्म हो रहा है। तय है कि हालात और खराब होने वाले हैं। भागने या छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी।' यह किसी साइंस फिक्शन वाली फिल्म की पटकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की तरफ से जलवायु परिवर्तन को लेकर सोमवार को जारी रिपोर्ट का निष्कर्ष है। यूएन ने इसे मानवता के लिए कोड रेड अलर्ट का नाम दिया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि यह जलवायु परिवर्तन मनुष्य की गतिविधियों का नतीजा है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) के तहत दुनियाभर के 234 विज्ञानियों ने 3,000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 2013 में आई पिछली रिपोर्ट के मुकाबले तथ्यों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से रखा गया है। विभिन्न सरकारें कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में कैसा कदम उठाएंगी, इसे आधार बनाते हुए रिपोर्ट में पांच संभावित परिस्थितियों का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में सुकून देने वाली बात यही है कि सबसे बुरी अनुमानित स्थिति को लेकर विज्ञानी मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा।

2015 में पेरिस जलवायु समझौते में विभिन्न सरकारों ने 19वीं सदी के आखिर की तुलना में धरती के औसत तापमान में वृद्धि को अधिकतम 1.5 डिग्री तक रोकने पर सहमति जताई थी। फिलहाल तापमान करीब 1.1 फीसद बढ़ चुका है। जल्द ही दुनिया इस लक्ष्य से ज्यादा गर्म हो जाएगी। रिपोर्ट में जितने भी अनुमान लगाए गए हैं, उन सबमें यह तय है कि तापमान में वृद्धि अगले दशक तक 1.5 डिग्री के लक्ष्य से आगे निकल जाएगी।

रिपोर्ट की सह-अध्यक्ष और फ्रांस की जलवायु विज्ञानी वैलेरी मैसन-डेल्मोट ने कहा,रिपोर्ट दिखाती है कि हमें अगले कुछ दशक में ज्यादा गर्म जलवायु के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोककर हम कुछ बहुत बुरी तस्वीरों को बदल सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान में वृद्धि के लिए कार्बन डाई आक्साइड व मीथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन जिम्मेदार है। इनके उत्सर्जन के प्राकृतिक माध्यम औसत तापमान में 10वें या 20वें हिस्से जितनी वृद्धि का कारण बन सकते थे। मौजूदा स्थिति के लिए इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। अनौपचारिक तौर पर 100 से ज्यादा देशों ने इंसानी गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाई आक्साइड को शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है।

कुछ खतरे, जो टल नहीं सकते

- अगले दशक में औसत तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर लेगी। यह पिछले अनुमानों से काफी पहले ही होने जा रहा है।
- बढ़ा हुआ तापमान कई बदलाव ला चुका है। बर्फ की चादरों का पिघलना सैकड़ों साल तक चलेगा। इससे समुद्र का स्तर बढ़ना तय है।
- यदि औसत तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक रोक लिया गया, तब भी समुद्र का स्तर वर्ष 2300 तक दो से तीन मीटर बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने का क्रम नहीं रुका तो स्तर सात मीटर तक बढ़ सकता है।

सबसे बुरा क्या? : रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो इस सदी के आखिर तक औसत तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन से सालभर ठंडे रहने वाले ग्रीनलैंड में भी हिमखंड पिघलकर समुद्र में तैरने लगे हैं। एएफपी

जलवायु परिवर्तन की तस्वीरें डरा रही हैं पेज>>14

सरकार ने कहा, एनएसओ के साथ कोई लेन-देन नहीं किया

- पेगासस जासूसी कांड में रक्षा राज्यमंत्री ने दिया राज्यसभा में बयान
- जासूसी के आरोपों के बाद देश में जारी है सियासी घमासान

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा, उसने सैन्य स्तर के जासूसी साफ्टवेयर पेगासस के निर्माता एनएसओ समूह के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है। स्पाइवेयर के जरिये जासूसी कराए जाने के आरोपों के बाद पेगासस को लेकर देश में जबर्दस्त सियासी बहस छिड़ी हुई है।

राज्यसभा में माकपा सदस्य वी सिवदासन के प्रश्न के जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ समूह संग कोई लेन-देन नहीं किया है। रक्षा मंत्रालय के खर्च को लेकर भी सिवदासन ने कई सवाल पूछे। ज्ञात हो, इजरायली साफ्टवेयर कंपनी एनएसओ ने पेगासस स्पाइवेयर विकसित किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेगासस के जरिये भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, राजनीतिक नेताओं व अन्य के फोन टैप किए गए। हालांकि, एनएसओ ने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया है।

सरकार को घेर रहीं विपक्षी पार्टियां : देश में विपक्षी दल जासूसी विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही हैं। विपक्षी दल 19 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से दोनों सदनों में कार्यवाही को बाधित कर रही हैं। विपक्ष संसद में पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है।

वैष्णव कर चुके हैं रिपोर्टों को खारिज : सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस के जरिये भारतीयों की जासूसी कराए जाने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर चुके हैं। लोस में उन्होंने कहा था कि मानसून सत्र से ठीक पहले इस तरह का आरोप लगाना भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब करने का प्रयास है।

39 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं सोमवार को दिल्ली में। संक्रमण दर 0.10 फीसद से घटकर 0.08 फीसद हो गई है। पिछले 24 घंटे में 76 मरीज ठीक हुए हैं व एक मरीज की मौत हुई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 10 अगस्त, 2021

न्यूज गैलरी

आफलाइन माध्यम से छात्र 10वीं व 12वीं में ले सकते हैं दाखिला

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं -12वीं में नान प्लान दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के मुताबिक जो छात्र आनलाइन माध्यम से दाखिले के लिए पंजीकरण नहीं कर सके, वे आफलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। निदेशालय के मुताबिक दाखिले के लिए छात्र 21 अगस्त तक अपने निकट के स्कूल से पंजीकरण फार्म ले सकते हैं। छात्रों को सभी संबंधित दस्तावेज भरकर स्कूलों में पंजीकरण फार्म जमा करना होगा। वहीं, छात्रों के दस्तावेजों की जांच के बाद 26 अगस्त को निदेशालय द्वारा आफलाइन माध्यम से पंजीकरण करने वाले छात्रों को आवंटित स्कूलों की सूची जारी की जाएगी। प्रधानाचार्य को छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर 31 अगस्त तक स्कूलों में दाखिला देना होगा। (जासं)

डीयू में तीसरे व चौथे सेमेस्टर का अकामिक कैलेंडर जारी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार को स्नातक व स्नातकोत्तर के तीसरे और चौथे सेमेस्टर का अकामिक कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के मुताबिक तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। साथ ही आठ से 12 दिसंबर तक प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। वहीं, लिखित परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। इसके बाद 29 दिसंबर से दो जनवरी 2022 तक सेमेस्टर ब्रेक रहेगा। चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं तीन जनवरी 2022 से शुरू होंगी, जबकि 17 मार्च से 20 मार्च तक छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद 21 मार्च से 27 अप्रैल तक फिर कक्षाएं चलेंगी। 28 अप्रैल से आठ मई तक प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। नौ मई से लिखित परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके बाद 24 मई से 19 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। (जासं)

मेडिकल कालेज में दाखिले के नाम पर डाक्टर से ठगी

नई दिल्ली : मेडिकल कालेज में दाखिले के नाम पर एक डाक्टर ने दूसरे डाक्टर के साथ ठगी कर डाली। जिस डाक्टर के साथ ठगी की गई, उसे आरोपित ने भरोसा दिया था कि वह उनके बेटे का दाखिला मेडिकल कालेज में करा देगा। आरोपित नवीन कुमार बंगाल के कोलकाता स्थित साल्ट लेक का रहने वाला है। दिल्ली के पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 2015 शिकायतकर्ता के पास एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया जिसमें मेडिकल के पीजी कोर्स में दाखिले की बात कही गई थी। जब इस नंबर पर शिकायतकर्ता ने संपर्क किया तो मालूम हुआ कि यह नंबर डा. नवीन कुमार का है। नवीन ने खुद को स्वास्थ्य मंत्रालय का पूर्व अधिकारी बताया और कहा कि वह प्रबंधन कोटे की सीट में दाखिला करा सकता है। तय हुआ कि दाखिले के एवज में डेढ़ करोड़ रुपये देने होंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने नवीन को बतौर एडवांस 24 लाख रुपये दे दिए। (जासं)

दो पालियों में आपरेशन थियेटर चलाएगा एम्स

राहत ▸ सर्जरी की वेटिंग होगी कम, अधिक मरीजों का होगा इलाज

विशेषज्ञ व निगरानी कमेटी की सिफारिश पर अमल के लिए फैकल्टी सेल ने जारी किया निर्देश

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

एम्स प्रशासन ने अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार के लिए पहल की है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी व निगरानी कमेटी ने दो पालियों में आपरेशन थियेटर चलाने की सिफारिश की है। इससे वेटिंग कम होगी और अधिक मरीजों का इलाज हो सकेगा। एम्स फैकल्टी सेल ने इसे लागू करने के लिए छह अगस्त को संस्थान के सभी सेंटरों के प्रमुखों व चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया है।

दरअसल, एम्स में सर्जरी के लिए तीन महीनों से लेकर छह साल तक की वेटिंग होती है। खास तौर पर दिल व न्यूरो की बीमारियों की सर्जरी के लिए वेटिंग सबसे ज्यादा है। दिल की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी सर्जरी के लिए पांच से छह साल की वेटिंग होती है। कैंसर की सर्जरी के लिए भी मरीजों को तीन से छह माह बाद के लिए समय दिया जाता है। कोरोना के दौर में लंबे समय तक रूटीन सर्जरी प्रभावित रही हैं। ऐसे में मरीजों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना के दौर में एम्स में आत्महत्या की तीन घटनाएं सामने आई थीं। इनमें दो मरीज थे और एक मेडिकल का छात्र था। इन घटनाओं के बाद एम्स की व्यवस्था पर सवाल उठे थे। इस वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के कामकाज व इलाज की व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने एम्स को मरीजों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए।

500 रुपये तक की जांच नि:शुल्क करने की सिफारिश

निगरानी कमेटी ने एम्स में 500 रुपये तक की जांच शुल्क को नि:शुल्क करने की सिफारिश की है। यह मामला पिछले कई सालों से लंबित है। निगरानी कमेटी ने कहा है कि एम्स प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इसे स्वीकृति दिलाने का प्रयास करें। 500 रुपये तक की जांच नि:शुल्क होने से मरीजों का समय बचेगा। उन्हें बार-बार काउंटर पर कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ाकर किया जा सकता है।

जागरण आकाईव

बेहतर इलाज के लिए तय होगी जिम्मेदारी

कमेटी ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। इसके तहत ओपीडी, सभी वार्ड, इमरजेंसी, सभी सेंटर व जांच सुविधा केंद्र के फैकल्टी प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। मरीजों को इलाज में ज्यादा परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना फैकल्टी प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। इस क्रम में कमेटी की ओर से आपरेशन थियेटर को दो पालियों में लंबे समय तक चलाने की बात कही गई है। ताकि सर्जरी की वेटिंग का समय कम हो सके। मौजूदा समय में सुबह करीब 8:30 बजे से शाम पांच बजे तक रूटीन सर्जरी होती है। एम्स में पहले भी दो पालियों में आपरेशन थियेटर चलाने की कोशिश हुई थी पर लागू नहीं हुआ। इस बार अमल होता है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा।

गोल्डन आवर में इलाज के लिए अब जागा संस्थान

राज्य ब्यूरो नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स के डाक्टर बताते रहे हैं कि हार्ट अटैक होने पर गोल्डन आवर में इलाज महत्वपूर्ण होता है। कुछ यही स्थिति स्ट्रोक के इलाज में भी है। लेकिन हार्ट अटैक व स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इमरजेंसी में जल्द इलाज के लिए एम्स खुद कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगा सकते हैं कि इमरजेंसी में कार्डियोलाजी व न्यूरोलाजी के डाक्टर मौजूद नहीं होते। दिल व न्यूरो के गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज के लिए एम्स अब जागा है। लिहाजा, संस्थान ने इमरजेंसी में कार्डियोलोजी व न्यूरोलाजी के रेजिडेंट डाक्टर नियुक्त करने की जरूरत महसूस की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर संस्थान के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में गठित विशेषज्ञ कमेटी ने दिल व न्यूरो के गंभीर मरीजों को जल्द इलाज उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी में 24 घंटे कार्डियोलाजी व न्यूरोलाजी के वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टर व रेजिडेंट डाक्टरों के उपलब्ध रहने की सिफारिश की है।

इसके बाद कार्डियोलाजी व न्यूरोलाजी विभाग के विभागाध्यक्षों से इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त रेजिडेंट डाक्टर नियुक्त करने की बात कही गई है। एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान के इमरजेंसी विभाग में नियुक्त डाक्टर हार्ट अटैक व स्ट्रोक के शुरुआती इलाज के लिए प्रशिक्षित होते हैं। फोन करके तुरंत कार्डियोलाजी व न्यूरोलाजी के रेजिडेंट डाक्टर बुला लिए जाते हैं। कमेटी की सिफारिश आगे किस तरह लागू होगी, यह बाद में स्पष्ट होगा। उल्लेखनीय है कि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शुरुआती एक घंटा को गोल्डन आवर माना जाता है। इसी तरह स्ट्रोक के इलाज के लिए शुरुआती तीन घंटे का समय महत्वपूर्ण मना जाता है। एम्स के एक डाक्टर ने कहा कि एक तो मरीज को अस्पताल पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है। मरीज के इमरजेंसी में पहुंचने पर काल करके विशेषज्ञ रेजिडेंट डाक्टर को बुलाने पर डाक्टर के पहुंचने में भी कुछ समय बर्बाद होता है।

शराब की होम डिलीवरी के आदेश को प्रवेश वर्मा ने दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नई आबकारी नीति-2021 के तहत शराब की होम डिलीवरी करने के दिल्ली सरकार के आदेश को भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। वहीं, अदालत ने नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवास के माध्यम से याचिका दायर कर सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली टीकाकरण और दवाओं की कमी से जूझ रही है। कोरोना महामारी के कारण हुए लाकडाउन के बीच घरेलू हिंसा की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। शराब की होम डिलीवरी से घरेलू हिंसा में और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखना राज्य का कर्तव्य है। शराब की होम डिलीवरी करके दिल्ली सरकार संविधान के अनुच्छेद-47 का उल्लंघन कर रही है।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि कोरोना महामारी के बीच नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये कमाए हैं।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत में सर्वश्रेष्ठ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइपी) को भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के अनुसार आइजीआइ को लगातार तीसरे वर्ष यह पुरस्कार मिला है। स्काइट्रैक्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की सूची में आइजीआइ के अलावा भारत से हैदारबाद एयरपोर्ट को भी जगह दी गई है। स्काइट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्डस विमानन उद्योग के क्षेत्र में बड़े पुरस्कार में शुमार किया जाता है।

डायल के अनुसार आइजीआइपी को कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकाल का पालन करने के लिए कोविड- 19 एयरपोर्ट एक्सिलेंस अवार्ड भी मिला है। इस श्रेणी में भारत से केवल आइजीआइपी को ही पुरस्कार मिला है। डायल के मुताबिक आइजीआइपी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट रैंकिंग में भी सुधार किया है। 2020 में जहां इस रैंकिंग में आइजीआइपी का स्थान 50वां था वहीं 2021 में बेहतर स्थान प्राप्त करते हुए 45वें स्थान पर जगह बना ली है। डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि आइजीआइ एयरपोर्ट की रैंकिंग में सुधार व अन्य पुरस्कार के लिए एयरपोर्ट के सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। यह एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी, साझीदार व अन्य लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम है।

यात्रियों की संख्या बढ़ी, जल्द खुल सकता है टर्मिनल-1

जासं, नई दिल्ली: कोरोना के मामले कम होने के बाद 22 जुलाई को शुरू किए गए टर्मिनल-2 से विमानों की आवाजाही एयरपोर्ट पर बढ़ी है। इसका असर यात्रियों की संख्या में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल रहा है। दो सप्ताह पहले करीब 42 हजार यात्रियों की आवाजाही एयरपोर्ट पर प्रतिदिन हो रही थी। अब यह तादाद बढ़कर 85 हजार तक पहुंच चुकी है। डायल के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए टर्मिनल-1 को जल्द ही खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। संभावना है कि सवा लाख यात्रियों का आंकड़ा पहुंचते ही टर्मिनल-1 को खोलना पड़ सकता है।

गुमनाम नायकों की कहानी कहेगा 'देशभक्ति पाठ्यक्रम'

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली

आजादी के गुमनाम नायकों की कहानी और संवैधानिक मूल्य अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए उसे छात्रों के जीवन में भी उतारने की तैयारी कर ली है। दरअसल, राजधानी के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस सत्र से ही देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 15 अगस्त को इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। देशभक्ति पाठ्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक पाठ्यक्रम को फिलहाल नर्सरी से आठवीं तक के छात्रों के लिए ही तैयार किया जाएगा। इसमें छात्रों को आत्मबोध से समानता और भाईचारे जैसे संवैधानिक व सामाजिक मूल्यों को जीने के लिए कौशल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, पाठ्यक्रम में परिवार, स्कूल, समुदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में समझ विकसित करने के पांच प्रमुख विषय भी शामिल किए जाएंगे।

गतिविधि आधारित होगा पाठ्यक्रम : शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम केवल गतिविधि आधारित ही होगा। वहीं, पाठ्यक्रम सरल भाषा में छात्रों में उन मूल्यों और विचारों को स्थापित करेगा जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनाने में सहायक हों।

छात्र करेंगे आत्म-मूल्यांकन : पाठ्यक्रम को तीन भागों में बांटा जाएगा। इसमें नर्सरी से दूसरी, तीसरी से पांचवीं और छठीं से आठवीं तक के लिए छात्रों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें सामूहिक कार्य, मन मानचित्रण, भूमिका निभाना और व्याख्या जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। वहीं, छात्रों को गृह कार्य के तौर पर पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों से विभिन्न विषयों पर विचार प्राप्त करने को कहा जाएगा। इस पाठ्यक्रम की कोई परीक्षा नहीं होगी। छात्रों को आत्म-मूल्यांकन करना होगा।

शिक्षकों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा : छात्रों को ये पाठ्यक्रम बेहतर समझ आए, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक भी सच्चे देशभक्त हों और उनमें भी राष्ट्रनिर्माण की भावना हो। इसलिए पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इसमें शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि छात्रों को किन-किन माध्यमों से पाठ्यक्रम को सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।

मनीष सिसोदिया ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के जश्न का किया शुभारंभ

आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोलते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ रन फार दिल्ली @ 75 दौड़ कार्यक्रम से हुआ। तीन किमी की यह दौड़ दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक आयोजित थी। इसमें दिल्ली सचिवालय के 200 कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें 10-15 व्यक्तियों के समूह में बांटा गया था। सिसोदिया ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए इसमें भाग भी लिया।

इससे पहले प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यह दिखाना है कि भले ही भारत 75 वर्ष का हो रहा है, लेकिन लोगों के दिल और आत्मा युवा है। देश की आजादी के 75वें साल में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेलिब्रेट्स फ्रीडम 75' के तहत एक कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य दिल्ली को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर आजादी के रंगों से रंगना है।

राहुल का ट्विटर अकाउंट ब्लाक करने के विरोध में युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भारतीय युवक कांग्रेस ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लाक करने के खिलाफ ट्विटर इंडिया के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लाडो सराय स्थित ट्विटर कार्यालय पर एकत्र हुए। इस दौरान पुलिस बलों ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।

इस दौरान श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने की बजाय, हमदर्दी व न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार ट्विटर को डरा कर, राहुल गांधी का अकाउंट बंद करा कर भी बेटी से न्याय की आवाज़ नही दबा पाएंगे।

युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है और सत्ता की हर ओछी हरकत के बावजूद वो लड़ते रहेंगे। भाजपा ट्विटर को डरा कर अकाउंट ब्लाक करा सकती है, लेकिन जो करोड़ों लोग ट्विटर पर बोल रहे हैं, उनको कैसे रोकेगी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हेमंत ओघले, दीपक चोटीवाला, मंजू तोंगड़ आदि मौजूद रहे।

लाडो सराय स्थित ट्विटर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर ले जाते पुलिसकर्मी। विपिन शर्मा

परिवहन विभाग की सभी सेवाएं कल से पूरी तरह हो जाएंगी आनलाइन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : परिवहन विभाग की सभी सेवाएं कल से पूरी तरह से आनलाइन सिस्टम के दायरे में आ जाएंगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये परिवहन विभाग की सेवाओं को पूरी तरह आनलाइन करने की तैयारियों को लेकर सभी एमएलओ के साथ बैठक की।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवहन विभाग की आनलाइन सेवाओं को जनता को समर्पित करेंगे। आनलाइन सेवाओं के शुरू होने से अब किसी भी जोनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी में जाकर किसी तरह के दस्तावेज को जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग घर बैठे ही किसी भी समय आनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। टेस्ट पास करने के बाद उसको आनलाइन लाइसेंस भी मिल जाएगा। केवल स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक बार अथारिटी टेस्ट देने के लिए जाना होगा।

भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक नारे लगाने पर दर्ज हुआ मामला

- आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर कनाट प्लेस थाना पुलिस ने की कार्रवाई
- पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर हुआ था कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर रविवार को जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने व आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में कनाट प्लेस थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदर्शन के बाद इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं का कहना था कि 1860 में बने इंडियन पैनल कोड, 1861 में बने पुलिस एक्ट, 1863 में बने रिलिजियस एंडोनमेंट एक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया जाए। इसके साथ ही भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू की जाए।

उनका कहना था कि जब तक घटिया कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी, उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण खत्म नहीं होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डाक्टर आनंद कुमार, वरिष्ठ नौकरशाह आरवीएस मणि, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई प्रीत सिंह और अनिल चौधरी, कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ और महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान मंच पर उपस्थित थे।

अश्विनी उपाध्याय बोले- मुझे किया जा रहा बदनाम

उक्त मामले में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को पत्र लिखकर बताया है कि वह रविवार पूर्वाह्न 11 बजे मंच पर पहुंचे थे। भीड़ बढ़ने के कारण 12 बजे कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। उसके बाद वह वहां से चले गए थे। इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो में एक व्यक्ति आपत्तिजनक भाषण दे रहा है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए उनका नाम लेकर उक्त वीडियो ट्विटर, फेसबुक और वाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं, जबकि वीडियो में दिख रहे लोगों को न तो वह जानते हैं और न उनसे मिले हैं।

सुविधा

डीटीटीडीसी तैयार कर रहा पोर्टल, इससे जुड़ेंगे सभी संबंधित विभाग, फिल्म निर्माताओं को इधर-उधर भटकने से मिलेगी निजात, पोर्टल पर ही मिल जाएगी शूटिंग की अनुमति

एकल खिड़की से होकर गुजरेगी फिल्मों की शूटिंग की राह

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं को किसी भी तरह की अनुमति लेने के लिए आने वाले दिनों में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लैपटाप पर माउस के महज एक क्लिक से आवेदन भी हो जाएगा और तय समय सीमा में अनुमति भी मिल जाएगी। यही नहीं, शूटिंग को लेकर कोई और समस्या होगी तो उसका समाधान भी कर दिया जाएगा।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजधानी में फिल्म शूटिंग के लिए निर्माताओं की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार फिल्म पालिसी बना रही है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को इस दिशा में नोडल एजेंसी बनाया गया है। पहले चरण में डीटीटीडीसी एक सिंगल विंडो (एकल खिड़की) पोर्टल तैयार करेगा, जिससे दिल्ली के सभी प्रमुख संबंधित विभाग जुड़े रहेंगे।

डीटीटीडीसी की ओर से डीडीए, दिल्ली मेट्रो, एमसीडी, एएसआइ, एनडीएमसी, उत्तर रेलवे, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एनएचएआइ इत्यादि हर प्रमुख सरकारी विभाग व एजेंसी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में शूटिंग के लिहाज से उनसे उनकी प्रमुख लोकेशनों और वहां के शुल्क की जानकारी मांगी गई है। इन विभागों से प्राप्त जानकारी को पोर्टल पर डाला जाएगा। इन सभी विभागों के साथ ही दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट अथारिटी व अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द तैयार और शुरू करने की कोशिश चल रही है। इसके शुरू होने पर फिल्म निर्माताओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग सरकारी दफ्तरों में भटकना भी नहीं पड़ेगा। सारी औपचारिकताएं आनलाइन ही पूरी हो जाएंगी। खास बात यह है कि हर आवेदन के निस्तारण का निर्धारित समय होगा और बाकायदा उच्च स्तरीय निगरानी भी होगी। अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली पर्यटन के पास अभी भी भारतीय और विदेशी फिल्मकारों की ओर से शूटिंग के लिए काफी प्रस्ताव आते रहते हैं। बहुत से फिल्म निर्माता तो यहां की लालफीताशाही से दुखी होकर किसी अन्य राज्य का रुख भी कर लेते हैं।

शूट की गईं कुछ सुपरहिट फिल्में	
1. चांदनी	2. थ्री इडियट
3. पीके	4. दिल्ली-6
5. चक दे इंडिया	6. फना
7. विकी डोनर	

कुछ पसंदीदा लोकेशन	
1. कनाट प्लेस	2. हुमायूं का मकबरा
3. पुरानी दिल्ली	4. पुराना किला
5. दिल्ली मेट्रो	6. इंडिया गेट
7. राजपथ	

यह भी जानें
1. दिल्ली में करीब दो सौ पर्यटन स्थल हैं।
2. शूटिंग के लिए किसी फिल्म निर्माता को करीब 17 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है।
3. हर साल यहां करीब 30 से 35 फिल्मों की शूटिंग होती है।

अब एप पर मिलेगी दिल्ली के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अब दिल्ली के पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार एक मोबाइल एप विकसित कर रही है। इस एप पर सभी पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी होगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पूर्व उन्होंने सोमवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें एप को विकसित करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन भी उपस्थित थे।

पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोबाइल एप में दिल्ली के पर्यटन स्थलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा उसका एक संक्षिप्त इतिहास भी उपलब्ध होगा। साथ ही टिकटिंग प्रणाली के बारे में भी जानकारी रहेगी।

93.31 करोड़ की ठगी के मामले में कंपनी निदेशक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 93.31 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोलकाता स्थित एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। आरोपित कोलकाता के गरियाहाट कुमुदिनी आपार्टमेंट निवासी मुर्गेश देवाश राय ने अपनी कंपनी के माध्यम से दर्जनों लोगों के शेयर हड़प कर एक बैंक में गिरवी रख करोड़ों के क्रेडिट की सुविधा हासिल की थी। आरोपित की कंपनी शेयर बाजार में लोगों के पैसे निवेश करने का काम करती है।

आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि दिल्ली निवासी राधिका पुरी ने शिकायत दी थी कि कोलकाता स्थित बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स कंपनी शेयर ट्रेडिंग का काम करती है। कंपनी के निदेशकों ने पीड़ितों के शेयर और उनके खातों की राशि को गिरवी रखकर करीब 3.5 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं।

सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को थोड़ा थामेगा ओबीसी विधेयक

सियासत ▸ लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश, आज हो सकता है पारित

मामले की संवेदनशीलता देख 15 विपक्षी दल बिल पास कराने को राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी मामले समेत तमाम मुद्दों पर संसद में चल रहे संग्राम के बीच विपक्षी दलों ने राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने संबंधी सोमवार को लोकसभा में पेश हुए संविधान संशोधन विधेयक का एक सुर से समर्थन करने की घोषणा की है।

ओबीसी सूची से जुड़े मामले की सियासी संवेदनशीलता को देखते हुए विपक्षी दलों ने मानसून सत्र की शुरुआत से संसद में चले आ रहे संग्राम में पहली बार इस विधेयक के लिए अपनी जंग को विराम देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की अगुआई में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की सोमवार सुबह हुई बैठक में ओबीसी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार का साथ देने पर सहमति बनी।

साथ ही विपक्षी दलों ने यह भी साफ कर दिया कि ओबीसी विधेयक का समर्थन करने के अपवाद के अलावा पेगासस, कृषि कानूनों और महंगाई के खिलाफ संसद में सरकार की आक्रामक घेरेबंदी की उसकी रणनीति नहीं बदलेगी। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भारी हंगामा जारी रखते हुए विपक्ष ने अपनी इस रणनीति को जाहिर भी कर दिया।

नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। एएनआइ

लोकसभा में विपक्ष के शोर-शराबे के बीच सरकार ने एक के बाद एक थोड़े समय में ही तीन विधेयक पारित करा लिए तो तीन नए विधेयकों को पेश भी किया गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने हंगामे के बीच आनन-फानन में विधेयकों को पारित कराने पर गंभीर एतराज जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार सदन में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हालांकि, विपक्षी दलों के हमलों और विरोध के बावजूद सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते को देखते हुए अपने विधायी कामकाज को पूरा करने की रफ्तार तेज कर दी है।

विपक्षी दलों को आशंका थी कि ओबीसी सूची से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान हंगामा जारी रहता तो सरकार और भाजपा इसे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी के लिए अहम है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं की सोमवार सुबह संयुक्त बैठक हुई तो इसमें एक मत से हंगामे को विराम देकर विधेयक का समर्थन करने का फैसला हुआ। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, राजद, सपा, माकपा, भाकपा, आप, एनसीपी आदि दलों के नेता शामिल थे।

राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने बैठक के बाद विपक्षी नेताओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी दल ओबीसी सूची में संशोधन के लिए जो बिल लेकर आई है हम उसका समर्थन करेंगे। इस संविधान संशोधन बिल पर चर्चा में भी विपक्ष हिस्सा लेगा। पेगासस जासूसी मामले के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा कि बाकी के मुद्दे अपनी जगह हैं, पर यह मसला बैकवर्ड क्लास और देश के हित में है। इसीलिए ओबीसी और गरीबों के हित में जो कानून आएगा, हम उसे एक होकर पास करेंगे।

कुछ कहने से नहीं, कुछ करके दिखाना होता है अहम : प्रधान

जाब्यू, नई दिल्ली : बताने की जरूरत नहीं कि ओबीसी विधेयक जब सदन में चर्चा के लिए पेश होगा तो किस तरह हर दल खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि विपक्ष ने भी इसके समर्थन की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन उससे पहले सोमवार को लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्याल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि मोदी सरकार का आरक्षण को लेकर रुख बिल्कुल साफ है। जिस वर्ग को संविधान के तहत आरक्षण दिया गया है, उसे वह 100 फीसद लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ कहने से नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाने से होता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।

उत्तर प्रदेश विस चुनाव से पहले रोहणी आयोग दे सकता है रिपोर्ट

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों के फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की पिछड़ी जातियों को केंद्र से उप-वर्गीकरण का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसमें ओबीसी को मिलने वाले 27 फीसद आरक्षण में उनकी भी हिस्सेदारी निर्धारित हो जाएगी। अभी वे ओबीसी की श्रेणी में हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का उनकी जातियों के बीच वर्गीकरण के काम में जुटे रोहणी आयोग ने फिलहाल इससे जुड़े सारे आंकड़े जुटा लिए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

वैसे भी रोहणी आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2021 तक ही है। ऐसे में आयोग की भी कोशिश है कि तय समय में इस काम को पूरा कर लिया जाए। आयोग को पहले भी कई विस्तार मिल चुका है। ऐसे में अब सही समय को देख सरकार ने भी इसकी अंतिम रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि इससे पहले आयोग ने ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर चुके राज्यों के साथ भी चर्चा की योजना बनाई थी। इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अड़ंगा लग गया, जिसमें अदालत ने ओबीसी पर राज्यों की सूची को अवैध बता दिया था। इस बीच सरकार संविधान संशोधन के जरिये राज्यों के ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के अधिकार को फिर से बहाल करने में जुटी है।

आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि राज्यों का अधिकार बहाल होते ही ओबीसी जातियों का पहले ही वर्गीकरण कर चुके 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं। इसके पूर्व आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले और सरकारी नौकरियों में ओबीसी की सभी जातियों का ब्योरा जुटा लिया है। इसमें यह पाया गया है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ अब तक इनकी सिर्फ एक हजार जातियों को ही मिला है, जबकि केंद्रीय सूची के तहत ही ओबीसी की कुल जातियों की संख्या करीब 27 सौ है। इनमें भी सौ जातियों ने इसका सबसे ज्यादा लाभ लिया है।

आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो वर्गीकरण का एक फार्मूला भी तैयार किया गया है, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें ओबीसी आरक्षण को चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है। इनमें उन जातियों को ओबीसी के 27 फीसद आरक्षण में ही एक कोटा तय किया गया है, जिससे अब उन्हें अनिवार्य रूप से इसका लाभ मिलेगा। आयोग का मानना है कि इस फार्मूले को अध्ययन व आंकड़ों के बाद वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब सबसे अहम हैं।

तैयारी

- ओबीसी की पहचान करने का राज्यों का अधिकार बहाल होते ही वर्गीकरण में फिर आएगी तेजी
- केंद्रीय सूची के आधार पर ओबीसी आरक्षण को चार श्रेणियों में बांटने की है आयोग की योजना

दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन में भिड़ंत

नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 'समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा : अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' पर उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की। एएनआइ

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को समुद्री सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिका और चीन भिड़ गए। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वह दक्षिण चीन सागर में गैरकानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाने वाली कार्रवाई देख रहा है। इस पर बीजिंग ने जवाब दिया कि अमेरिका को इस मुद्दे पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने का हक नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा पर उच्चस्तरीय वर्चुअल खुली बहस की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र के 15 देशों के इस उच्चस्तरीय निकाय की अध्यक्षता इस महीने भारत कर रहा है। समुद्री सुरक्षा को लेकर जो बैठक हुई वह तीन हस्ताक्षर कार्यक्रमों में से एक है। पीएम के बाद इस बैठक की अध्यक्षता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इस बैठक में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने अपने राष्ट्रीय बयान दिए।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समुद्री नियमों और सिद्धांतों को खतरे में देख रहे हैं। चीन पर इशारों में हमला करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में गैरकानूनी दावे को लेकर हमने समुद्र में जहाजों के बीच खतरनाक मुठभेड़ें और उत्तेजक कार्रवाइयां होते देखी हैं। उल्लेखनीय है दक्षिण चीन सागर के लगभग 13 लाख वर्ग मील इलाके को चीन अपना संप्रभु क्षेत्र होने का दावा करता है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मोदी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में दोनों के बीच हुई तीखी तकरार
- अमेरिका ने कहा, दक्षिण चीन सागर में गैरकानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए उकसाने वाली कार्रवाई हो रही

चीन इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य पर ठिकाने बना रहा है। हालांकि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। अमेरिका ने उन कार्रवाइयों पर अपनी चिंता जता दी है जिनसे चीन दूसरे देशों को उनके समुद्री संसाधनों का कानूनी रूप से लाभ उठाने से डराने-धमकाने का काम करता है। ब्लिंकन ने कहा कि हम, दक्षिण चीन सागर के अन्य दावेदारों सहित अन्य देश दक्षिण चीन सागर में इस तरह के व्यवहार और गैरकानूनी दावे का विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर विवाद से अमेरिका या किसी और ऐसे देश का लेना-देना नहीं है जो यहां के द्वीपों और जल क्षेत्र के दावेदार नहीं हैं। लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि सदस्य देश उन नियमों की रक्षा करें जिनका पालन करने के लिए हम सभी सहमत हैं और समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करें।

ब्लिंकन ने कहा दक्षिण चीन सागर या किसी भी महासागर में संघर्ष का सुरक्षा और व्यापार पर गंभीर वैश्विक असर होगा। इससे भी अधिक, जब किसी देश को नियमों की अनदेखी के लिए सजा नहीं मिलती तो वह हर जगह अस्थिरता पैदा करता है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर बैठक आयोजित करने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। अमेरिका की टिप्पणी के बाद चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि दाई बिंग ने कहा कि सुरक्षा परिषद, दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सही जगह नहीं है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे का उल्लेख किया है और चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चीन और आसियान देशों के संयुक्त प्रयासों से, दक्षिण चीन सागर में स्थिति आम तौर पर स्थिर बनी हुई है। सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता की छूट है। चीनी राजनयिक ने कहा कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दृढ़ और सक्षम है।

निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के योग्य नहीं है। अमेरिका बिना किसी बात के परेशानी पैदा कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में मनमाने ढंग से जंगी जहाजों और विमानों को भेजकर क्षेत्रीय देशों को मोर्चबंदी के लिए उकसा रहा है। यह देश अपने आप में दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।

पीएम मोदी आज महोबा से उज्ज्वला-2 का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

राब्यू, लखनऊ : गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बुंदेलखंड के महोबा (उप्र) से करेंगे। महोबा की पुलिस लाइन के परेड मैदान में बायोफ्यूल प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहीं पहुंचेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला-2 के 10 लाभार्थियों को आनलाइन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।

योजना के पहले चरण के विभिन्न राज्यों के पांच लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। पहले चरण में प्रदेश के गरीब परिवारों को कुल एक करोड़ 47 लाख 43 हजार 862 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। जो पात्र परिवार रह गए, उन्हें इस दूसरे चरण में लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में लगाए जा रहे कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की शुरुआत भी मंगलवार को की जाएगी।

बिजली वितरण में एकाधिकार बनाए रखना चाहती हैं ममता

- बिजली संशोधन बिल के विरोध पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की मंशा पर संदेह जताया। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि ममता बिजली वितरण में एकाधिकार की रक्षा क्यों करना चाहती हैं?

बताया जाता है कि पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने सरकार की योजना का विरोध किया था। उनका कहना था कि कुछ राज्यों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने नए संशोधनों को जनविरोधी बताया था। इस पत्र के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, 'ममता बनर्जी बिजली वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार की रक्षा क्यों करना चाहती हैं, खासतौर पर तब जबकि देश में कोलकाता में बिजली दरें सबसे ज्यादा हैं।' सिंह ने बताया कि इस विधेयक का मकसद बिजली वितरण के क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर इसे सरकारी और निजी क्षेत्र के एकाधिकार से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि वह बंगाल के साथ ही केरल सरकार को भी पत्र लिखकर विधेयक की खासियतों के बारे में बताएंगे।

विधेयक के कानून बन जाने से बिजली वितरण क्षेत्र लाइसेंस राज से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल कंपनियों की तरह ही बिजली कंपनियों को चुनने की आजादी मिल जाएगी। किसी कंपनी के सर्विस सही नहीं होने पर उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली कनेक्शन को भी पोर्ट करा सकेंगे। सिंह ने कहा कि लाइसेंस राज के खत्म होने से बिजली वितरण के क्षेत्र में निवेश भी आएगा। निवेश आने के बाद ही इस क्षेत्र में सुधार होगा। अगर निवेश नहीं आता है तो हमें अंधकार में रहना होगा।

ओबीसी विधेयक को लेकर शाह से मिले फड़नवीस

नयी दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ओबीसी से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मानसून सत्र में पारित कराए जाने का अनुरोध किया। इस विधेयक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने का प्रविधान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा.वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। सरकार मंगलवार को इस विधेयक को निचले सदन से पारित कराने का प्रयास करेगी। ज्यादातर दलों ने इस विधेयक के समर्थन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आग्रह (शाह से) किया कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित होना चाहिए। मैं उन सभी राजनीतिक दलों, जिन्होंने संसद में गतिरोध कायम किया है, से आग्रह करूंगा कि वह ओबीसी कल्याण के लिए इसका समर्थन करें और सर्वसम्मति से पारित करें।

जज हत्याकांड की जांच पर नजर रखेंगे झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज की कथित हत्या के मामले में सीबीआइ को हर सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है।

यह बात प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने धनबाद में जज उत्तम आनंद की आटो से टक्कर के बाद मौत के मामले में सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जजों की सुरक्षा के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस वीडियो में साफ नजर आया था कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को हर सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देना उचित होगा। इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच की निगरानी करें। पीठ ने कहा कि इस मामले के अलावा कोर्ट ने देश में जजों और वकीलों को धमकी देने, उन पर हमले और दबाव डाले जाने की घटनाओं पर संज्ञान लिया है और इसका हल निकालने पर सुनवाई शुरू की है।

जजों, वकीलों के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी : कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां न्यायिक अधिकारी स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें। पीठ ने कहा कि धनबाद की घटना के इस मामले को भी जजों की सुरक्षा के मुख्य मामले के साथ सुनवाई पर लगाया जाए। जजों की सुरक्षा के मामले में कोर्ट पहले ही केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर चुका है और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन राज्यों ने मामले में जवाब दाखिल नहीं किया है दाखिल कर दें।

सीबीआइ ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी : धनबाद के मामले में सीबीआइ की ओर से कोर्ट में सील बंद लिफाफे मे रिपोर्ट दाखिल की गई। कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इसमें अपराध के पीछे की मंशा और इरादे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कोर्ट ने सीबीआइ से कहा कि वह इस मामले में कुछ ठोस चाहते हैं। पीठ ने पूछा कि हाई कोर्ट में सुनवाई कब है। बताया गया कि हाई कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई है। इसके बाद पीठ ने सीबीआइ को हाई कोर्ट में प्रति सप्ताह स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की निगरानी करने को कहा।

- सुप्रीम कोर्ट ने किया आग्रह, सीबीआइ को मुख्य न्यायाधीश की पीठ में साप्ताहिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
- 28 जुलाई को धनबाद में सुबह के समय जागिंग करते समय जज उत्तम आनंद को आटो रिक्शा ने पीछ से मारी थी टक्कर

सीबीआइ करा रही आरोपितों का लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद को आटो से टक्कर मारने वाले लखन वर्मा और राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट धनबाद में ही कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए घटना की जांच कर रही सीबीआइ टीम ने बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर सोमवार को दोनों आरोपितों का चार टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। दोनों की जांच प्रक्रिया देर शाम तक जारी थी। सोमवार को अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही सीबीआइ टीम अदालत पहुंची और दोनों के ब्रेन मैपिंग की अनुमति मांगी। दोनों आरोपितों की सहमति पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में टेस्ट कराने की अनुमति दी।

कराए जा रहे ये टेस्ट : सीबीआइ ने कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपितों का लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति ली।

अहम मामला

जजों की रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

कहा, जजों की कम संख्या के चलते महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्रता से न्याय करना असंभव हो जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई साल तक नियुक्तियां नहीं करने के सरकार के 'अड़ियल रवैये' पर सोमवार को गहरी नाराजगी जताई। जजों के रिक्त स्थानों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्रता से न्याय करना असंभव हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि वाणिज्यिक विवादों पर जल्द-से-जल्द फैसला होना जरूरी है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में जज होने चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश राय की पीठ ने कहा कि इस साल 20 अप्रैल के अपने आदेश में शीर्ष अदालत द्वारा समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद न्यायिक संस्थान इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। पीठ ने कहा, हमने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के सामने यह बात रखी है कि सिफारिशों को कोलेजियम तक पहुंचने में महीनों और साल लगते हैं। उसके बाद महीनों और वर्षों के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि जहां उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से न्याय करना असंभव हो जाएगा। पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें एक याचिका और अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को डंपिंग रोधी जांच के बारे में अधिसूचना से संबंधित मामले में पक्षकारों से जवाब मांगा था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में एक सप्ताह के भीतर 50 फीसद से कम न्यायाधीश होंगे। इसमें 60 न्यायाधीशों में से केवल 29 न्यायाधीश होंगे। दो दशक पहले जब हम में से एक (जस्टिस संजय किशन कौल) को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तब वह न्यायालय के 32वें न्यायाधीश थे जबकि संख्या 33 जजों की थी।

- वाणिज्यिक विवादों पर जल्द फैसले के लिए पर्याप्त संख्या में जज होने चाहिए
- पीठ ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं

हाई कोर्ट में जजों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जागरण आर्काइव

पद्म सम्मान के लिए 15 सितंबर तक नामांकन

नई दिल्ली, एएनआइ : पद्म सम्मान (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) के लिए नामांकन या सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और यह सरकार के पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे। सम्मानों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म सम्मान के लिए नामांकन और सिफारिश केवल पद्म सम्मान पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है, 'सरकार पद्म सम्मान को लोक पद्म में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी नागरिकों से ऐसे प्रतिभावान लोगों की पहचान करने का आग्रह करती है जिनकी उपलब्धि वास्तव में इसकी हकदार है। महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बीच ऐसी प्रतिभाओं की पहचान की जाए।'

कह के रहेंगे

माधव जोशी

ओबीसी बिल

'जादुई छाता!'

16 अगस्त से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारी। उत्तराखंड में देवस्थानम अधिनियम समाप्त करने की मांग को लेकर चारों धाम व 47 मंदिरों के पुरोहित और हक-हकूकधारी दो वर्ष से आंदोलनरत हैं।

तेजप्रताप के तेवर बता रहे राजद में अभी नहीं हुआ है शक्ति संतुलन

अरविंद शर्मा, पटना

- लालू पहले ही कर चुके हैं अपनी तीनों संतानों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा
- तेजप्रताप की महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति से असहज हो जाते हैं तेजस्वी समर्थक

तेजप्रताप यादव

मीसा भारती।

तेजस्वी यादव। फाइल

लालू प्रसाद की पार्टी (राष्ट्रीय जनता दल) और परिवार फिर सुर्खियों में है। विधायक तेजप्रताप यादव के तेवर से साफ है कि सियासी उत्तराधिकार का जिन्न बोतल से बाहर निकलने के लिए अभी भी प्रयासरत है। कभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानबाजी तो कभी पोस्टर के रूप में सिर उठाते रहता है। हालांकि लालू ने राजनीति में सक्रिय अपनी तीन संतानों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा बहुत पहले ही कर दिया है। बड़े पुत्र तेजप्रताप को छात्र राजद की कमान देने और पुत्री डा. मीसा भारती को राज्यसभा भेजने के बाद छोटे पुत्र तेजस्वी यादव में संगठन और उम्मीदों की सारी शक्तियां निहित कर दी हैं। फिर भी असंतुष्ट खेमे में जब-तब महत्वाकांक्षा हावी होने लगती है। यह लालू-राबड़ी के पुत्र मोह से ताकत लेकर तेजस्वी के समर्थकों को असहज करती है। इतना कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुशासन का पाठ भी बेअसर हो जाता है।

छात्र राजद के कार्यक्रम को नजीर के तौर पर लिया जा सकता है। एक दिन पहले तक तेजप्रताप दिल्ली में बहन मीसा के घर रह रहे पिता लालू यादव के पास थे। रविवार को दिल्ली से पटना आए और जगदानंद सिंह पर गरजने-लगे। कहा जा रहा है कि तेजप्रताप को ऐसा प्रोत्साहन परिवार के ही किसी सदस्य से मिला होगा। इसके पहले भी कई मामलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तेजप्रताप अपने अंदाज में टिप्पणी कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लालू के करीबी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना उन्होंने एक लोटा पानी से कर दी थी। एक दूसरे वरिष्ठ नेता एवं राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को भी राजद की रीति-नीति समझा चुके हैं। तेजप्रताप की टिप्पणी से जगदानंद सिंह भी कई बार आहत हो चुके हैं। उन्हें तो अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करने पर भी मजबूर होना पड़ा था, किंतु लालू ने हस्तक्षेप करके जैसे-तैसे मामले को संभाला।

तेजप्रताप का दावा तेजस्वी के लिए और तिकड़म अपने लिए : हालांकि तेजप्रताप ने खुद को हमेशा श्रीकृष्ण की भूमिका में पेश किया है और भाई तेजस्वी को अर्जुन बताते आए हैं। दावा भी कि तेजस्वी के लिए महाभारत की लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है। उन्हें सीएम बनाना है, मगर जब भी मौका मिला, खुद को तेजस्वी के बड़े भाई व विरासत के प्रमुख दावेदार के रूप में अहसास कराने से भी नहीं चूके। यही कारण है कि एक गुट द्वारा वह हमेशा नजरअंदाज किए जाते रहे। अब तो पार्टी के बैनर-पोस्टरों से भी गायब हो चुके हैं। तेजप्रताप की ताजा गतिविधियों को वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

राजद में पोस्टर वार, तेजस्वी के बाद अब तेजप्रताप आउट

राजद में प्रभाव के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। शुरुआत तेजप्रताप यादव के समर्थकों की ओर से की गई। छात्र राजद के पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई। छात्र राजद के कार्यक्रम में रविवार को तेजप्रताप बेकाबू भी दिखे। तेजस्वी के समर्थक माने जाने वाले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताया। इसके कुछ घंटे बाद ही देर रात तेजप्रताप के पोस्टर पर लगी आकाश यादव की तस्वीर पर किसी ने कालिख पोत दी। सोमवार सुबह में दूसरे गुट की प्रतिक्रिया भी आई। राजद कार्यालय के बाहर तेजप्रताप के पोस्टर को फाड़कर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा दिया गया। राजद में इसका भावार्थ शक्ति प्रदर्शन के रूप में निकाला जा रहा है।

तमिलनाडु का हर परिवार 2.63 लाख रुपये का कर्जदार : रिपोर्ट

- राज्य के वित्त मंत्री ने जारी किया श्वेत पत्र

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने सोमवार को एक श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की तस्वीर साफ की है। इसमें कहा गया है कि अब पुराना रुख नहीं चलने वाला है, क्योंकि राजकोषीय मोर्चे पर कोई गुंजाइश नहीं बची है। आलम यह है कि आज प्रदेश में प्रति परिवार 2.63 लाख रुपये का सार्वजनिक कर्ज है।

त्याग राजन ने संवाददाताओं से कहा, 'हमारी पार्टी की सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति व प्रशासनिक कौशल से स्थितियां बदल देगी। श्वेत पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं।' राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक विपक्ष में रहते अन्नाद्रमुक सरकार की कुप्रबंधन के लिए आलोचना करती थी। उसने पारदर्शिता के लिए राजकोषीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की बात कही थी।

मई में सत्ता संभालने के बाद द्रमुक सरकार ने इस तरह की अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि गंभीर वित्तीय हालात कुछ हद तक बाहरी कारणों की वजह से हैं। हालांकि, बहुत बड़ा कारण शासन के स्तर पर संरचनात्मक खामियां हैं, जिसे समय पर ठीक नहीं किया गया। घाटे की बदतर स्थिति से राज्य कर्ज पर निर्भर होता चला गया और आज स्थिति यह है कि प्रति परिवार 2,63,976 रुपये का सार्वजनिक कर्ज है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बिगाड़ा। हमें अगर बढ़ते कर्ज और ब्याज लागत के दुष्चक्र को तोड़ना है, को अपने रुख में व्यापक बदलाव लाना होगा। यह सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर भी है।' श्वेत पत्र में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पिछले आठ साल से बिगड़ रही है और इसके कारण विकास से जुड़ा निवेश प्रभावित हुआ। वर्ष 2006-13 के बीच के सात में से पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राजस्व अधिशेष की स्थिति थी। वर्ष 2013 से राजस्व घाटा जारी है।

अभिषेक व तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले के पीछे शाह का हाथ : ममता

बंगाल की सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री पर लगाया गंभीर आरोप

कहा- हम ऐसी हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में हाल ही में किए गए हमले के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। तृणमूल का आरोप है कि गत शनिवार को त्रिपुरा के धलाई जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले में बंगाल से गए उसके कई नेता व कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह शाह के इशारे पर अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी हरकतों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। त्रिपुरा के सीएम में ऐसे हमलों के निर्देश देने की हिम्मत नहीं है। ममता ने भाजपा को राक्षसी पार्टी भी बताया। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि अभिषेक जिस फ्लाइट से यात्रा करते हैं, भाजपा उसी में अपने कुछ गुंडों का टिकट बुक करा कर सफर कराती है।

ममता ने सोमवार सुबह कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल जाकर त्रिपुरा में घायल हुए दो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी।

ममता बनर्जी सोमवार को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर झाड़ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं। वह आदिवासी संस्कृति के रंग में दिखीं। उन्होंने महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। प्रेट्र

टीएमसी ने भवानीपुर सीट पर ममता के लिए लांच किया नया नारा

बंगाल में उपचुनाव के तारीखों की घोषणा भले अभी नहीं हुई है, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी ने भवानीपुर सीट पर अपनी पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नया चुनावी नारा लांच कर दिया है। ममता भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने वाली हैं। टीएमसी ने नए नारे में ममता को भवानीपुर की बेटी बताते हुए इसका नाम 'उन्नयन घरे-घरे, घरेर मेये भवानीपुर' (विकास हर घर में, भवानीपुर की अपनी बेटी) दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले हाल में संपन्न बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल ने 'बांग्ला निजेर मेये के चाय' (बंगाल अपनी बेटी को चाहता है) का नारा दिया था, जो बेहद ही हिट रहा था।

'आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा को कानून लाए केंद्र'

सोमवार को झाड़ग्राम में अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कानून लाना चाहिए। इसके साथ ही गैर-आदिवासी लोगों को उन भूखंडों के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

असम के मुख्यमंत्री सरमा ने मोदी और शाह से मिल बताए प्रदेश के हालात

नई दिल्ली, एएनआइ : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें मिजोरम के साथ सीमा विवाद से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी और शांति स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार के कदमों के बारे में बताया। सरमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तर-पूर्व के विकास मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की।

सरमा ने राज्य के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात में प्रधानमंत्री को सीमा विवाद के अतिरिक्त राज्य में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया गया। साथ ही राज्य की अपेक्षाओं से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। मोदी ने नई सरकार से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने को कहा। आश्वासन दिया कि राज्य के विकास में सहयोग देने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

सरमा और सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में सीमा विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। शांति कायम करने के प्रयासों के बारे में बताया। बताया कि दोनों प्रदेशों ने शांति स्थापित करने के लिए विवादित इलाके में तटस्थ बलों की गश्त का फैसला किया है। इस फैसले के तहत इलाके में फिलहाल केंद्रीय बल तैनात हैं।

राज्य में राजमार्गों के विकास और अन्य योजनाओं पर सरमा और सांसदों ने गडकरी से मुलाकात कर अपनी बात कही। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर सरमा और सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से बात की। उत्तर-पूर्व मामलों के मंत्री रेड्डी से मुलाकात में विकास योजनाओं को गति देने पर बात की गई जिससे उनका फायदा जनता को जल्द मिल सके।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रेट्र

सीमा विवाद को कांग्रेस ने लटकाया : सरमा

प्रेट्र के साथ साक्षात्कार में असम के सीएम सरमा ने कहा, असम-मिजोरम सीमा पर शांति है लेकिन यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान रातों-रात संभव नहीं है। यह समस्या ब्रिटिश शासनकाल से है जिसे कांग्रेस की सरकारों ने फायदे के लिए लटकाए रखा। विदित हो कि 26 जुलाई को दोनों राज्यों के सुरक्षा बल आमने-सामने आ गए थे। उस दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में असम पुलिस के छह जवानों और एक नागरिक की मौत गई थी।

उप्र में महापुरुषों के वंदन से शुरू भाजपा का चुनाव अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी तो कई महीने से है, लेकिन अब महापुरुषों के वंदन के साथ संगठनात्मक गतिविधियों का अभियान शुरू हुआ है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख भी मैदान में उतर आए हैं। पहला कार्यक्रम अगस्त क्रांति दिवस से शुरू हुआ है, जिसमें ब्लाक स्तर पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ कर माल्यार्पण किया जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उप्र प्रवास के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कुछ कार्यक्रम तय किए। विस प्रभारियों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों की बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दी। इनकी शुरुआत सोमवार को अगस्त क्रांति दिवस से हो गई। पार्टी कार्यकर्ता सहित जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई कर माल्यार्पण किया। किसी न किसी महापुरुष के प्रति आस्था अधिक होती है, इसे देखते हुए पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा छूटे नहीं। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा।

नीतीश बोले, राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना के लिए करेंगे विचार

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना के लिए वह विचार-विमर्श करेंगे। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जनगणना का काम तो पूरे देश में एक साथ होता है, लेकिन जानकारी के लिहाज से जाति की गणना कर्नाटक सहित कुछ अन्य राज्यों ने किया है। हम लोगों की सोच है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराए। यह राष्ट्र के हित में है।

नीतीश ने कहा कि जातिगत जनगणना के संदर्भ में निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। यह कहीं से भी राजनीतिक मसला नहीं, बल्कि यह सामाजिक मामला है। इस मसले पर उनके द्वारा लिखा गया पत्र चार अगस्त को ही प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मिलेगा तो वह इस बारे में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि 2019 में बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। उसके बाद 2020 में भी इस संदर्भ में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। जातिगत जनगणना का काफी फायदा होगा। एक-एक चीज की जानकारी हो जाएगी। हम लोगों के मन में 1990 से यह बात है। 1931 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। बकौल नीतीश, मेरी तो यह समझ है कि यह राष्ट्र के हित में है।

दूसरे राज्यों में भी जदयू लड़ेगा चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि जदयू बिहार के बाहर भी अपने पांव पसारेगा। निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर गठबंधन होता है तो ठीक, अन्यथा जदयू अपने दम पर अकेले ही चुनाव में मैदान में उतरेगा।

अगले साल उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में जनाधार वाले कई राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपने लिए गुंजाइश तलाश रहे हैं। इनमें जदयू के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल दूसरे घटक दल (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी) भी हैं। रविवार को जदयू के प्रदेश प्रवक्ताओं ने तो सामूहिक रूप से प्रेसवार्ता का आयोजन कर उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। अब नीतीश कुमार उस पर मुहर लगा रहे हैं।

बकौल नीतीश, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विभिन्न राज्यों से आए पार्टी पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अपनी बात कही थी। अगर गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी अपने बूते चुनाव मैदान में उतरेगी। दरअसल, जदयू के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू को राज्य-स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से वह दूसरे राज्यों में दांव आजमाएगा।

माकपा की केंद्रीय समिति में नहीं मिलेगी 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को जगह

नई दिल्ली, प्रेट्र : माकपा ने केंद्रीय समिति के सदस्यों की आयुसीमा 80 साल से घटाकर 75 साल करने का फैसला किया है। केंद्रीय समिति की छह से आठ अगस्त के बीच हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। यह पार्टी के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है, जो पोलित ब्यूरो के सदस्यों का चयन करती है। पार्टी के 23वें अधिवेशन में अनुमोदन के बाद यह निर्णय प्रभावी हो जाएगा। अधिवेशन का आयोजन अगले साल अप्रैल में केरल के कन्नूर में किया जाएगा।

अप्रैल 2018 में हैदराबाद में हुए पार्टी के अधिवेशन में मौजूदा केंद्रीय समिति का चयन किया गया था। तब समिति सदस्य के लिए अधिकतम उम्र 80 वर्ष रखा गया था। एस. रामचंद्रन पिल्लई को इससे छूट दी गई थी, ताकि उन्हें पोलित ब्यूरो सदस्य बरकरार रखा जाए। मौजूदा 17 सदस्यीय पोलित ब्यूरो में रामचंद्रन सबसे उम्रदराज, जबकि 64 वर्षीय मुहम्मद सलीम व नीलोत्पल बसु सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन 76 साल के हैं और नए फैसले से पोलित ब्यूरो से बाहर हो सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया, 'हमने निर्णय लिया है कि 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को केंद्रीय समिति से मुक्त किया जाए।'

अब मुलायम और देवेगौड़ा से मिले ओमप्रकाश चौटाला

तीसरे मोर्चे का ताना-बाना बुनने में जुटे इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने सोमवार को नई दिल्ली में सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान ओमप्रकाश चौटाला के पौत्र करण चौटाला भी मौजूद रहे। सौ. इनेलो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला भाजपा व कांग्रेस के विरुद्ध तीसरे मोर्चे का ताना-बाना बुनने में जुटे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंच कर चुके चौटाला ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दोनों उनके पुराने साथियों में शुमार हैं।

चौटाला अपने पिता पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को हरियाणा में एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं। इसके जरिये वह गैर कांग्रेसी व गैर भाजपाई नेताओं को एकजुट करना चाहते हैं। साथ ही यह संदेश देना चाहते हैं कि पुराना कैडर इनेलो के साथ। इसी कड़ी में वह गैर कांग्रेसी व गैर भाजपाई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एचडी देवेगौड़ा और मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में मुलाकात की और तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा की। अब चौटाला अगले 10 दिनों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और शरद यादव से भी मुलाकात करेंगे।

कांग्रेस नेताओं को सियासी रणनीति समझाएंगे राहुल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता, मीर के बेटे की शादी में लिया हिस्सा

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी मंगलवार को सुबह माता क्षीर भवानी के दर्शन करने के बाद श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें वह सियासी रणनीति बनाने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। इसके पहले वह दो दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रधान जीए मीर के बेटे की शादी के समारोह में हिस्सा लिया।

राहुल गांधी श्रीनगर हवाई अड्डे से सीधे नेहरू गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां से मीर के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए। हवाई अड्डे पर प्रदेश प्रधान जीए मीर, पार्टी की जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, वरिष्ठ नेता रमण भल्ला, मुलाराम, तारिक हमीद करा, मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, एनएसयूआइ के राष्ट्रीय प्रधान नीरज कुंदन आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी मंगलवार सुबह मां क्षीर भवानी के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय की नई इमारत का सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। वह इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

'साबरमती आश्रम का पुनर्विकास करना राष्ट्रपिता का अपमान'

संवाद सूत्र, उदयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि आश्रम को तोड़कर संग्रहालय बनाने की गुजरात सरकार की योजना बेहद ही चौंकाने वाली है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आश्रम का अपमान करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने के साथ ही फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।

गहलोत ने ट्विटर पर साझा एक बयान में कहा कि गुजरात सरकार का साबरमती आश्रम को गिराकर संग्रहालय बनाने का निर्णय अनुचित है। यदि गुजरात सरकार की साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना अमल में लाई गई तो यह महात्मा गांधी और आश्रम की गरिमा का अपमान होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधीजी से जुड़ी हर चीज को बदलने के लिए राजनीतिक मकसद से यह फैसला लिया गया है। देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश को भविष्य की पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐतिहासिक आश्रम की रक्षा करने की मांग की। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 1200 करोड़ रुपये के गांधी आश्रम स्मारक और विकास परियोजना के तहत साबरमती आश्रम के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा है।

गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम सद्भाव और बंधुत्व के विचारों के लिए जाना जाता है। देश-विदेश के लोग वहां विश्वस्तरीय इमारत नहीं देखना चाहते। यहां आने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने किस तरह का सादा जीवन जिया और समाज के हर वर्ग को जोड़कर उन्होंने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने वहां अपने जीवन के महत्वपूर्ण 13 साल बिताए थे।

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने सावरकर की हिंदू राष्ट्र की मांग को बताया जायज

संवाद सूत्र, उदयपुर

- गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा-सावरकर ने कोई गुनाह नहीं किया
- गहलोत सरकार में मंत्री के बयान से प्रदेश में छिड़ी नई बहस

राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को वीर सावरकर पर बयान देकर राजनीति के गलियारों में चर्चा का माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से पहले सावरकर की हिंदू राष्ट्र की मांग जायज थी।

दरअसल, अगस्त क्रांति दिवस पर सोमवार को हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि हम यह इन्कार नहीं करते कि स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर शामिल नहीं हुए। आजादी से पहले उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग भी जायज थी और कोई गुनाह भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से विपरीत उनके इस बयान से प्रदेश भर में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि, डोटासरा ने यह भी कहा कि सावरकर ने खुद अंग्रेजों से उन्हें जेल से बाहर आने की उपयोगिता समझाई। उन्होंने कौन-कौन सी सूचनाएं अंग्रेजों को दीं, सभी को पता हैं। हैरत तो तब होती है कि जो लोग उनके परम राष्ट्रभक्त होने का दावा कर रहे हैं, जिनका आजादी के आंदोलन में योगदान नगण्य है। डोटासरा ने यह भी कहा कि भाई से भाई को लड़ाने का षड्यंत्र भाजपा-आरएसएस करते हैं। हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे।

कांग्रेस ने चिदंबरम को गोवा, जयराम को मणिपुर का पर्यवेक्षक बनाया

नई दिल्ली, आइएएनएस : आगामी विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रबंधन के काम में लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गोवा में चुनाव प्रचार की निगरानी करने के लिए वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को मणिपुर का भार सौंपा है। गोवा और मणिपुर में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।

दोनों राज्यों में कांग्रेस बहुमत से कुछ ही सीटें दूर रही थी और भाजपा सत्ता में आ गई। 2017 से गोवा में इसके दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पाला बदल लिया। दोनों नेताओं के सामने चुनाव जीतने के साथ ही सभी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी होगी। एक बयान में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को पर्यवेक्षक बनाने की जानकारी दी।

46 नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनएलएफबी) के उग्रवादियों ने किया समर्पण असम में। एक महीने से भी कम समय में नवगठित एनएलएफबी के उग्रवादियों का यह दूसरा सामूहिक आत्मसमर्पण है।

पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रोन से गिराया आरडीएक्स टिफिन बम, पांच ग्रेनेड मिले

नापाक करतूत ▸ आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, गिराए गए बम को किया डिफ्यूज

जागरण टीम, अमृतसर

दहशत फैलाने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में हथियार गिराए गए। इस बार ग्रेनेड के साथ आरडीएक्स टिफिन बम गिराया गया, लेकिन पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान और आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है।

शनिवार और रविवार की रात को फेंके गए इस बम में दो से तीन किलो आरडीएक्स था, जबकि इसके साथ ही पुलिस ने पांच ग्रेनेड और नौ एमएम के एक सौ से ज्यादा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्वतंत्रता दिवस से सात दिन पहले बम गिराए जाने की कार्रवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। यहां मीडिया से बातचीत करते डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आतंकियों के खिलाफ बेबाकी से बोलने के कारण उनके निशाने पर हैं, परंतु उनकी सुरक्षा कड़ी की हुई है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर तलाशी अभियान में विस्फोटक सामग्री मिली है। एक बैग में मिले सात पैकेट में से एक पैकेट में दो से तीन किलो आरडीएक्स और स्विच मैकेनिज्म वाला टाइम बम था। आरडीएक्स टिफिन बम के अलावा तीन डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। बम को सोमवार सुबह एनआइए व एनएसडी कमांडो की देख-रेख में डिफ्यूज किया गया। डीजीपी ने कहा कि यह बम किसी स्पेशलिस्ट की ओर से बनाया गया है और किसी बड़े मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होना था। कुछ समय से सीमा पार से आतंकी गतिविधियां फिर बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि करीब 25 साल पहले आतंकवाद के दौर में ट्रांजिस्टर बम और टिफिन बमों का प्रयोग होता था, लेकिन अब ड्रोन के जरिये इसकी सप्लाई चिंता का विषय है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है और यह भी पता किया जा रहा है कि हथियारों की यह खेप किसके लिए भेजी गई थी। इस घटना के पीछे गैंगस्टरों और आतंकियों के लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती।

अमृतसर के गांव डालेके के पास से बरामद आरडीएक्स टिफिन बम। बम को सोमवार सुबह एनआइए व एनएसडी कमांडो की देख-रेख में डिफ्यूज किया गया। विज्ञप्ति

किसान ने रात 12 बजे सुनी थी ड्रोन की आवाज

थाना लोपोके के अधीन पड़ने वाले गांव बच्चीविंड के किसान जग्गा शनिवार रात करीब 12 बजे खेत में ट्यूबवेल चलाने के लिए घर से निकला था। तभी उसने ड्रोन की आवाज सुनी। रविवार सुबह उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। अमृतसर देहाती के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना, डीएसपी गुरिंदर सिंह नागरा, डीएसपी गुरप्रताप सिंह सहोता के नेतृत्व में पुलिस ने कुछ गांवों में तलाशी अभियान चलाया तो रविवार शाम ढालेके शूरा नहर के पास विस्फोटक से भरा बैग मिला। यह गांव कंटीली तार से तीन किलोमीटर दूर है।

कुछ भी संदिग्ध मिले तो डायल करें 112

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने लोगों से अपील की कि किसी भी माल, रेस्टोरेंट, सिनेमा आदि सार्वजनिक जगह पर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस को 112 नंबर सूचना दें।

दिल्ली से इंदौर आ रहे विमान से टकराया पक्षी, कोई अप्रिय घटना नहीं

नईदुनिया, इंदौर: दिल्ली से इंदौर आ रहे विमान से सोमवार को एक पक्षी टकरा गया। हादसा तब हुआ, जब विमान इंदौर एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था। पायलट ने विमान को सकुशल उतार दिया। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। विस्तारा एयरलाइंस के इस विमान में करीब सौ यात्री सवार थे। विमान उतरने के बाद निरीक्षण किया गया तो मामूली तकनीकी खराबी सामने आई। दरअसल, विस्तारा एयरलाइंस का यह विमान (यूके-913/914) दिल्ली से इंदौर सुबह 7.55 बजे आता है। इसके बाद सुबह 8.30 बजे वापस दिल्ली जाता है। सोमवार को भी यह सही समय पर इंदौर आया, लेकिन उतरने से कुछ देर पहले विमान से पक्षी टकरा गया। थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाहट हुई, लेकिन पायलट ने समझदारी से विमान को सुरक्षित उतार लिया। इससे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी घटना की सूचना दे दी।

विमान से यात्री उतरने के कुछ देर बाद ही दिल्ली जाने वाले 113 यात्री चढ़ गए थे, उसी समय पता चला कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। इस कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को वापस उतारा गया। बाद में दिल्ली से चार इंजीनियरों को लेकर दूसरा विमान आया। यही विमान दोपहर करीब दो बजे यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना हुआ। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार रात तक विमान की गड़बड़ी सुधारी नहीं जा सकी थी।

बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, टीएमसी पर आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- हावड़ा के बागनान इलाके की वारदात, पीड़िता घर में थी अकेली
- मामले में तृणमूल कांग्रेस के दो स्थानीय नेता गिरफ्तार, तीन फरार

बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह वारदात हावड़ा के बागनान थाना क्षेत्र में शनिवार रात की है। इसका आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पांच स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरोप है कि 34 वर्षीय महिला को बांधकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी तीन फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपितों के नाम कुतुबुद्दीन मलिक व देवाशीष राणा हैं। सोमवार को दोनों को उलबेरिया अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात पीड़िता घर में अकेली थी। पति काम के सिलसिले में कोलकाता में थे। आरोप है कि रात करीब साढ़े बारह बजे पांच लोग भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सभी घर के अंदर घुसे और सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता अचेत हो गई। रविवार सुबह घर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता को वारदात की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़िता को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीड़िता के पति ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनके बूथ से भाजपा को बढ़त मिली थी। यही कारण है कि तृणमूल नेताओं ने वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। भाजपा ने इस घटना की निंदा करते हुए तृणमूल को घेरा है। साथ ही पुलिस पर शुरू में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी का भी आरोप लगा है। हालांकि, तृणमूल ने इस वारदात में अपने कार्यकर्ताओं के शामिल होने से इन्कार किया है।

अमित मालवीय ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप : भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वारदात को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बंगाल में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि विरोधियों को चुप कराने के लिए टीएमसी दुष्कर्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

भाजपा ने शुरू किया बंगाल बचाओ सप्ताह, निकाला मशाल जुलूस : बंगाल में ममता सरकार पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाते हुए भाजपा की प्रदेश इकाई ने राज्य की बिगड़ती कानून- व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को 'बंगाल बचाओ सप्ताह' की शुरुआत की। बंगाल बचाओ सप्ताह के दौरान भाजपा अगले एक हफ्ते तक ममता सरकार को घेरने के लिए धरना, प्रदर्शन करेगी।

उप्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं गंगा-यमुना

प्रयागराज शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। बारा थाना क्षेत्र के मझियारी में यमुना का पानी गांवों तक जा फैला है। ग्रामीण नाव से आवाजाही कर रहे हैं। जागरण

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों में उफान जारी है। प्रयागराज में गंगा पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रहीं थीं, रविवार रात यमुना भी खतरे का निशान पार कर गईं। वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर हैं। कानपुर में यमुना में उफान है, जबकि गंगा, बेतवा और चंबल स्थिर हैं। गंगा और यमुना की बाढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी आबादी भी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। बिहार में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गांधी घाट पर गंगा नदी लाल निशान से करीब 98 सेंमी ऊपर बह रही है। कुछ ऐसा ही हाल दीघा घाट पर भी है। पटना के अलावा बक्सर में भी गंगा उफान पर है। बक्सर में गंगा सोमवार को लाल निशान से 31 सेमी ऊपर बह रही है। वहीं समस्तीपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे जिले के तीन प्रखंड मोहनपुर, मोहिउद्दीननगर व विद्यापतिनगर प्रभावित हैं। वह खतरे के निशान से एक मीटर 40 सेमी ऊपर बह रही है।

प्रयागराज में बाढ़ की विभीषिका विकराल हो चली है। आधी रात यमुना भी खतरे का निशान पार कर गई। गंगा का जलस्तर रविवार शाम सात बजे ही खतरे का निशान (84.73 मीटर) पार कर गया था। शहरी में बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। करीब 12 हजार मकान पानी से घिर गए हैं। बीते बुधवार को राजस्थान के धौलपुर बैराज और मध्य प्रदेश के माताटीला बैराज से छोड़ा गया पानी यहां आफत बन चला है। सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अधिकारियों का कहना है कि सहायक नदियों से आया यमुना का पानी बैक फ्लो कर रहा है। इससे गंगा का जलस्तर भी बढ़ा है।

चमोली में फूलों की घाटी में बादल फटा, पर्यटकों की आवाजाही रोकी

जागरण टीम, गढ़वाल : चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा एक पुलिया भी बह गई है। हालात को देखते हुए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक मार्ग दुरुस्त कर लिया जाएगा।

घटना रविवार देर रात की है। मुख्य पड़ाव घांघरिया से दो किलोमीटर दूर बामणधौड़ में बारिश के बीच एक बरसाती नाले में उफान आ गया। पानी के साथ भारी मात्रा में आए मलबे से करीब 20 मीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा इसी मार्ग पर एक पुलिया भी बह गई। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी नंदबल्लभ शर्मा ने बताया कि 70 पर्यटकों को मुख्य पड़ाव घांघरिया में रोक दिया गया है। 12 श्रमिकों की मदद से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने बताया कि फूलों की घाटी में पर्यटकों को रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है। पर्यटकों को सुबह 12 बजे तक घाटी में प्रवेश करना होता है और दोपहर बाद तीन बजे उनकी वापसी हो जाती है।

तीन दिन पहले हिजबुल में शामिल दो आतंकी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़

पुलिस और सेना ने किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी तीन दिन पहले ही हिजबुल में शामिल हुए थे। इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल, दो ग्रेनेड, पिस्टल के 20 कारतूस, यूबीजीएल (अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर), एक वायरलेस सेट और एक पाउच बरामद हुआ है। पकड़े गए आतंकियों में यासिर हुसैन और उस्मान कादिर शामिल हैं। ये दोनों आतंकी पांच अगस्त से अचानक घर से गायब हो गए थे। इसके बाद आतंकी संगठन में शामिल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इन्हें दबोचने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इसके बारे में सूचना मिलने पर रविवार को पुलिस ने सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सोमवार को पुलिस और सेना ने तीन दिन पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जागरण

सुरक्षित आवासीय सुविधा छोड़कर चले गए थे

▸ प्रथम पृष्ठ का शेष

कश्मीर के आइजीपी विजय कुमार ने बताया कि यह वारदात लश्कर के आतंकियों ने अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और उसकी पत्नी को कुलगाम में एक होटल में सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले ही उसे छोड़ दिया था और अपने घर में रहने लगे। वह कुछ समय पहले अनंतनाग में एक अन्य मकान में आकर रहने लगे। फिलहाल, उनके अंगरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

उपराज्यपाल और अन्य नेताओं ने हत्या की निंदा की : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने पति-पत्नी की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है।

एक साल में 14 भाजपा कार्यकर्ता की हत्या

दो जून 2021 : त्राल में भाजपा नेता और त्राल म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता की हत्या की।

29 मार्च, 2021 : सोपोर में भाजपा से संबंधित दो काउंसलर आतंकी हमले में मारे गए।

आठ जुलाई, 2020 : भाजपा नेता वसीम बारी को उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर सुल्तान संग उनके घर में ही मार दिया था।

नौ अगस्त, 2020 : बड़गाम में भाजपा नेता अब्दुल हमीद नजार आतंकी हमले में मारे गए।

छह अगस्त 2020 : काजीगुंड में भाजपा से संबंधित सरपंच सज्जाद अहमद खांडे आतंकी हमले में मारे गए।

23 सितंबर, 2020 : बड़गाम में भाजपा समर्थित ब्लाक विकास परिषद के चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह की आतंकियों ने उनके घर के बाहर हत्या कर दी थी।

29 अक्टूबर, 2020 : कुलगाम में भाजपा के तीन कार्यकर्ता फिदा हुसैन यत्तु, उमर रशीद बेग और उमर रमजान हज्जाम को आतंकियों ने अगवा कर मार डाला था।

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

जागरण संवाददाता, पुंछ : सुरक्षाबलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पुंछ जिले में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को विफल कर दिया है। कृष्णा घाटी सेक्टर में सीमावर्ती गांव कस्सबलाड़ी इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया तो हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई। तलाशी अभियान में सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के खोजी कुत्तों को भी उतारा गया। पुंछ जिले के एसएसपी डा. विनोद कुमार ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ जंगल में चलाया गया। इसी दौरान आतंकी ठिकाना खोजा गया। आतंकी ठिकाने से दो एके-47 राइफल, एके-47 की चार मैगजीन और इसके 257 कारतूस, एक चीन निर्मित पिस्टल व इसकी दस मैगजीन, एक रेडियो सेट, चार चीन निर्मित ग्रेनेड, नौ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, चार नान-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, चीन निर्मित हथगोले के 15 फ्यूज डेटोनेटर लीवर के साथ, 16 मीटर कार्डेक्स वायर, नौ एमएम पिस्टल के 68 कारतूस, 7.65 एमएम एएमएनएस-23 कारतूस, दो मोबाइल फोन, 12 बैटरी मोबाइल चार्जर, दो नौ वोल्ट बैटरी बरामद की गईं। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने इन हथियारों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छुपा कर रखा था, जिसे बरामद करके बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया गया।

भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा, नए कृषि कानून हो सकते हैं वापस

जागरण संवाददाता, बलिया : उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य व पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसे वापस ले सकती है। उन्होंने बलिया में रविवार रात पत्रकारों से कहा कि किसानों की मांग सही है। विधानसभा चुनाव और किसानों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार नए कृषि कानून वापस ले सकती है। कृषि कानूनों के विरोध के कारण, भाजपा नेता पश्चिमी यूपी के गांवों में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि किसान भविष्य में भी उनका घेराव भी कर सकते हैं। गतिरोध पर उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। अगर विपक्ष जांच चाहता है, तो सरकार को इस पर आगे बढ़ना चाहिए।

नीट-एमडीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग की जानकारी तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह 11 अगस्त तक उसे बताए कि वह नीट-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग कब आयोजित करेगा, जिसके लिए 16 दिसंबर, 2020 को परीक्षा हुई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अब जब केंद्र ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसलिंग कब कराएगी। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि यह क्या है। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है कि केंद्र ने ओबीसी कोटा को मंजूरी दे दी है। अब फिर से आप इसे अक्टूबर या नवंबर में ले जाएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कृपया हमें बुधवार तक बताएं कि आप काउंसलिंग कब आयोजित करने जा रहे हैं। हम मामले को पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 29 जुलाई को ओबीसी के लिए 27 फीसद कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना में 10 फीसद आरक्षण को मंजूरी दी है। 12 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग आयोजित करने में देरी का यह कहते हुए कड़ा संज्ञान लिया था कि केंद्र और अन्य एक साल से ढिलाई कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये योग्य बीडीएस छात्र हैं और केंद्र ने पिछले साल से काउंसलिंग क्यों नहीं की।

बैचलर इन डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की डिग्री रखने वाले डाक्टर, एमडीएस पाठ्यक्रम के लिए पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन (एनबीई) द्वारा डेंटल सर्जरी में मास्टर में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी-एमडीएस में शामिल हुए थे।

केंद्र और एमसीसी के अलावा, पीठ ने पहले डेंटल काउंसिल आफ इंडिया और नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को भी नोटिस जारी किया था।

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ये डाक्टर एनईईटी-एमडीएस, 2021 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा करने में एमसीसी द्वारा की गई अन्यायपूर्ण और अनंत देरी को चुनौती दे रहे हैं। याचिका में एमसीसी को एनईईटी-एमडीएस 2021 के लिए एक अलग काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

एक करोड़ रुपये में खरीदा था पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर

पंकज आत्रेय, कैथल : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर एक करोड़ रुपये में खरीदा गया था। पेपर लीक गिरोह का मुख्य आरोपित हिसार निवासी नरेंद्र है। पुलिस इस प्रकरण में अब तक दस से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार नरेंद्र ने एक करोड़ रुपये में उत्तर पुस्तिका खरीदी थी। परीक्षा से एक दिन पहले शाम को ही कैथल पहुंचकर उसने बालाजी डिफेंस एकेडमी के संचालक रमेश चंद्र थुआ को प्रश्न और उत्तर नोट करा दिए थे। एसपी लोकेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। नरेंद्र उत्तर पुस्तिका किससे खरीदकर लाया, वह किन-किन लोगों के संपर्क में था, इसकी पड़ताल के लिए उसे नौ दिन के रिमांड पर लिया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि नरेंद्र ने बालाजी डिफेंस एकेडमी, कैथल के संचालक रमेश चंद्र को उत्तर पुस्तिका दस लाख रुपये प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से बेची थी।

किस्मत-कनेक्शन

...गुजरात में नीरज नाम वालों की पौ बारह

ओलिंपियन नीरज के हमनाम को रोप-वे में सवारी व हेयर कटिंग से लेकर पेट्रोल तक मिल रहा मुफ्त

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा देश की आंखों का तारा बन गए हैं। उनकी मेहनत का फल तो उन्हें मिलना ही था, लेकिन गुजरात में उनके हमनाम की भी पौ बारह हो गई है। नीरज नाम वालों को रोप-वे में सफर और हेयर कटिंग से लेकर पेट्रोल तक मुफ्त में मिल रहा है।

लंबे इंतजार के बाद ओलिंपिक में जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) में जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा तो दुनियाभर में बसे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। केंद्र व राज्य सरकारें, खेल संगठन आदि ने ओलिंपिक विजेताओं के लिए खजाने खोल दिए हैं, तो गुजरात के लोग भला अपनी खुशी जताने में पीछे कैसे रहते। जूनागढ़ के गिरनार रोप-वे में नीरज नाम वाले वाले मुफ्त सवारी कर सकेंगे। इसकी संचालक उषा ब्रेको कंपनी के अनुसार, 20 अगस्त तक नीरज नाम का कोई भी व्यक्ति अपना पहचान पत्र लेकर गिरनार रोप-वे की मुफ्त सवारी कर सकता है। यह देश के सबसे लंबे रोप-वे में शुमार है, जिसका एक तरफ का किराया 400 रुपये व दोनों तरफ का 700 रुपये है। पहले गिरनार पर्वत पर स्थित अंबे माताजी के मंदिर में जाने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं।

नीरज बने स्टाइल आइकान। फाइल फोटो

भरूच के एसपी पेट्रोल पंप ने भी अनोखी योजना शुरू की है। उसने नीरज नाम वालों को 501 रुपये का पेट्रोल मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके बाद पेट्रोल पंप पर नीरज नामधारियों की भीड़ एकत्र हो गई। भरूच के ही अंकलेश्वर में एक सैलून मालिक ने भी नीरज नाम के लोगों की मुफ्त में कटिंग व शेविंग करने की घोषणा की है।

उप्र के शामली में एक परिवार के 18 लोगों ने हिंदू धर्म में की वापसी

जागरण संवाददाता, शामली : उप्र में शामली जिले के कांधला कस्बे के निवासी बंजारा समाज के एक परिवार के 18 लोगों ने सोमवार को इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। सुबह मंदिर परिसर में हवन पूजन व शुद्धीकरण के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। उन्हें जनेऊ भी धारण कराया गया। सभी ने अब हिंदू धर्म में ही रहने का संकल्प लिया। इस दौरान हिंदू समाज के काफी लोग मौजूद रहे।

मोहल्ला रायजादगान निवासी उमर उर्फ संजू पुत्र इकबाल उर्फ अमीचंद कस्बे में करीब 25 वर्ष से रह रहे हैं। उनके बेटे राशिद उर्फ विकास ने बताया कि वह बंजारा समाज से हैं। उनके पूर्वज हिंदू धर्म से थे। पूर्व में अलग-अलग स्थानों पर डेरा लगाकर रहते थे। कांधला आने से पूर्व उनके पूर्वज कैराना कोतवाली के गांव अलीपुर और फलावदा में रहते थे। उनके समाज में व्यक्ति की मौत के बाद शव को समाधि देने की प्रथा चली आ रही थी। उनके समाज के पास कांधला में इस क्रिया के लिए अपनी कोई जगह नहीं थी। चूंकि उनके पूर्वज इस्लाम धर्म के कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाते थे। इसी परेशानी के चलते उनके पूर्वज अमीचंद ने 13 साल पूर्व परिवार सहित हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। अपना नाम अमीचंद से इकबाल रख लिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। राशिद उर्फ विकास ने बताया कि इस्लाम धर्म कबूल किए हुए काफी समय बीत गया।

टीजीटी के साल्वर गैंग पर अब गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) की परीक्षा में सेंधमारी के दौरान पकड़े गए साल्वर गैंग के सरगना और उसके छह गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई होगी। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी आरोपितों की अवैध तरीके से अर्जित चल व अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।

गिरोह का सरगना धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके सोरांव थाना क्षेत्र के वादी का पूरा कमलानगर निवासी है। पहले वह 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपित डा.केएल पटेल के साथ काम करता था। बाद में उसने अलग गैंग बना लिया और प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर बैठाने से लेकर पेपर तक आउट कराने लगा। टीजीटी की परीक्षा में पास कराने के लिए उसने प्रति अभ्यर्थी से 12 से 15 लाख रुपये में सौदा तय किया था। वह सिपाही भर्ती, टेट, सुपर टेट, सी-टेट और रेलवे की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा कर चुका है।

पूछताछ में पता चला है कि शंकरगढ़ का आशीष सिंह पटेल पेपर आउट कराने तथा सुभाष पटेल (सोरांव), मनीष पटेल (फूलपुर) और दिनेश कुमार पटेल (बहरिया) कंडीडेट लाने का काम करते थे। फूलपुर निवासी राहुल कनौजिया व होलागढ़ के संजय पटेल, परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षक से सेटिंग कर नकल करवाते थे। इनका भी संबंध केएल पटेल से है।

नए मामलों में आई गिरावट, 24 घंटे में 35 हजार केस

सुधरते हालात ▶ सक्रिय मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट

कोरोना को हराना है

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहे केरल में स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। रविवार को कम जांच होने के चलते सोमवार को नए मामलों में तो कमी आई, लेकिन केरल फिर भी आधे से अधिक मामले पाए गए। हालांकि, राज्य में मृतकों की संख्या सौ से नीचे आ गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामलों में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई और 4,634 की कमी के साथ एक्टिव केस चार लाख के करीब आ गए। कोरोना संक्रमण के बाकी पैरामीटर पूर्व की स्थिति में बने हुए हैं जैसे मरीजों के उबरने की दर, मृत्युदर और दैनिक एवं साप्ताहिक संक्रमण दर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

अब विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे वैक्सीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अब भारत में रहने वाले विदेशी भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह फैसला किया। विदेशी नागरिकों को आधार नंबर की जगह अपने पासपोर्ट को पहचान पत्र के रूप में पेश करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भी वैक्सीन लेने के पहले कोविन प्लेटफार्म पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए उन्हें पासपोर्ट नंबर देना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण केंद्र और समय मिल जाएगा। देश में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं और उनमें अधिकांश बड़े शहरों में केंद्रित हैं। ऐसे में वैक्सीन नहीं लेने वाले लोग न सिर्फ संक्रमित हो सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं।

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	35,499
कुल सक्रिय मामले	4,02,188
24 घंटे में टीकाकरण	16.11 लाख
कुल टीकाकरण	50.86 करोड़
सोमवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	35,499
कुल मामले	3,19,69,954
सक्रिय मामले	4,02,188
मौतें	(24 घंटे में) 447
कुल मौतें	4,28,309
ठीक होने की दर	97.39 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.59 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.35 फीसद
जांचें (रवि.)	13,71,871
कुल जांचें (रवि.)	48,17,67,232

देश में अब तक 51 करोड़ डोज लगाई गई

कोरोना महामारी के खिलाफ जनवरी में शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 51 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 16 लाख से डोज लगाई गई है।

स्वतंत्रता के सारथी — महामारी से आजादी

तकनीक के सहारे दिखाई टीकाकरण की राह

कानपुर में दो दोस्तों की मुहिम बनी वरदान, वाट्सएप के जरिये बुक कराया 10 हजार लोगों का स्लाट

राजीव सक्सेना • कानपुर

स्वतंत्रता पर्व की तैयारियों के बीच ऐसे नायकों की चर्चा जरूरी है जिन्होंने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कोरोना महामारी से आजादी की अलख जगाई। आज इसी क्रम में कानपुर के दो दोस्तों के बारे में जानते हैं जिन्होंने जिंदगी का टीका लगवाने में आम जनता की अनूठे तरीके से मदद की।

दूसरी लहर के दौरान जब लोग टीकाकरण कराने के लिए परेशान थे कि कैसे आनलाइन स्लाट (टीकाकरण का दिन व केंद्र) बुक कराएं, तब दो दोस्तों ने 'हमारा कानपुर-बेहतर कानपुर' नाम से वाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को टीकाकरण की राह दिखाई। ये दोनों दोस्त हैं केशव नगर निवासी प्रोफेशनल फोटोग्राफर मनीष त्रिपाठी और अधिवक्ता अमित मिश्रा।

स्लाट बुक न कर पाने वालों के लिए की शुरुआत : मनीष बताते हैं, वास्तव में यह वाट्सएप ग्रुप उन लोगों के लिए बनाया गया था, जो वैक्सीन का स्लाट बुक नहीं कर पा रहे थे। ग्रुप से करीब ढाई सौ लोगों को जोड़ा और सभी से टीकाकरण के लिए स्लाट बुक न करा पाने वाले लोगों को उनका (मनीष व अमित) मोबाइल नंबर देने को कहा। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब दिनभर उनके फोन की घंटी बजती ही रहती थी। वे अब तक करीब 10 हजार लोगों के लिए स्लाट बुक कराकर टीकाकरण करवाने में मदद कर चुके हैं।

कानपुर में कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के लिए अपने मोबाइल से लोगों का स्लाट बुक करते मनीष त्रिपाठी • सौ. : स्वयं

रविवार को भी स्लाट करते रहे बुक : मनीष के मुताबिक, दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण के लिए बहुत अधिक लोग सामने आने लगे, लेकिन ज्यादातर स्लाट बुक नहीं करा पा रहे थे। तमाम के पास स्मार्टफोन भी नहीं था। मित्र अमित के साथ रविवार को छुट्टी का दिन भी स्लाट बुक करने में ही गुजरने लगा। अमित के अनुसार, प्रयास रहता था कि जिनके लिए स्लाट बुक करा रहे हैं, उन्हें उनके घर के पास ही टीका लगवाने का अवसर मिले। हालांकि कई बार यह नहीं भी हो पाता था। लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्लाट बुक हो जाएं और टीका लग जाए।

अब बुजुर्गों की कर रहे मदद

ज्यादातर लोग समझ चुके हैं कि कैसे स्लाट बुक करना है, अब प्रतिदिन आठ से 10 लोग ही संपर्क कर रहे हैं। अब दोनों दोस्त उसी वाट्सएप ग्रुप के जरिये निराश्रित बुजुर्गों के भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं।

कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए लोगों का स्लाट बुक कराने वाले अमित मिश्रा • सौ. : स्वयं

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर नजर रखेंगी 360 जांच टीमें

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर है। सरकार का फोकस इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में जांच की गति बढ़ाने पर है। इसके तहत प्रदेश में 360 रैपिड एंटीजन जांच (रैट) टीमों का गठन किया गया है। हर ब्लाक में कम से कम दो टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए जांच उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही 108 आपात सेवा के लिए एंबुलेंस की संख्या अब बढ़कर 240 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति इस समय काफी धीमी पड़ चुकी है। अब केवल 463 एक्टिव केस हैं। इन सबके बीच विशेषज्ञों ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इस लहर में 18 वर्ष से कम आयु के किशोर व बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बच्चों के लिए पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट व नियोनेटल केयर यूनिट स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के हिसाब से दवाओं की खरीद की जा रही है। बच्चों को टेबलेट न देकर सिरप दिए जाते हैं, इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर इनकी खरीद की जा रही है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आक्सीजन सिलिंडर और आक्सीजन कंसन्ट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहां तैनात मेडिकल स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस हफ्ते देश को मिल सकता है एक और टीका

कोरोना को हराना है

नई दिल्ली, एएनआइ : देश को इस हफ्ते कोरोना रोधी छठी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। भारत के दवा नियामक (डीसीजीआइ) से इस हफ्ते जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने इस मंजूरी के लिए पिछले महीने आवेदन किया था। यह तीन डोज की वैक्सीन है।

अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जायडस कैडिला ने इस वैक्सीन के लिए देश में सबसे ज्यादा 50 केंद्रों पर परीक्षण किया है। इस वैक्सीन का 12-18 आयुवर्ग के किशोरों पर भी ट्रायल किया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पहले वयस्कों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

अब तक पांच वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी

अगर जायकोव-डी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो देश में यह मंजूरी पाने वाली छठी वैक्सीन होगी। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक-वी, माडर्ना और जानसन एंड जानसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। जानसन एंड जानसन सिंगल डोज वैक्सीन है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले हफ्ते राज्यसभा को बताया था कि सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक देश को चार और कोरोना रोधी वैक्सीन मिल जाएंगी। इनमें जायडस कैडिला की वैक्सीन भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा था कि जायडस कैडिला की वैक्सीन को जल्द ही दवा नियामक से मंजूरी मिल जाएगी। जायडस ने जायकोव-डी ब्रांड नाम से कोरोना रोधी वैक्सीन तैयार की है। डीसीजीआइ ने पिछले हफ्ते उससे वैक्सीन को लेकर कुछ और आंकड़े मांगे थे। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने हर साल 10-12 करोड़ डोज का उत्पादन करने की योजना तैयार की है। इससे पहले प्रेस कांफ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल ने कहा कि डीसीजीआइ कैडिला की बच्चों के लिए वैक्सीन की समीक्षा कर रहा है। कैडिला हेल्थकेयर के प्रबंधन निदेशक डा. सर्विल पटेल ने कहा कि मानव पर इस्तेमाल के लिए जायकोव-डी पहली प्लासमिड डीएनए आधारित वैक्सीन है। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा और प्रभाव के मामले में कारगर पाया गया है।

सौ साल पुराना टीबी का टीका कर सकता है बुजुर्गों की रक्षा : शोध

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के एक शोध के मुताबिक तपेदिक (ट्यूबरकुलोसिस-टीबी) की करीब सौ साल पुरानी वैक्सीन बुजुर्गों को कोविड-19 के संक्रमण के खतरों से बचाने में मदद कर सकती है।

बासीलुस कलमेट-गोरिन (बीसीजी) का टीका विश्व में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन है। करीब 13 करोड़ शिशुओं को हर साल वैक्सीन लगाई जाती है।

जिन देशों में बड़ी तादाद में कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं, वहां खासतौर पर वृद्ध आबादी को बीसीजी का टीका लगाने से फायदा होगा। पिछले शोधों में बताया गया था कि बीसीजी के टीके से सांस लेने संबंधी बीमारियों में फायदा हो सकता है। पर अब साइंस जनरल में प्रकाशित नए शोध में बताया गया है कि बीसीजी से संभवतः खून की प्रतिरोधक कोशिकाओं को जागृत किया जा सकता है। हालांकि अभी इस तथ्य को परखा जाना बाकी है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोशिका में इनफ्लेमेशन बढ़ाने की प्रक्रिया को कितने समय तक कायम रखा जा सकता है। आइसीएमआर के टीबी अनुसंधान और एपिडेमियोलोजी की टीमों ने इस शोध में बताया है कि बीसीजी टीके का अत्यधिक इनफ्लेमेशन से सीधा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मध्यम स्थिति के इनफ्लेमेशन में यह लाभकारी है।

राष्ट्रीय फलक

'वैक्सीन के ट्रायल का डाटा सार्वजनिक करें'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल का डाटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआइआइ) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने मामले में कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया है। याचिका में वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया गया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ सुनवाई में मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी। पीठ ने कहा कि हमारे देश में पहले से ही वैक्सीन के प्रति हिचक है विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है जबतक सभी का टीकाकरण न हो जाए। पीठ ने कहा हम देश में वैक्सीन के प्रति हिचक की समस्या से लड़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि दुनिया में बड़ी समस्या वैक्सीन के प्रति हिचक है। अगर हम इस मामले की जांच शुरू कर देंगे तो क्या इससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर संदेह नहीं पैदा होगा। यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट को वैक्सीन की क्षमता पर विश्वास नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह याचिका वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। इसमें तो सिर्फ पारदर्शिता की मांग की गई है।

वैज्ञानिक निर्णय में हस्तक्षेप से इन्कार : बाद में कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह विशेषज्ञों द्वारा लिए गए वैज्ञानिक निर्णय में दखल नहीं देना चाहता। वह इस मामले में निजी स्वायत्तता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन के मुद्दे पर विचार करेगा। कोर्ट ने साफ किया कि वह टीकाकरण पर कोई रोक नहीं लगाएगा।

आक्सीजन टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर क्या किया, बताए केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आक्सीजन के आवंटन और आडिट पर नेशनल टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट पर अमल के बारे में केंद्र सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और इसके सुझावों पर अमल की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह में रिकार्ड पर पेश करने को कहा है। ये निर्देश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने दिए।

सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि नेशनल टास्क फोर्स ने आक्सीजन के आवंटन और आडिट पर सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर पीठ ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स में वरिष्ठ डाक्टर और विशेषज्ञ शामिल थे। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मौजूदा या भविष्य के संकट से निपटने के लिए टास्क फोर्स के सुझावों को ठीक से

नेशनल टास्क फोर्स ने आक्सीजन के आवंटन व आडिट पर सौंपी रिपोर्ट

लागू किया जाए। सुनवाई की शुरुआत में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध पत्र दिया गया है। सरकार को नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल की कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दिल्ली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि उन्हें इस उप समिति की रिपोर्ट पर आपत्ति है।

मेहरा ने कहा कि आक्सीजन आवंटन के इस मामले को भी कोरोना इलाज के इंतजाम पर चल रही सुनवाई के साथ संलग्न किया जाए। तभी कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट आने के बारे में कुछ संदेह होने की बात उठी। केंद्र की ओर से पेश हुईं एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट और उप समिति की अंतिम रिपोर्ट 22 जून को आ गई है। इसके बाद पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह टास्क फोर्स की रिपोर्ट और इसके सुझावों पर अमल की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह में कोर्ट में पेश करे। साथ ही रिपोर्ट की प्रति न्यायमित्र व अन्य पक्षकारों को दे। कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह बाद स्वतः संज्ञान वाले मामले के साथ सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने जयदीप गुप्ता से कहा कि वह और दूसरी न्यायमित्र वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा एक संक्षिप्त नोट कोर्ट में दाखिल करें, जिसमें बताएं कि किस तरह मामले पर विचार किया जाए, ताकि तीसरी लहर के लिए तैयारी रहे। नेशनल टास्क फोर्स ने गत 22 जून को आक्सीजन पर दी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि देश में आक्सीजन का दो-तीन सप्ताह का रिजर्व कोटा होना चाहिए। साथ ही कहा था कि सभी अस्पतालों के पास आपात स्थिति के लिए बफर कैपेसिटी होनी चाहिए और एक आक्सीजन निगरानी कमेटी बनानी चाहिए।

अभिनेता अनुपम श्याम का निधन, मुंबई में अंत्येष्टि

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़

धारावाहिक 'प्रतिज्ञा' में ठाकुर सज्जन सिंह का दमदार किरदार अदा कर मशहूर हुए अभिनेता अनुपम श्याम ओझा (64) का रविवार आधी रात मुंबई के लाइफ लाइन अस्पताल में निधन हो गया। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही गोरेगांव स्थित श्मशान घाट पर हुआ। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। प्रतापगढ़ निवासी अभिनेता अनुपम श्याम करीब साल भर से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। चार दिन पहले उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के लाइफ लाइन हास्पिटल में भर्ती कराया गया था।

स्मृतियों में रहेंगे अनुपम श्याम। फाइल

हमेशा ठकुराइन कह कर ही बुलाते थे : अस्मिता शर्मा

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : अभिनेता अनुपम श्याम के निधन पर रवि किशन, मनोज जोशी और यशपाल शर्मा समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। उनके साथ धारावाहिक प्रतिज्ञा में करीब तीन साल तक पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अस्मिता शर्मा ने दैनिक जागरण से उनकी यादें साझा की। अस्मिता ने कहा, 'उनका इस तरह से गुजरना काफी दर्दनाक है। वह काफी अच्छे एक्टर थे। उनका सेट पर होना एक साथ काफी लंबा और यादगार सफर था। उम्दा एक्टर होने के साथ-साथ अनुपम जी इंसान भी बहुत अच्छे थे। प्रतिज्ञा खत्म होने के नौ साल बाद प्रतिज्ञा 2 में हम दोबारा साथ काम कर रहे थे। उन्हें खाने-पीने का बहुत शौक था। वह अक्सर मुझसे मेरी ससुराल जयपुर से मिठाइयां और कचौड़ियां मंगाने के लिए कहते थे। मैंने कुछ दिन पहले उन्हें एक-एक पीस मिठाई और कचौड़ी खिलाई थी। सेट पर हो या सड़क पर, वह मुझे हमेशा ठकुराइन ही बुलाते थे।'

1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर बम गिराने वाले हीरो नहीं रहे

चेन्नई, प्रेट्र : महावीर चक्र से सम्मानित भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के हीरो कमांडर कसारगोड पत्ताभिरामा गोपाल राव का सोमवार को निधन हो गया। रक्षा सूत्रों ने इससे पहले उनका निधन रविवार को होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि 94 वर्षीय वार हीरो का निधन सोमवार को हुआ। सेवानिवृत्त नौसेना योद्धा का निधन उम्र संबंधी बीमारी के कारण हुआ। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। राव को विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था।

राव ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है को आजाद कराने के लिए हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे टास्क समूह का नेतृत्व किया। आपरेशन कैक्टस लिली के तहत कराची तट पर आक्रमण किया। हवाई, जमीनी और पनडुब्बी से हमले की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने चार दिसंबर 1971 की रात में दुश्मन की जल सीमा में समूह का नेतृत्व किया। दुश्मन की ओर से हो रही गोलाबारी के कारण भारतीय पोत और सैनिकों पर गंभीर खतरा था, इसके बावजूद कमांडर राव आगे बढ़े और दो विध्वंसकों और एक माइनस्वीपर को डुबो दिया। जमीनी लड़ाई शुरू होने के बाद उन्होंने कराची बंदरगाह पर बम गिराया और वहां तेल एवं अन्य ठिकानों को ध्वस्त करने में कामयाब हुए। अभियान में उन्होंने पराक्रम और अतुलनीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया था।

अध्ययन

रायपुर के आयुर्वेद कालेज में शोध के बाद तैयार दवा महिलाओं के लिए बन रही संजीवनी, एलोपैथी में अब तक नहीं है दवा, लक्षण के आधार पर किया जाता है इलाज

आयुर्वेद से मिली राह, रजोनिवृत्ति के दर्द से मिलेगी मुक्ति

आकाश शुक्ला, रायपुर

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं में 45 वर्ष के बाद मीनोपाजल सिंड्रोम (रजोनिवृत्ति) अवस्था आती है। इस अवस्था में महिलाओं को रक्तस्राव, अनियमित मासिक धर्म, जननांग में सूखापन, यूरिन इंफेक्शन, अचानक तेज गर्मी, अनिद्रा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब तक एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, जो इस दर्द को दूर कर सके। आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर में शोध कर पहली बार दवा तैयार की गई है। सात तरह के आयुर्वेद द्रव्य से तैयार टेबलेट का नाम जीवनीय महाकषाय घनवटी रखा गया है।

काय चिकित्सा की विभागाध्यक्ष डा. अरुणा ओझा ने बताया कि रजोनिवृत्ति की बीमारियों को देखते हुए शोध में चरक संहिता से जीवनीय महाकषाय के द्रव्यों से गोली तैयार की गई है।

रजोनिवृत्ति से जूझ रहीं 45 से 55 आयु वर्ग की 60 महिलाओं पर आयुर्वेद महाविद्यालय में दवा का प्रयोग किया गया। इन महिलाओं को सुबह-शाम दो-दो टेबलेट (500 एमजी) दी गई। साथ ही निगरानी की गई। 15 दिनों में सकारात्मक असर सामने आया। दवा से रजोनिवृत्ति के विभिन्न लक्षणों की महिलाओं को 85 से 100 फीसद लाभ मिला। जीवनीय महाकषाय घनवटी को विदारीकंद, शतावरी, अश्वगंधा, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवंती और मुलेठी औषधि से तैयार किया गया है। इसका लाभ ओपीडी में पहुंचने वाली महिलाओं को दिया जा रहा है।

एलोपैथी में लक्षण पर ही इलाज

आंबेडकर अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डा. ज्योति जयसवाल ने बताया कि मीनोपाजल सिंड्रोम की कोई एक दवा एलोपैथी में नहीं है। लक्षण को देखकर ही इलाज किया जाता है। अधिक समस्या आने पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थैरेपी भी एक विकल्प होती है। ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 10 महिलाएं समस्याएं लेकर आती हैं। जागरूकता के अभाव और लोकलाज की वजह से अधिकतर महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं।

अनियमित मासिक धर्म में अशोकारिष्ट उपयोगी

अशोकारिष्ट (विथानिया सोम्निफेरा) का उपयोग कई स्त्री रोगों और अनियमित मासिक धर्म के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा गर्भाशय के विकारों में फायदा करता है। यह अशोक, मुस्ता, विभितकी, जीरका, वासा व धातकी आदि औषधी से बना होता है।

महिलाओं में 45 वर्ष की आयु के बाद मासिक धर्म ना आने की अवस्था शुरू हो जाती है। इसे मीनोपाजल सिंड्रोम कहते हैं। इस दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियां आती हैं। शोध कर इससे दवा तैयार की गई है। ओपीडी में समस्या लेकर आने वाली महिलाओं को दवा का लाभ मिल रहा है।

-डा. अरुणा ओझा, विभागाध्यक्ष, कायचिकित्सा (आयुर्वेद मेडिसिन), शासकीय आयुर्वेद कालेज रायपुर

रजोनिवृत्ति समस्याओं पर दवा का कितना रहा प्रभाव

स्वास्थ्य समस्या	लाभ
हाट फ्लेशेस	95.35 फीसद
अनिद्रा	90.7 फीसद
अति स्वेद प्रवृत्ति	87.8 फीसद
डिप्रेशन	95.35 फीसद
चक्कर आना	87.8 फीसद
मानसिक विक्षोभ	95.24 फीसद
नर्वसनेस	81.82 फीसद

470 करोड़ महिलाएं विश्व में रजोनिवृत्ति की समस्या से गुजरती हैं

25 करोड़ भारतीय महिलाओं को परेशानियां

1 से 5 वर्ष तक भी जूझना पड़ता है परेशानियों से

60 फीसद महिलाओं को होती है चिकित्सा की आवश्यकता

13 प्रदेशों ने दी ईवी नीति को मंजूरी

नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक सहित 13 राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने वाली नीति को या तो मंजूर कर लिया या फिर उसे अधिसूचित कर दिया है। यह जानकारी भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राज्यसभा में सोमवार को दी। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। (प्रेट्र)

कारोबारी पूरी तैयारी के साथ सीसीआइ को बताएं कि आनलाइन कंपनियों ने कहां-कहां नियमों का उल्लंघन किया है। उन्हें सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

— पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री

सेंसेक्स	54,402.85	▲ 125.13
निफ्टी	16,258.25	▲ 20.05
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 45,391	▼ ₹317
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 62,572	▼ ₹1,128
डॉलर	₹ 74.26	▲ ₹+0.11
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 67.91	

अब मिस्ड काल से भी एलपीजी कनेक्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अब सिर्फ एक मिस्ड काल कर नया इंडेन एलपीजी कनेक्शन लिया जा सकता है। इंडियन आयल ने देशभर में पहली बार यह सेवा शुरू की है। इसके लिए 8454955555 पर एक मिस्ड काल करना होगा। इससे ग्राहकों का बहुत समय बचेगा तथा नए कनेक्शन के लिए ग्राहकों को मुफ्त पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को विशेष लाभ मिलेगा।

इंडियन आयल के चेयरमैन एसएम वैद्य ने बताया कि कंपनी देशभर में सभी संभावित ग्राहक नए कनेक्शन के लिए इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड काल दे सकते हैं। देशभर में रिफिल बुकिंग और चुनिंदा क्षेत्रों में नए कनेक्शन के लिए मिस्ड काल सुविधा को इससे पहले इस वर्ष जनवरी में लांच किया गया था।

वैद्य ने ग्राहकों को उनके घर पर ही डबल बाटल कनेक्शन (डीबीसी) का लाभ उठाने की सुविधा भी शुरू की। इस पहल के तहत डिलीवरी कर्मियों द्वारा ही सिंगल बाटल कनेक्शन (एसबीसी) को डीबीसी में बदला जा सकेगा। इसके तहत ग्राहक बैक-अप के रूप में पांच किलो वाला सिलेंडर ले सकते हैं।

खाद्य तेलों में बनना होगा आत्मनिर्भर : मोदी

प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपये की लागत से आयल पाम मिशन शुरू करने का एलान किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की नौवीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को दाल और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पाम मिशन की घोषणा की। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।

नई दिल्ली में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की नौवीं किस्त जारी करने के मौके पर संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी • प्रेट्र

पीएम-किसान योजना की किस्त जारी, 9.75 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना की नई किस्त जारी करते हुए 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये जमा कराए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पीएम-किसान योजना इस दिशा में सफल और सार्थक सिद्ध हुई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों के प्रमुख लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर उनके अनुभव बांटे। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई जाती है। अब तक इस योजना में 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों में बांटी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत पहली बार कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंच गया है। उसकी पहचान अब एक कृषि निर्यातक देश की बन रही है। किसानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'कृषि को समृद्ध करने में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका रही है। किसानों और सरकार की साझेदारी के कारण देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन गेहूं, चावल और चीनी की आत्मनिर्भरता देश के लिए काफी नहीं है। हमें दाल और खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा।' प्रधानमंत्री ने किसानों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारे किसान दाल की तरह खाद्य तेलों उत्पादन के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों तक दालों का आयात करना पड़ता था। लेकिन उनकी एक अपील के बाद इस क्षेत्र में स्थिति बदल गई। पिछले छह वर्षों में दाल के उत्पादन में लगभग 50 फीसद की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दाल के मामले में किया वही संकल्प अब हमें खाद्य तेलों के उत्पादन में लेना है। इसके लिए तेजी से काम करना है ताकि देश इसमें भी आत्मनिर्भर बन सके। वर्ष 2025-26 तक देश में पाम आयल का उत्पादन तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। पाम आयल की तरह पारंपरिक तिलहन की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, यह उचित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े तंत्र पर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर प्रौद्योगिकी और अन्य सभी सुविधाएं मिलें।'

उल्लेखनीय है कि भारत में सालाना 93 लाख टन पाम आयल की खपत होती है। इसका सर्वाधिक हिस्सा मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है।

कोरोना-पूर्व स्तर पर पहुंची कारोबारी गतिविधि

08 अगस्त को समाप्त सप्ताह में कारोबारी सूचकांक 99.4 के स्तर पर

आवाजाही से लेकर बिजली खपत, श्रमिकों की भागीदारी जैसी कई आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के घटते मामलों एवं टीकाकरण में तेजी की वजह से आर्थिक गतिविधियों में लगातार विस्तार जारी है। नोमुरा इंडियन बिजनेस रिजंप्शन इंडेक्स (एनआइबीआरआइ) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आठ अगस्त को खत्म सप्ताह में कारोबारी सूचकांक तेजी से बढ़त लेते हुए 99.4 के स्तर पर पहुंच गया, जो ठीक पिछले सप्ताह के आखिर में 94 था। आठ अगस्त को खत्म सप्ताह में आवाजाही से लेकर बिजली खपत, श्रमिकों की भागीदारी जैसी कई आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई।

एनआइबीआरआइ के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह के बाद का कारोबारी सूचकांक कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के मुकाबले आगे निकल चुका है। इस वर्ष फरवरी मध्य में कारोबारी सूचकांक 99.3 के स्तर पर था। एनआइबीआरआइ के मुताबिक बिजली की खपत आर्थिक गतिविधियों की बढ़ोतरी के प्रमुख संकेतक में से एक है। आठ अगस्त को खत्म सप्ताह में बिजली की खपत पिछले सप्ताह की तुलना में 5.3% बढ़ी। उससे पिछले तीन सप्ताह से बिजली की खपत में गिरावट आ रही थी। वैसे ही, समीक्षाधीन सप्ताह में श्रमिकों की भागीदारी 41.5% रही, जो एक सप्ताह पहले 39.8 फीसद थी।

नोमुरा के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या घटने से कई प्रकार की ढील दी गई है, जिससे सर्विस सेक्टर में तेजी की उम्मीद की जा रही है। वहीं, जुलाई में टीकाकरण की दर प्रतिदिन लगभग 50 लाख रही, जो जून में 39 लाख के आसपास थी। पेट्रोल की खपत पहले से ही कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है।

शेयर बाजार में खुदरा निवेश शीर्ष पर

नई दिल्ली, आइएएनएस: घरेलू शेयर बाजारों में खुदरा निवेश की हिस्सेदारी इस वक्त अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। एक अध्ययन के अनुसार इस वर्ष 30 जून को नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध कंपनियों में खुदरा निवेशकों की कुल रकम 16 फीसद बढ़कर 16.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इस वर्ष 31 मार्च को 13.94 लाख करोड़ रुपये थी। अध्ययन रिपोर्ट में प्राइम डाटाबेस ग्रुप ने कहा कि संख्या के लिहाज से भी खुदरा निवेशकों (दो लाख रुपये तक का निवेश करने वालों) की संख्या अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है।

रिपोर्ट के अनुसार एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में खुदरा निवेशकों की संख्या इस वर्ष 31 मार्च को 6.96 फीसद थी, जो 30 जून को बढ़कर 7.18 फीसद हो गई। इसी अवधि (अप्रैल-जून, 2021) में बीएसई-सेंसेक्स 6.01 फीसद और एनएसई-निफ्टी 7.02 फीसद बढ़े हैं। प्राइम डाटाबेस ग्रुप के एमडी प्रणव हल्दिया ने कहा कि शेयर बाजारों की तेजी और पिछले कुछ समय के दौरान एक के बाद एक नई सूचीबद्धता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से खुदरा निवेशकों का बड़ा हिस्सा शेयर बाजारों को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार दो लाख रुपये से अधिक निवेश करने वाले हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) की हिस्सेदारी भी एनएसई में पंजीकृत कंपनियों में कुल निवेश के 2.10 फीसद पर पहुंच गई है।

16.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई खुदरा निवेशकों की रकम

7.18 फीसद पर पहुंच गई जून के अंत में खुदरा निवेशकों की संख्या

चुनिंदा शेयरों में निवेश से बाजारों में तेजी

मुंबई, प्रेट्र : फाइनेंशियल व आइटी शेयरों में खरीदारी के दम पर घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तेजी देखी गई। दिन के कारोबार में बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 125.13 अंकों यानी 0.23% उछाल के साथ 54,402.85 पर स्थिर हुआ। एनएसई का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी सोमवार को 20.05 अंक यानी 0.12% सुधरकर 16,258.25 पर बंद हुआ।

चीन में बढ़ रहे आर्थिक जोखिम से भारत को लाभ

राजीव कुमार • नई दिल्ली

भारतीय बाजार में विदेशी निवेश के साथ घरेलू निर्यात भी बढ़ेगा, चीन में बढ़ रही महंगाई, घट रहा निर्यात

चीन इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर चौतरफा दबाव झेल रहा है और इसका फायदा भारत को मिल सकता है। शेयर बाजार में यह रुझान दिखने लगा है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त के शुरुआती पांच दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 1,210 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की बिगड़ती आर्थिक हालत को देखते हुए निवेशक भारत को प्राथमिकता देने लगे हैं।

यूबीएस ग्रुप एजी ने कहा, चीन के नए बाजार नियामक से नाखुश निवेशक अन्य उभरते बाजार में निवेश की संभावना तलाश रहे हैं और भारत को अधिक महत्व दिया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि प्रमुख सूचकांक सर्वकालिक उच्च स्तर के आसपास हैं और कई स्टार्ट-अप कंपनियों के आइपीओ कतार में हैं। चालू संसद सत्र में कई आर्थिक बिल की मंजूरी से भी भारतीय बाजार को मजबूती मिल रही है। दूसरी तरफ चीन इन दिनों भारी महंगाई से जूझ रहा है। वहां महंगाई दर नौ फीसद पर पहुंच गई है जो पिछले 18 माह के अधिकतम स्तर पर है। घरेलू खपत घटी है, निर्यात कम करने पर विचार किया जा रहा है। जुलाई में चीन का निर्यात घटकर 19.3% रह गया जो जून में 32% रहा था। इसका फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलेगा।

अमेजन-फ्लिपकार्ट के खिलाफ जारी रहेगी जांच, कोर्ट ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी आनलाइन दिग्गज अमेजन इंक तथा वालमार्ट की सहयोगी फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-रोधी जांच रोकने का दोनों कंपनियों का आग्रह ठुकरा दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इसके विपरीत दोनों कंपनियों से कहा है कि उन जैसी बड़ी कंपनियों को तो इस तरह की जांच को बढ़ावा देना और इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को जांच में शामिल होने और सीसीआइ को अपना पक्ष सौंपने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है और स्पष्ट किया है कि इस मामले में कंपनियों को और वक्त नहीं दिया जाएगा।

दोनों कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा एंटी-ट्रस्ट जांच चलाने के खिलाफ कर्नाटक

हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। हाई कोर्ट यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थीं कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से यह उम्मीद करती है कि वे खुद स्वयं को जांच के लिए पेश करेंगी। लेकिन यहां तो दोनों कंपनियां ही जांच में शामिल नहीं होना चाहती हैं। इन कंपनियों को जांच में शामिल होना ही होगा। पीठ ने कहा, उसे कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता है।

अमेजन व कैटामरन ने करार खत्म किया: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ देर बाद अमेजन व इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति की कंपनी कैटामरन ने प्राईवन बिजनेस सर्विसेज नामक संयुक्त उपक्रम को खत्म करने की घोषणा कर दी। करार मई, 2022 तक था और कंपनियों ने कहा है उसके बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। प्राईवन बिजनेस सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा क्लाउडटेल को अमेजन डाट इन पर बड़े विक्रेताओं में गिना जाता है।

राष्ट्रीय फलक

110 रुपये शुल्क नहीं देने पर विवाह रजिस्ट्रेशन में देरी

कोच्चि, प्रेट्र : विशेष विवाह अधिनियम के तहत नोटिस के साथ 110 रुपये के अपेक्षित शुल्क का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण एक अंतरधार्मिक जोड़े के विवाह के रजिस्ट्रेशन में देरी हो गई। इसके चलते लड़की का सऊदी अरब जाने का कार्यक्रम टल गया, जहां वह नर्स के रूप में काम करती है। इस जोड़े को केरल हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन या विधि सम्मत कार्रवाई तब तक नहीं होगी, जब तक कि अपेक्षित शुल्क के साथ नोटिस नहीं दिया जाए। इस जोड़े ने शुरू में 11 जून को विवाह अधिकारी को विवाह के लिए नोटिस दिया था। लेकिन इसके साथ उन्होंने शुल्क नहीं दिया था। जोड़े की ओर से हाई कोर्ट में पेश हुए वकील आर राजेश ने बताया कि कुछ हफ्ते बाद ही उन दोनों को अहसास हुआ कि केरल विशेष विवाह नियम, 1958 के तहत आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसके चलते उनके नोटिस को प्रकाशित नहीं किया गया।

चूंकि उन्होंने नौ जुलाई को शुल्क का भुगतान किया, इसलिए अब नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिनों के बाद ही रजिस्ट्रेशन संभव है। यानी विवाह का रजिस्ट्रेशन पांच अगस्त से पहले नहीं किया जा सकता था, जबकि उसी दिन लड़की को सऊदी अरब जाना था। विवाह अधिकारी पांच अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन से इन्कार कर रहे थे। इसलिए जोड़े ने हाई कोर्ट का रुख किया। लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

महिला को अपने होने वाले पति के लिए वीजा पाने की खातिर विवाह प्रमाणपत्र जरूरी है, ताकि वह उसके साथ सऊदी अरब जा सके।

आरोपित जांच से जुड़े दस्तावेज देखने का हकदार : दिल्ली हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए अहम टिप्पणी की कि जांच एजेंसी आरोपित पर भरोसा करे या न करे, लेकिन जांच के दौरान एजेंसी द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों का मुआयना करने का उसे हक है। वहीं, सीबीआइ द्वारा पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर संबंधित अधिकारियों से राय लेने का समय दिया जाए। इस पर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही प्रकरण में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर

- आइएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
- निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक की समयसीमा बढ़ाई

लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। सीबीआइ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम के दस्तावेज का निरीक्षण करने के संबंध में निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित किए गए सभी दस्तावेजों को मांगने या देखने का आरोपित अधिकार रखता है। वह चाहे तो दस्तावेज की मांग कर सकता है।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को ईडी ने मनी-लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआइ द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी, जबकि ईडी मामले में उन्हें चार दिसंबर, 2019 को जमानत मिली थी।

दलितों के खिलाफ टिप्पणी के लिए अभिनेत्री मीरा मिथुन गिरफ्तार

चेन्नई, आइएएनएस : तमिलनाडु पुलिस की साइबर विंग ने माडल और अभिनेत्री मीरा मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इंटरनेट मीडिया के जरिये एक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है जिसमें उन पर अनुसूचित जातियों (एससी) को अपशब्द कहने का आरोप है। बताया जाता है कि तमिलनाडु में दलितों के समर्थक एक राजनीतिक दल विदुथलाई चिरुथगाई काची (वीसीके) की ओर से यह शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पार्टी का नेतृत्व सांसद थोल तिरुमावलन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की साइबर क्राइम पुलिस ने मीरा मिथुन के खिलाफ आइपीसी की सात धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जमात पर एनआइए की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी, पीडीपी बौखलाई

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और उनसे संबंधित संगठनों के कार्यालयों की तलाशी ली। बांडीपोरा में पांच जगहों पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई जमात-ए-इस्लामी द्वारा आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने व युवाओं को भर्ती करने की साजिश के संदर्भ में मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है।

एनआइए ने गत रविवार को कश्मीर के सभी 10 जिलों और जम्मू संभाग के चार जिलों में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों व संगठनों के कार्यालयों समेत 56 जगहों पर छापे मारे थे। इन छापों में हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन लाखों रुपये के लेन देन से संबंधित दस्तावेज और जिहादी साहित्य बरामद किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एनआइए की टीम ने सोमवार को पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दस्ते के साथ उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा में सुबह से लेकर दोपहर बाद तक पांच जगहों पर तलाशी ली। यह सभी मकान और संस्थान जमात-ए-इस्लामी के नेताओं के हैं। जिन मकानों और कार्यालयों की तलाशी ली गई, वहां कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन किसी को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की एनआइए ने देर शाम तक पुष्टि नहीं की थी। उधर, पीडीपी ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी की एक विचारधारा है लेकिन लेकिन केंद्र सरकार अपने विरोधी विचारों को कुचल रही है, जिसके परिणाम नकारात्मक होंगे।

जावेद अख्तर ने कंगना की याचिका खारिज करने का कोर्ट से किया आग्रह

मुंबई, प्रेट्र : गीतकार जावेद अख्तर ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनोट की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। कंगना ने अख्तर की शिकायत पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू की गई आपराधिक मानहानि के मुकदमे को रद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जवाबी हलफनामे में अख्तर ने कहा है कि अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि मुकदमा शुरू करने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। पिछले महीने कंगना ने याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ इस साल के प्रारंभ में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देते हुए कहा था कि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अभिनेत्री ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट स्वतंत्र रूप से उनके खिलाफ शिकायत या उसमें नामित गवाहों का परीक्षण नहीं कर सकता। अख्तर ने इसी मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ पिछले साल नवंबर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ आधारहीन व छवि को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणी की। दिसंबर में अदालत ने जुहू पुलिस को कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू करते हुए फरवरी में अभिनेत्री को नोटिस जारी किया था।

नवाब खानदान की संपत्ति में सीलिंग की जमीन, मामला कोर्ट में

जासं, रामपुर : नवाब खानदान की संपत्ति में सीलिंग की जमीन भी शामिल है। सरकारी वकील ने जिला जज की अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात कही। कोर्ट इस मामले में फैसला करेगी। मंगलवार को भी अदालत में सुनवाई होगी। रामपुर में नवाब खानदान की 2,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। उन्होंने बंटवारे के लिए विभाजन योजना भी पेश कर दी है। प्तमाम पक्षकार आपत्ति दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई।

छह माह पहले तक समझौते के प्रयास करते रहे बैंक अफसर

जागरण संवाददाता, कानपुर

- कोरोना के कारण कंपनी के प्रबंध निदेशक नहीं गए दिल्ली, अफसर आते थे कानपुर
- कई बार वार्ता के बावजूद बात नहीं बनने पर बैंक पहुंचे सीबीआइ के पास

श्रीलक्ष्मी काटसिन कंपनी के 6833 करोड़ रुपये के बकायेदारी मामले में बैंक अंतिम समय तक मामले में समझौते का प्रयास करते रहे। अभी छह माह पहले तक कई बैंक के अधिकारी दिल्ली से कानपुर आकर कंपनी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के साथ बैठकें करते रहे, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो आखिर में बैंक सीबीआइ के पास गए।

श्रीलक्ष्मी काटसिन के बैंक खाते 2013 के करीब ही एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) होने लगे थे। इसके बाद भी आठ वर्षों तक बैंकों की अपनी कवायद चलती रही। पिछले तीन वर्ष में यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई।

श्रीलक्ष्मी काटसिन के लोन दिल्ली के बैंक कार्यालयों से जारी हुए थे। इसलिए 2019 तक तो कंपनी के प्रबंधन के लोग दिल्ली जाकर वार्ता करते रहे, लेकिन 2020 से चेयरमैन व प्रबंध निदेशक माता प्रसाद अग्रवाल ने कोरोना की आड़ लेकर दिल्ली जाकर बात करने से इन्कार कर दिया। बैंक अफसरों पर इसके लिए कितना दबाव था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तब बैंकों के अफसरों ने दिल्ली से आकर कानपुर में ही बैठकें शुरू कर दीं, लेकिन जब उसका भी कोई असर नहीं हुआ तो जून, 2021 में सीबीआइ को तहरीर दी गई।

निदेशकों और गारंटर की क्षमता से ज्यादा दिया गया लोन : कंपनी के निदेशकों और गारंटरों ने कागजात में हेराफेरी कर अपनी क्षमता से कहीं अधिक लोन ले लिया।

यह आरोप अब सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के डीजीएम राजीव खुराना ने भी अपनी रिपोर्ट में लगाया है। इससे सवाल खड़ा होता है कि उस समय बैंक अफसरों ने क्या जांच की थी, इस मामले में कोई ज्यादा नहीं बोल रहा है। बैंक अधिकारियों को भी डर था कि मामला किसी दूसरी जांच एजेंसी के पास गया तो वह फंस सकते हैं। बैंक अफसर बताते हैं, इसी वजह से अंतिम समय तक आपसी समझौते के प्रयास किए गए।

अविनाश भोसले मनी लांड्रिंग मामले में चार करोड़ की जमीन जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पुणे स्थित कारोबारी अविनाश भोसले के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के तहत चार करोड़ रुपये की जमीन जब्त की गई है। जांच एजेंसी ने कहा है, 'जब्त संपत्ति जमीन है जहां एबीआइएल (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) का कारपोरेट कार्यालय एवं अन्य समूह कंपनियां स्थित हैं। अविनाश भोसले एबीआइएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर हैं।' यह जमीन पुणे के गणेशखिंड रोड पर यशवंत गाडगे नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, रांगे हिल कार्नर में प्लाट नंबर दो है। जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमीन जब्त करने के लिए प्रोविजनल आदेश जारी किया है। भोसले के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामला सिटी पुलिस की एफआइआर पर आधारित है। इसमें आरोप है कि रंजित मोहिते द्वारा एआरए प्रोपर्टीज को मूल आवंटन शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि स्थानांतरित की गई थी। ईडी ने कहा है, '1951 में आवंटन के समय सरकार द्वारा तय शर्त के अनुसार, भूमि केवल सरकार या कमीशंड अधिकारी को स्थानांतरित की जा सकती थी।'

नए आइटी नियम बेरहम, रोक लगाने की मांग

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाईकोर्ट में दायर याचिका में इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी रूल्स (आइटी नियम), 2021 को अस्पष्ट और बेरहम बताते हुए रद करने की मांग की है।

यह याचिका लीफलेट नाम के डिजिटल न्यूज पोर्टल और पत्रकार निखिल वागले ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नए आइटी नियम प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले हैं, जबकि देश का संविधान इन दोनों तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लीफलेट की ओर से हाईकोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ से आग्रह किया कि नए आइटी नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए।

क्षमा से बड़ा दान कोई दूसरा नहीं

पड़ोस में प्रताड़ित हिंदू

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में एक हिंदू मंदिर पर हमले की खबर के बाद बांग्लादेश के खुलना जिले में चार हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाना यही बताता है कि इन दोनों पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के लिए जीना कितना दूभर हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले की खबरें नई नहीं हैं। इन दोनों देशों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। चिंता की बात यह है कि इस तरह की खबरें आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। भले ही पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोपितों की धरपकड़ की जा रही हो, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि जिन तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाया, उनकी पैरवी करने वाले सामने आ गए हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के मामलों में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती। यही कारण है पाकिस्तान के बचे-खुचे हिंदू खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। इस पर गौर करें कि रहीम यार खान जिले के जिस इलाके में मंदिर पर हमला किया गया, उसके आसपास के हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। पता नहीं वे पलायन कर कहां जाएंगे, लेकिन हर किसी को इससे अवगत होना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू किसी न किसी बहाने भारत आना पसंद करते हैं। वे वहां रहे तो या तो सताए जाएंगे या फिर मतांतरण के लिए मजबूर किए जाएंगे।

पाकिस्तान के हिंदू केवल दोयम दर्जे के नागरिक ही नहीं बन गए हैं। उनके लिए सम्मान के साथ जीना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को अगवा कर उनका निकाह किसी मुस्लिम के साथ कराना अब आम हो गया है। निःसंदेह बांग्लादेश में पाकिस्तान सरीखा धार्मिक अतिवाद नहीं, लेकिन वहां के भी हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं। वास्तव में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नागरिकता कानून में संशोधन कर यह प्रविधान करना कितना जरूरी हो गया था कि इन दोनों देशों के साथ अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। उचित यह होगा कि इस कानून में ऐसे भी प्रविधान किए जाएं, जिससे इन तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को और अधिक उदारता से नागरिकता देने का रास्ता साफ हो सके। इसी के साथ इस कानून के विरोधी न केवल खुद को आईने में देखें, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा पर भी गौर करें।

उम्मीद जगाते कदम

योगी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसका असर दिखने लगा है। राज्य सरकार पांच साल में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चार लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने जा रही है। इस दौरान 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक कुल 1000 करोड़ रुपये का निवेश इस सेक्टर में आ चुका है। इलेक्ट्रानिक्स का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ही उप्र इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 सामने आ चुकी है। इसके तहत कहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए कहीं मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है तो कहीं सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना। यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रानिक सिटी ही बसाने की योजना है तो बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ये सब ऐसे कदम हैं जो आने वाले वर्षों में उप्र की तस्वीर बदल देंगे। कुछ वर्ष पहले तक प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को यहां उचित सम्मान नहीं मिल पाता था। प्रदेश औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ा था कि शिक्षित या कुशल युवाओं को अन्य राज्यों की राह पकड़नी पड़ती थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इस स्थिति में सुधार आया है। जल्द ही इसकी और भी ज्यादा खुशनुमा तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल अगले साल ही प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन योजनाएं पांच वर्ष की बन रही हैं। इसका अर्थ यही है कि सरकार पूरी तरह आशान्वित है कि उसने जो शुरुआत की है, उसे रोक पाना अब किसी के लिए भी मुश्किल है। औद्योगिक विकास का जो खाका खींच दिया गया है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकेगा। निश्चित रूप से अब समय आ चुका है जब युवाओं को उनका हक देना ही होगा। प्रदेश की प्रतिभा को प्रदेश में ही खपाने के हर जतन करने होंगे। सरकार यही कर रही है। यह तो समय ही बताएगा कि वह भविष्य में अपने मकसद में कितना कामयाब होती है।

> अब समय आ चुका है जब युवाओं को उनका हक देना ही होगा। प्रदेश की प्रतिभा को प्रदेश में ही खपाने के हर जतन करने होंगे

कब होगी कश्मीरी पंडितों की वापसी

बलबीर पुंज

> जिस अलगाववाद और कट्टरता को कश्मीर में दशकों से खाद-पानी दिया गया, उसका खात्मा एक या दो वर्ष में संभव नहीं

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए की विदाई के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक साक्षात्कार सुर्खियों में रहा। उसमें उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार के इस ऐतिहासिक कदम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दो वर्ष बीत जाने के बाद कितने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी हो पाई है? निःसंदेह उनका घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी से कोई सरोकार नहीं है। वह तो अप्रत्यक्ष रूप से उस विभाजनकारी राजनीति को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने 90 वर्ष पहले की थी। कालांतर में उसी राजनीतिक दृष्टिकोण को उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और अन्य मानसबंधुओं ने आगे बढ़ाया। मुफ्ती परिवार को भी इसी में गिना जा सकता है।

तीन दशक पहले कश्मीरी पंडितों पर हुआ अत्याचार और परिणामस्वरूप उनका सामूहिक निर्वासन कोई स्वतंत्र घटना या अपवाद नहीं है। इसका बीजारोपण 14वीं शताब्दी में तब हुआ, जब कश्यप मुनि की तपोभूमि और शैव-बौद्ध मत के प्रमुख केंद्रों में से एक इस क्षेत्र का इस्लामीकरण प्रारंभ हुआ। कालांतर में इसे 'काफिर-कुफ्र' की अवधारणा से सींचा गया। बौद्ध राजकुमार रिंचन इस्लामी मतांतरण के पहले शिकार बने। फिर कश्मीर से हिंदुओं को पलायन के लिए बाध्य किया गया। मस्जिदों से भारत और हिंदुओं की मौत की दुआ मांगी गई। मजहबी नारों से माहौल गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने आतंकियों की ढाल बनकर सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाए। सिनेमाघरों पर ताले लग गए। स्कूलों को जलाया गया। निजाम-ए-मुस्तफा यानी शरीयत कानून की जोरदार पैरवी हुई। इस क्षेत्र में यह सब औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामी शासक के दौर में भी असंभव था। उसे शेख अब्दुल्ला ने 1931 में सेक्युलरवाद की आड़ में संभव कर दिखाया। शेख अब्दुल्ला को इसमें तत्कालीन भारतीय नेतृत्व के वरदहस्त और पाकिस्तान को जन्म देने वाली विभाजनकारी सोच से पूरा सहयोग मिला। इसी परिपाटी को शेख के अनुचरों ने आगे जारी रखा। अब 370 और 35ए की बहाली की मांग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

क्या 90 वर्ष पहले कश्मीर की स्थिति इतनी विषाक्त थी? महाराजा हरी सिंह के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा. कर्ण सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, '9 मार्च 1931 को जब उनका जन्म हुआ, तब श्रीनगर में उत्सव का माहौल था।' यह स्पष्ट सूचक था कि तब रियासत में सद्भाव था। महाराजा हरी सिंह स्वयं किसी सामान्य हिंदू की भांति मजहबी स्वतंत्रता, बहुलतावाद और भेदभाव रहित लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे। यह समरस स्थिति तब बिगड़ी, जब उसी वर्ष मुहम्मद शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर वापस घाटी लौटे। उन्होंने 21 जून 1931 को खानकाह-ए-मौला मस्जिद से अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज किया। शेख के भड़काऊ भाषणों ने उन्हें कश्मीर का बड़ा नेता बना दिया। महाराजा हरी सिंह के विरुद्ध मजहबी आंदोलन के लिए उन्होंने मुस्लिम शोषण और कथित सामंतवाद को आधार बनाया। यह विचित्र भी था, क्योंकि शेख ने अपनी आत्मकथा 'आतिश-ए-चिनार' में स्वयं स्वीकार किया था कि 'महाराजा (हरी सिंह) सदैव ही मजहबी विद्वेष से ऊपर थे और अपने कई मुस्लिम दरबारियों के निकट थे।'

अवधेश राजपूत

शेख को 'शेरे कश्मीर' भी कहा जाता है। वह कितने बहादुर थे, इसका पता 26 सितंबर, 1947 को महाराजा हरी सिंह को लिखे उनके पत्र से लग जाता है। उस समय शेख जेल में थे। तब उन्होंने महाराजा और राज्य के प्रति अपनी पार्टी की निष्ठा प्रकट करते हुए लिखा था कि कश्मीर के प्रशासन को अनुकरणीय बनाने के लिए वह अपना सहयोग देने के लिए हमेशा महाराजा के साथ हैं। शेख ने महाराजा, सिंहासन और डोगरा राजवंश के प्रति स्वामिभक्ति की लिखित में कसमें भी खाईं। इसके बाद महाराजा ने सभी राजनीतिक कैदियों को क्षमादान दे दिया। इसमें शेख भी छूट गए, परंतु जैसे ही जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो बाजी एकदम पलट गई। तब शेख ने पं. नेहरू से मिलकर महाराजा हरी सिंह को उनकी ही रियासत से बेदखल करा दिया। महाराजा को मुंबई जाकर शरण लेनी पड़ी। शेख ने नेहरू की मेहरबानी से जम्मू-कश्मीर की कमान संभाल ली। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत से विलग करने का कुचक्र रचना शुरू कर दिया। यह घटनाक्रम शेख के वास्तविक चरित्र को ही रेखांकित करता है।

यह सत्य नहीं है कि जिस संधि के तहत जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उसमें अनु. 370 और धारा 35-ए एक महत्वपूर्ण शर्त थी। वास्तव में महाराजा ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर के समय कोई विशेषाधिकार नहीं मांगा। यह तो वायसराय लार्ड माउंटबेटन की कुटिलता, शेख अब्दुल्ला के मजहबी मंसूबों और पं. नेहरू की अदूरदर्शिता का परिणाम था। इसकी परिणति 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में अनु. 370 और 14 मई 1954 को धारा 35-ए के जुड़ाव के रूप में हुई। हालांकि यह व्यवस्था अस्थायी ही की गई थी।

यदि कश्मीर को हिंदू विहीन करने वाली जिहादी मानसिकता को समझना है तो हमें अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा किए कबाइली आक्रमण में लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह से जुड़े हृदयविदारक घटनाक्रम को समझना होगा। नारायण सिंह महाराजा हरी सिंह की रियासती सेना में 4जेएके के कमांडिंग अधिकारी थे। उनकी कंपनी में हिंदू-मुस्लिम सैनिकों की संख्या लगभग बराबर थी। एक दिन रात के अंधेरे में लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह और अन्य हिंदू अधिकारियों की हत्या करके सभी मुस्लिम सैनिक शत्रुओं से जा मिले। वे हथियार भी लूट ले गए।

स्पष्ट है कि जिस अलगाववाद, कट्टरता और घृणा को यहां दशकों से खाद-पानी मिला है, उसकी समाप्ति एक या दो वर्ष में संभव नहीं। इस भूखंड के मूल निवासी और स्थानीय संस्कृति के ध्वजवाहक कश्मीरी पंडितों की वापसी यहां तभी संभव है, जब घाटी को विषाक्त मजहबी माहौल मे मुक्ति मिले। अनु. 370 और धारा 35 ए की विदाई इसी दिशा में एक ठोस पहल है। ऐसे में इस कदम से तात्कालिक परिणाम चाहने वालों को अनावश्यक सवाल उठाने के बजाय आवश्यक और अनुकूल परिवेश बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्या अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवार से इसमें किसी सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

खेल संस्कृति को संवारने का समय

जगमोहन सिंह राजपूत

> हर उस जिले को खेल जिला घोषित कर देना चाहिए, जहां से एक भी ओलिंपिक खिलाड़ी टोक्यो गया हो

टोक्यो ओलिंपिक का सफल समापन हो गया और भारतीय ओलिंपिक दल वापस आ गया। देश में उसका भव्य स्वागत हो रहा है। देखा जाए तो यह ओलिंपिक भारत के लिए कई मायने में अद्भुत रहा। इसमें भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस बार हमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक मिले। टोक्यो ओलिंपिक भारत में खेल संस्कृति के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नीरज चोपड़ा के रूप में एथलेटिक्स में पहली बार भारत का कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता है। नीरज की सफलता स्वर्णिम है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक सफलता के साथ यह न भूलें कि हाकी ने भी अपना पुराना गौरव हासिल कर लिया है। पुरुष हाकी टीम के कांस्य पदक जीतते ही हर देशवासी का चेहरा खिल गया। देश में एक उत्सव का माहौल बन गया। मैं ऐसा कोई और अवसर या समारोह याद नहीं कर पा रहा हूं जिसमें सभी एक साथ एक 'प्राप्ति' के लिए अभूतपूर्व भाईचारे की भावना से एकजुट हुए हों। दुनिया में शायद ही किसी देश में कांस्य पदक पाने की खुशी पूर्ण भागीदारी, अपनत्व और हार्दिकता से जश्न में परिवर्तित की गई होगी। भारत की महिला हाकी टीम ने भी जिस दृढ़ता, साहस और प्रयास की एकाग्रता से मुकाबला किया, वह हृदयस्पर्शी था। इसके बाद भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जैसे ही स्वर्ण पदक जीता पूरा देश झूम उठा। आज सारा देश नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहाई, पीवी सिंधू, रवि दाहिया, बजरंग पूनिया की चर्चा कर रहा है। ये खिलाड़ी इसके पात्र भी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार जाने वाली टीमों/खिलाड़ियों को भी बधाई दी। शायद ही कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। हर भारतीय को यह अच्छा लगा है। आगे से खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाने का फैसला भी सराहनीय है। देश में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों की कहानियां न सुनी हों। इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे ध्यानचंद स्वयं को हाकी का भक्त मानते थे। दुनिया उन्हें हाकी का जादूगर कहती थी। 1936 में फ्रांस के विरुद्ध सेमीफाइनल भारत ने 10-0 से जीता था, जिसमें चार गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। फाइनल मैच 15 अगस्त, 1936 के दिन था। पहले हाफ में भारत कोई गोल नहीं कर सका, मगर दूसरे में वह 8-1 से जीता। दर्शकों में हिटलर भी था। हिटलर ने ध्यानचंद से ही यह जानकर कि वह भारत की सेना में हैं, उन्हें जर्मन सेना में बहुत ऊंचा पद देने की पेशकश की, जिसे हाकी के जादूगर ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। 1928 में अपने पहले ओलिंपिक में ध्यानचंद ने 14 गोल दाग कर सारे विश्व का ध्यान खींचा था। 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार छह स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 1956 में पाकिस्तान को हराना भी शामिल था। हालांकि 1960 में फाइनल में भारत पाकिस्तान से एक गोल से पराजित हो गया था, मगर 1964 में उसने पाकिस्तान को हराकर फिर स्वर्ण जीता।

भारतीय हाकी के पुनर्जन्म का साक्षी बना ओलिंपिक। फाइल

वह दौर भारत में हाकी का स्वर्णिम काल था। तब हाकी का गोल्ड मेडल भारत के लिए आरक्षित माना जाता था। आज इस पर चर्चा का समय नहीं है कि क्यों भारत की हाकी नेपथ्य में चली गई या यूं कहें कि कैसे उसे अंधेरे कोने में धकेल दिया गया? सामान्य रूप से लोग कारण भी जानते हैं। उन्हें भी जानते हैं, जो हाकी के मैदान के बाहर अपने-अपने खेल खेलते हैं। इस पर राष्ट्रव्यापी बहस होनी ही चाहिए कि उन लोगों को खेलों से बाहर कैसे रखा जाए, जो स्वयं न कभी खेले हों, न खेलों के लिए कुछ किया हो, मगर केवल सुख-सुविधा और उगाही के लिए ही किसी न किसी पद को हथियाकर पूरी व्यवस्था पर कब्जा जमा लेते रहे हैं। कुछ वर्षों पहले क्रिकेट में जो उठापटक हुई, वह अशोभनीय थी, मगर आज क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष एक नामी-गिरामी खिलाड़ी है। ऐसा हर खेल में होना चाहिए।

ओलिंपिक खिलाड़ियों को हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन जो करोड़ों की बरसात कुछ मुख्यमंत्री सरकारी खजाने से कर रहे हैं, साथ में प्लाट और नौकरी भी दे रहे हैं, वे न तो खिलाड़ियों के साथ न्याय कर रहे हैं, न ही खेलों के साथ। खिलाड़ी का सम्मान कीजिए, मगर यह न भूलें कि सरकारी खजाने का पैसा आपका नहीं है। उनका भी है, जो राशन की दुकानों पर दशकों से लाइन में लगे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री शहंशाह नहीं है। खेल रत्न अवार्ड की राशि 25 लाख रुपये है। इससे अधिक राशि किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस ओलिंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के उन कष्टों के बारे में भी जाना है, जो उन्होंने उठाए हैं। ऐसे में सभी मुख्यमंत्रियों को घोषणा करनी चाहिए कि उसके प्रांत में हर सरकारी स्कूल में खेल के सामान की कोई कमी नहीं होगी। हर स्कूल को कोच की व्यवस्था सप्ताह में कम से कम दो दिन उपलब्ध होगी। हर होनहार खिलाड़ी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हें आवासीय विद्यालयों में पढ़ने के साथ उनकी खेल प्रतिभा के विकास की व्यवस्था भी होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी सराहना करना हर भारतवासी का धर्म है। उन्होंने भारतीय हाकी को गर्त से निकाल कर विश्व पटल पर सम्मानपूर्ण स्थान दिला दिया। उन्होंने सरकारी पैसे का निवेश सोच-समझकर किया, देशहित में किया। उनमें कहीं कोई राजनीति या स्वार्थ नहीं दिखाई दिया।

देश में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए हर उस जिले को खेल जिला घोषित कर देना चाहिए, जहां से एक भी खिलाड़ी टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने के लिए गया हो। वहां एक खेल स्कूल की स्थापना भी की जानी चाहिए। सभी मुख्यमंत्रियों को नवीन पटनायक की तरह खेलों में निवेश की उपयोगिता को समझना चाहिए।

(लेखक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पुरुषार्थ का दीया

जो लोग नाउम्मीदी एवं निराशा में ज्यादा जीते हैं, वे हमेशा समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। वहीं पुरुषार्थ करने वाले समस्यामुक्त जीवन जीते हैं। ऐसे लोग दुनिया के लिए आदर्श एवं प्रेरणास्रोत बन जाते हैं। हालांकि बहुत बार हम अपने पुरुषार्थ के प्रति संदिग्ध हो जाते हैं। हमारे संदेह हमको गुमराह कर जाते हैं। यह असफलता और निरर्थक जीवन का कारण बनता है। यह अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है।

ज्यादातर लोग एक बेचैनी हर समय अपने साथ लिए फिरते हैं। यह फिक्र अपने बारे में नहीं, दूसरों से जुड़ी होती है। उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं? कैसे रहना चाहिए आदि? लेखक पाउलो कोएलो कहते हैं, 'हर व्यक्ति यह साफ-साफ सोच पाता है कि दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। बस उन्हें अपनी ही जिंदगी का पता नहीं होता।' ऐसे लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि पैर का कांटा निकालने तक ठहरने से ही व्यक्ति पिछड़ जाते हैं। प्रतिक्षण और प्रति अवसर का यह महत्व जिसने भी नजरअंदाज किया, उसने उपलब्धि को दूर कर दिया। नियति एक बार एक ही क्षण देती है और दूसरा क्षण देने से पहले उसे वापस ले लेती है।

वर्तमान भविष्य से नहीं, अतीत में किए गए पुरुषार्थ से बनता है। समाज और राष्ट्र को नया परिवेश देने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। इसके लिए हमें व्यापक सोच विकसित करना होगा। हम केवल घर को ही देखते रहेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे और केवल बाहर को देखते रहेंगे तो टूट जाएंगे। मकान की नींव देखे बिना मंजिलें बना लेना खतरनाक है, पर अगर नींव मजबूत है और फिर मंजिल नहीं बनाते तो यह अकर्मण्यता है। स्वयं का विकास और समाज का भी विकास, यही समष्टिवाद है। यही धर्म है। निजीवाद कभी धर्म नहीं रहा। जीवन वही सार्थक है, जो समष्टिवाद से प्रेरित है। केवल अपना उपकार ही नहीं, परोपकार भी करना है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है।

ललित गर्ग

जैविक ईंधन की ओर अग्रसर दुनिया

अरविंद जयतिलक

> अगर जैविक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता है तो इससे ईंधन की कीमतें घटेंगी और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा

जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह सुखद है कि दुनिया जैविक ईंधन की ओर तेजी से अग्रसर है। इससे भी अच्छी बात यह है कि विकसित देशों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने तय किया है कि कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन को वातावरण में कम करने के लिए कोयले की परियोजनाओं से दूर रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष कोप-23 नाम के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जैविक ईंधन के इस्तेमाल के लिए भारत समेत दुनिया के 19 देशों ने अपनी सहमति की मुहर लगाई थी। उस सम्मेलन में विकसित देशों ने एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में कोयले से बिजली निर्माण बंद करने की शपथ ली थी। जीवाश्म ईंधन में कोयले से विश्व की तकरीबन 40 प्रतिशत बिजली का निर्माण होता है। डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल ने भविष्यवाणी की थी कि अगली सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजन जैविक ईंधन से चलेंगे और इसी में दुनिया का भला भी है। इसलिए और भी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संबंधी संगठन के सालाना ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन में कार्बन उत्सर्जन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीते साल धरती के वायुमंडल में जिस रफ्तार से कार्बन डाईआक्साइड गैस जमा हुई उतनी पिछले लाखों वर्षों के दौरान नहीं देखी गई। कार्बन उत्सर्जन का यह दर समुद्र तल में 20 मीटर और तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस इजाफा करने में सक्षम है।

इसको रोकने के लिए जैविक ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन है। भारत में जैविक ईंधन की वर्तमान उपलब्धता तकरीबन 120-150 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, जो कृषि और वानिकी अवशेषों से उत्पादित है। जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं, जो मृत पेड़-पौधे और जानवरों के अवशेषों से तैयार हुआ, जबकि जैव ईंधन उसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर विद्यमान वनस्पति को रासायनिक प्रक्रिया से गुजारकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने के रस को अल्कोहल में बदलकर उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। या मक्का के दानों में खमीर उठाकर उससे ईंधन तैयार किया जाता है। इसके अलावा जट्रोपा, सोयाबीन और चुकंदर इत्यादि से भी ईंधन तैयार किया जाता है। अच्छी बात यह है कि जैविक ईंधन कार्बन डाईआक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को स्वच्छ रखता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इससे ईंधन की कीमतें घटेंगी और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। भारत में कृषि क्षेत्र को जैविक ईंधन के उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो किसानों का भी भला होगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को 11 सितंबर, 2008 को मंजूरी दी जा चुकी है। इसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अंधविरोध से ग्रस्त विपक्ष

'कमजोर धुरी पर टिकी विपक्षी एकता' शीर्षक से लिखे आलेख में आशुतोष झा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेतृत्व विहीन विपक्षी एकता का जैसा सटीक विश्लेषण किया है, वह अपनी जगह दुरुस्त है। वस्तुतः विभिन्न विपक्षी दलों के बीच जहां एक ओर मजबूत धुरी के रूप में सक्षम नेतृत्व का अभाव है वहीं विकासशील भारत की लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए एक सर्वस्वीकार्य नेता भी विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में यदि बात तीसरी बार बंगाल विजय करने वाली टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की करें तो उनके दल की हैसियत केवल एक क्षेत्रीय दल की है, जिसके कारण सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टियां उनके नेतृत्व को सहज रूप से स्वीकार कर पाएंगी, इसमें संदेह है। इसके बाद यदि राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को विपक्षी एकता की कमान सौंपे जाने पर विचार किया जाता है तो कांग्रेस के पास अभी स्वयं का ही कोई मजबूत अध्यक्ष नहीं है तो फिर विपक्षी एकता की कमान भला कौन संभालेगा? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास योग्य नेताओं का अभाव हो, लेकिन नेहरू-गांधी परिवार यह कभी नहीं चाहेगा कि उससे इतर कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व करे। अब ले-देकर बचते हैं राहुल गांधी, जिनकी राजनीतिक समझ जगजाहिर है। अंधविरोध में वह किस सीमा तक क्या बोल दें कुछ कहा नहीं जा सकता। राफेल विमान सौदे पर अपनी भद पिटाने वाले राहुल गांधी आजकल संसद में बिना सुबूत के कथित पेगासस जासूसी मुद्दे को जोर-शोर से उछाल कर विपक्षी दलों के बीच हीरो बनने की कवायद में लगे हुए हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस शोर-शराबे के बीच बहुत ही शालीनता के साथ अपना काम पूरा कर रहा है। मानसून सत्र में संसद के हंगामे के बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए हैं। निःसंदेह यह मोदी सरकार की कुशलता और सूझ-बूझ का परिचायक है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन जब विपक्ष राष्ट्रीय महत्व के नीतिगत मुद्दों से परे हटकर केवल देश के प्रधानमंत्री को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दे तो इसका फायदा सत्ता पक्ष को ही मिलेगा। महत्वपूर्ण मानसून सत्र को विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ता देख देश की जनता हैरान है। जब विपक्ष को महंगाई, कोरोना महामारी, नई शिक्षा नीति, अफगान संकट और सुलगते गुलाम कश्मीर के मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष के साथ सार्थक चर्चा करनी चाहिए थी तब वह कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को निरस्त करने जैसे आधारहीन मुद्दों को लेकर संसद के अंदर और बाहर व्यर्थ का हंगामा काटे हुए है। विपक्ष का यह रवैया देशहित में नहीं है। बावजूद इसके अंध मोदी विरोध से ग्रस्त विपक्ष अब अपने ही बुने जाल में फंसकर फड़फड़ाने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा है।

डा. वीपी पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़

कामयाब सफर

टोक्यो ओलिंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अपना पूरा दमखम दिखाया और एक स्वर्ण, दो रजत, और चार कांस्य के साथ कुल सात पदक जीते। टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय टीम देशवासियों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय टीम ओलिंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसा हुआ भी, टीम ने कमाल का खेल दिखाया और खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। बेशक इस बार ओलिंपिक में हमारे गोली (निशानेबाजी) और तीर (तीरदांजी) न चले, लेकिन हाकी टीम (पुरुष और महिला) ने पूरे देश का दिल जीत लिया। पुरुष हाकी टीम ने ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता तथा महिला हाकी टीम पहली बार ओलिंपिक में चौथे स्थान पर रही। कुश्ती, बाक्सिंग, बैडमिंटन में भारत ने अपना दबदबा दिखाया, वहीं पहली बार ओलिंपिक में अदिति गोल्फ में बेहतर करके भी अद्वितीय प्रदर्शन से चूक गईं। भारत ने अपने 121 साल के ओलिंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इस तरह 13 साल बाद भारत ने ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

ओलिंपिक

टोक्यो में नए भारत का उदय

बीजिंग में अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतना सनसनीखेज था, लेकिन नीरज चोपड़ा के जेवलिन ने भरोसे की वह नींव रखी है जो खिलाड़ियों को एक पाठ के रूप में पढ़ाई जाएगी। यह वही टर्निंग प्वाइंट है जो क्रिकेट के मामले में लंदन में 1983 में आया था। इस ओलिंपिक में हुए कमाल ने कोविड महामारी से उपजी हताशा पर भी कुछ मरहम लगा दिया

मनीष तिवारी
manishtiwari@nda.jagran.com

नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में ओलिंपिक गोल्ड मेडल भारत के लिए गेम चेंजर है। टोक्यो में सात पदक हमारे देश को खेलों में शक्ति के रूप में नहीं दिखाते, लेकिन यह महसूस किया जा सकता है कि हम उस रेखा के काफी करीब आ गए हैं जो औसत और विलक्षण को विभाजित करती है। 23 जून, 1983 को लार्ड्स में गार्डन ग्रीनिज ने अगर बलविंदर सिंह संधू को हल्के में लेने की गलती नहीं की होती तो शायद न हम इस स्टेडियम की बालकनी में कपिल देव और उनके खिलाड़ियों को विश्वकप ट्राफी लिए देखते और न ही आज भारत की क्रिकेट टीम पावर हाउस के रूप में नजर आती। ओलिंपिक खेलों के लिहाज से टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में पिछले शनिवार को शाम सवा पांच बजे का वक्त उसी परिवर्तन की आहट लेकर आया है। बीजिंग में अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतना सनसनीखेज था, पर नीरज चोपड़ा के जेवलिन ने भरोसे की वह नींव रखी है जो खिलाड़ियों को एक पाठ के रूप में पढ़ाई जाएगी। यह वही टर्निंग प्वाइंट है जिसका इंतजार था।

क्या बदला, क्या बदलेगा : रियो में हुए पिछले खेलों में भारत की तरफ से केवल 20 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल और उससे आगे प्रवेश किया था, जिनमें पुरुष हाकी टीम भी शामिल थी। इसके मुकाबले टोक्यो में 55 खिलाड़ियों का इस स्तर तक पहुंचना बताता है कि हमारे खिलाड़ियों की पदक के पास जाने की क्षमता बढ़ी है। कम से कम दस ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें भारत का प्रदर्शन विश्वस्तरीय रहा। यह व्यापकता गौर करने लायक है। इसका सरल मतलब है कि हमने इन खेलों में ओलिंपिक के लिए न केवल क्वालीफाई किया, बल्कि अपनी उपस्थिति भी महसूस कराई। सात पदक इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन इससे भी ऊपर लड़ने की क्षमता अधिक प्रभावशाली है। सुधार और क्षमता में वृद्धि सबसे अधिक हाकी में आनंद और राहत पहुंचाने वाली है। पतन को कोसते 35 साल बीते। एस्ट्रो टर्फ की तेजी के मुकाबले भारतीयों का धीमापन सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आया था और यह दलील इतनी घिस-पिट गई थी कि उससे इतर कुछ सोचा ही नहीं जा सका। इसके साथ ही कुछ चिर-परिचित कमियां भी गिनाई जाती थीं, जैसे पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलने की क्षमता का अभाव और आखिरी मिनट में गोल खा जाने की प्रवृत्ति। इन कमियों को दूर करने के लिए कोचों की लाइन लगा दी गई। आधा दर्जन तो केवल आस्ट्रेलिया से आए। इसके नतीजे पिछले चार-पांच साल में आए हैं। सुधार का सिलसिला फिटनेस के स्तर से शुरू हुआ। कुछ साल पहले सरदार सिंह की टीम को दुनिया में सबसे फिट टीम माना गया। संदीप सिंह और जुगराज सिंह के बाद कई ड्रैग फ्लिकरों ने बाजी ही पलट दी। टोक्यो में पुरुष टीम आस्ट्रेलिया वाले मैच को छोड़कर पूरे अधिकार के साथ खेलती नजर आई, जबकि महिलाओं ने लड़ने की अपनी क्षमता के कारण ध्यान खींचा। उन्हें भी कांस्य पदक मिल जाता तो यह लगभग परफेक्ट फिनिश माना जाता। जो भी हो, हाकी टीम ने भावनात्मक रूप से देश को बहुत कुछ दिया है। हाकी फिर से ताकतवर हो सकती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी भी हैं और अभी कायम भी हैं।

पहले दिन का कमाल : पहले के ओलिंपिक में यह इंतजार करते-करते कई दिन बीत जाते थे कि पदक तालिका में भारत का नाम कब आएगा। अक्सर यह इंतजार खेल के आखिरी दिनों में पूरा होता था। इन खेलों में केवल एक पदक का लंबा रिकार्ड है। फिर दो या तीन मेडल भी आए। लंदन ओलिंपिक में यह सिलसिला टूटा, जब देश को छह पदक मिले। टोक्यो में जब इवेंट के पहले ही दिन मीरा बाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिला दिया तो पूरा देश इससे चमक उठा। उम्मीदें बढ़ गईं। अगले 15 दिन लोगों ने टीवी के सामने बिताए। शूटिंग और तीरंदाजी में एक के बाद एक निराशा हाथ लगती गई, लेकिन भरोसा बना रहा। शूटिंग ने सबसे अधिक निराश किया-इतना कि जांच की जरूरत महसूस हो रही है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और उनके पति अतानु दास चैंपियन होकर भी बड़े आयोजनों में बिखर जाते हैं, यह टोक्यो में भी साबित हुआ। इसे सिर्फ इस तथ्य से समझिए कि मिश्रित युगल में टीम को ओलिंपिक के बीच में अतानु दास की जगह प्रवीण जाधव को उतारना पड़ा, जो बेहतर फार्म में थे। इन दो स्पर्धाओं में उम्मीदें टूटने के बावजूद कोई भी खेल प्रेमी न तो श्रीलंका की ओर मुड़ा जहां भारत की एक और नेशनल क्रिकेट टीम सफेद गेंद की सीरीज खेल रही थी और न ही उसने इंग्लैंड की तरफ देखा, जहां विराट कोहली एंड कंपनी एक अहम टेस्ट सीरीज के लिए है। वीरेंद्र सहवाग इसे क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखते हैं। उनका निष्कर्ष कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन घरों और जगह-जगह आफिस में लगे टीवी के सामने लोग जिस तरह बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा की जीत पर उछले, पीवी सिंधू, लवलीना के लिए तालियां बजाईं और हाकी टीम की जीत पर झूमे उससे उनके मनोभावों को समझा जा सकता है। इन्होंने ही युवा गोल्फर अदिति अशोक का दुख भी हल्का कर दिया, जो मात्र एक स्ट्रोक से इस इवेंट में पदक हासिल करने से वंचित रह गईं। गोल्फ में मेडल आता तो बहुत बड़ी बात होती। कबड्डी से लेकर क्रिकेट तक को यह देश अच्छे से जानता है, लेकिन गोल्फ खेलना तो दूर, उसके नियम-कायदों से भी लोग ज्यादा परिचित नहीं हैं। यह ध्यान देने लायक है कि इस खेल में भी हमने दोनों वर्गों में भाग लिया। शायद पेरिस में कोई अदिति टोक्यो की कसर पूरी कर देगी। गोल्फ में जो अदिति ने किया वही काम तलवारबाजी में भवानी देवी ने किया। वह इस स्पर्धा में उतरने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उन्होंने भी वह सब कर दिया जो उन्हें रोल माडल बना सकता है।

पृष्ठभूमि भी देखिए : ओलिंपिक के हमारे हीरो अपने-अपने प्रदर्शन के साथ-साथ और भी बहुत कुछ सामने लाए हैं। जिनके खेल की चर्चा घर-घर में हुई उनकी कहानी भी बार-बार सुनाने लायक है। मीरा बाई चानू को अपने घर के लिए ईंधन की व्यवस्था में लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती थीं, नीरज चोपड़ा मोटापा कम करने की कोशिश में संयोग से जेवलिन थ्रोअर बन गए, हरियाणा के हर पहलवान का सफर फिल्मी स्क्रिप्ट वाला है, किसी के घर में बिजली-पानी नहीं है तो कोई खेत से सीधे मैट पर पहुंच गया, लवलीना किक बाक्सर बनना चाहती थीं, रेस वाक में गए एथलीट के पिता बकरियां चराते थे। यह भारत है, यही उभर रहा है, यही जीतेगा भी।

कुछ क्षण खुशी के : ओलिंपिक में हुए कमाल ने कोविड से जन्मी हताशा पर कुछ मरहम लगा दिया। टोक्यो में नीरज चोपड़ा के थ्रो से लहराए तिरंगे ने आशा और खुशी की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। कई दशक बाद लोग इन दिनों को इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जब महामारी ने जिंदगी को और सियासत ने संसद को बांध दिया था तब हमारे एथलीटों ने बताया था कि देश को उत्साहित कैसे किया जाता है। पेरिस गेम्स इससे भी अच्छे हो सकते हैं। फिलहाल आप इंग्लैंड में क्रिकेट देखिए।

भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से आह्लादित खेल प्रेमी अलहदा अंदाज में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए। एएनआइ

खेल प्रतिभाओं को मिले प्रोत्साहन

अतुल कनक

टोक्यो ओलिंपिक के दौरान भारतीयों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब नीरज चोपड़ा ने अपनी साधना, प्रतिभा और प्रतिबद्धता के दम पर भाला फेंक प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। ओलिंपिक मुकाबले आसान नहीं होते। उनमें विजेता होना किसी भी देश के लिए उत्सव की बात होती है। पदक से चूक गई मेरी काम और महिला हाकी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी उत्सवी माहौल में सराहा गया है। हर उपलब्धि और हर बेहतर प्रदर्शन को सराहा ही जाना चाहिए।

भारत इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकता है कि टोक्यो ओलिंपिक से हमारी झोली में अब तक के सबसे ज्यादा पदक आए हैं। एक स्वर्ण और दो रजत सहित भारतीय खिलाड़ियों ने कुल सात पदक जीते हैं और पदक तालिका में इस बार भारत का स्थान 48वां रहा है। पहली बार भारत टाप 50 देशों की सूची में शामिल हुआ है। अदिति अशोक, भारतीय महिला हाकी टीम, विनेश फोगाट हालांकि पदक नहीं जीत सकीं, लेकिन इनके प्रदर्शन ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मनु भाकर की पिस्टल का लीवर खराब हो जाने के कारण उनका फाइनल का सफर अधूरा रह गया। यानी टोक्यो ओलिंपिक में यह तो साबित हो ही गया है कि हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा की चमक दुनिया को दिखाने की प्रतिबद्धता की राह पर हैं और यही प्रतिबद्धता प्रदर्शन को पदक में परिवर्तित करती है।

लेकिन बिना किसी पूर्वाग्रह के सोचें तो यह सवाल असहज प्रतीत नहीं होता कि आखिर 135 करोड़ की आबादी वाला देश ओलिंपिक के प्रदर्शन में छोटे छोटे देशों से भी पीछे क्यों रह जाता है। यह कहानी आज की नहीं है। इस बार तो हमने अपने ओलिंपिक इतिहास के सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, वरना कई ओलिंपिक मुकाबले तो ऐसे भी हुए हैं, जब हमारे खिलाड़ी और उनके साथ गए हुए अधिकारी खाली हाथ लौटे हैं।

हालांकि हाकी में ओलिंपिक में हमारा प्रदर्शन पिछली सदी के आठवें दशक तक बेहतर रहा है। वर्ष 1920 से 1980 के बीच हुए 12 ओलिंपिक में भारत ने 11 बार कोई न कोई पदक अपने नाम किया था। इसके बाद भारतीय हाकी टीम की ओलिंपिक उपलब्धियों में जो सन्नाटा पसरा, वह टोक्यो में टूटा है। यह 41 साल का सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। हम सफलता पर खिलाड़ियों के यशगान में कमी नहीं रखते, लेकिन कठिन क्षणों में उनकी मदद के लिए भी तैयार नहीं रहते। खेल छात्रावासों में कुछ लोगों की मनमानी और बेहद दयनीय दशा में रह रहे खिलाड़ियों की तस्वीरें जब-तब समाचार-पत्रों में छपती रहती हैं। बाजार ने सफलता के ग्लैमर को इस तरह थाम लिया है कि कुछ बड़े नामों को छोड़कर शेष सब अपनी आजीविका के लिए या तो संघर्ष करने पर विवश हैं या फिर खेल को छोड़कर किसी और क्षेत्र में अपने करियर को तलाशते हैं।

निश्चित रूप से इस बार हमारे खिलाड़ियों ने ओलिंपिक के हमारे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और भविष्य के लिए उम्मीदें भी जगाई हैं। लेकिन खेलों के संवर्धन और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार खेल संघों, अधिकारियों, सरकारों और कारपोरेट घरानों को भी प्रतिभाओं को संवारने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

उफ! ये 'शो' वाले शोक संदेश

राजेंद्र देवधरे 'दर्पण'

शोक संदेश तेजी से अपना ट्रेंड बदल रहे हैं। अब वे मृत्यु की सूचना न होकर शक्ति प्रदर्शन का हथियार हो गए हैं। एक भरे-पूरे परिवार का चित्ताकर्षक शोक संदेश : अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी एवं राधेश्याम (डिप्टी कलेक्टर), सुरेश (प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय), दिनेश (संयुक्त संचालक आइडीसीएस), बीना (मुख्य कार्यपालन अधिकारी), टीना (निदेशक, नर्मदा शोध संस्थान), मीना (डाक्टर, जिला चिकित्सालय) की पूज्य माताजी, संगीता (अध्यक्ष, वूमन वेलफेयर ग्रुप), सुनीता (सचिव, अनाथ कन्या कल्याण समिति), रानी (उपाध्यक्ष, विनोबा वृद्ध आश्रम), मनीष जी (डीएसपी), रमेश जी (सीएमओ), बलवीर जी (लेबर इंस्पेक्टर एफआइसी) की प्यारी सासू मां, सखाराम (सेवानिवृत्त विभाग प्रमुख स्वास्थ्य), देवकीनंदन (से. नि. सहायक संचालक) की भाभी, राखी, सविता, सरला (फाउंडर मेंबर, इंसान बचाओ ट्रस्ट) की जेठानी, सीतारामजी (रिटा. जिला मजिस्ट्रेट), गंगाराम जी (से. नि. उपसंचालक, शिक्षा विभाग) की छोटी बहन, सलोनी (फिल्ड आफिसर, एलआइसी), मयंक (इंजीनियर), शुभम, (डाक्टर), करिश्मा (पंचायत सचिव), रागिनी (नायब तहसीलदार) की दादीजी, मनीषा (साफ्टवेयर इंजीनियर), विनोद (प्रोफेसर) की नानी जी, प्रतिभा (सब इंस्पेक्टर), प्रवीण कुमार (एडवोकेट) की दादी सास, राकेश जी (प्रोबेशनरी अधिकारी, एसबीआइ), सतीश जी (टीसी, पश्चिम रेलवे), महेश जी (इंस्पेक्टर, सीआइडी) रीना (कैशियर, पीएनबी), रूपा (आबकारी उपनिरीक्षक), स्नेहलता (लेखिका) की नानी सास का देवलोकगमन हो गया है। जिनका उठावना एकादशी को श्री बांकेबिहारी रिसोर्ट्स (निज होटल) पर शाम चार बजे निर्धारित किया गया है।

इतना सब देख-सुनकर बेचारी दादी की आत्मा भी सोच रही होगी कि ये शोक संदेश है या 'शो' संदेश! ईश्वर को प्यारी दादी अपने प्यारों की हरकत से कन्फ्यूज हो जाएंगी कि ये भले लोग मेरी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं या स्वयं की?

ट्वीट-ट्वीट

ओलिंपिक पदक विजेताओं को प्रदर्शनकारी किसानों का बेटा बताने वालों ने इन खिलाड़ियों के किसान पिता से जाकर पूछा है कि क्या वे कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं या विरोध? अगर नहीं तो फिर अहंकारी और अपने एजेंडे से प्रेरित लोग क्यों उनकी ओर से अपनी बात कहते फिर रहे हैं?
मोनिका@TrulyMonica

भारतीय खिलाड़ियों की ओलिंपिक में ऐतिहासिक जीत के समय भी जो लोग नफरत का एजेंडा फैलाने में लगे हैं, उन्हें नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि ये निकृष्ट लोग अपने ही बनाए कीचड़ के गड्ढे में धंसे हुए हैं।
मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

टोक्यो ओलिंपिक की अंतिम पदक तालिका यही दर्शाती है कि जर्मनी और रूस जैसे मजबूत देश भी एथलेटिक्स में केवल एक-एक स्वर्ण पदक ही जीत पाए। वहीं ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों को तो एथलेटिक्स में एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

कई बार दशकों के दौरान कुछ नहीं घटित होता, लेकिन हफ्तों में ही बहुत कुछ घट जाता है। ओलिंपिक में गुजरा एक सप्ताह कुछ ऐसा ही रहा।
वसीम जाफर@WasimJaffer14

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या टोक्यो ओलिंपिक के प्रदर्शन से देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित होने की उम्मीद बंधी है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'टोपी जालीदार' को रहे समझते शान,
नापसंद है पर उन्हें कहना अब्बाजान।
कहना अब्बाजान नहीं क्यों उनको भाता,
जब 'एम' का ही वोट काम 'वाई' के आता!
बंधु सियासी लोग सिर्फ सत्ता के लोभी,
नहीं तिलक से प्यार न प्यारी उनको टोपी।
– ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

ममता की जांच आयोग वाली सियासत

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

पिछले माह दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग गठित करने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीशों वाला यह आयोग कुछ दिनों में जांच शुरू करेगा। परंतु अभी से ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इस कथित राजनीतिक जासूसी में आयोग के हाथ कुछ ठोस सबूत लगेंगे या नहीं? इस सवाल की खास वजह है। बंगाल के कई पूर्व नौकरशाहों ने स्पष्ट कहा कि नेताओं की जासूसी व फोन टैपिंग करने का कोई भी आरोप इस राज्य में अब तक साबित नहीं हुआ है। यहां तक कि पूर्व पुलिस महानिदेशक, मुख्य और गृह सचिवों ने भी कहा कि राज्य में समय समय पर राजनीतिक जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी भी बार-बार फोन टैपिंग के आरोप लगाती रही हैं। हालांकि इनमें से एक भी मामला अब तक तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। वर्ष 2011 में बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता ने वाम शासन में फोन टैपिंग के आरोपों की इसी तरह की जांच का आदेश दिया था। परंतु आज तक उनकी फोन टैपिंग से जुड़े एक भी सबूत और न ही आयोग की रिपोर्ट सामने आई।

यही नहीं, पिछले एक दशक में ममता बनर्जी पर भी विपक्षी दलों के नेताओं व पत्रकारों के फोन टैप कराने के आरोप लगते रहे हैं। हाल में तृणमूल में शामिल हुए वरिष्ठ नेता मुकुल राय ने भाजपा में रहते हुए ममता सरकार पर कई बार फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। ऐसे में पेगासस मामले में ममता की जांच आयोग वाली सियासत कितनी सफल होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। पिछले एक दशक से ममता की जांच आयोग वाली सियासत चल रही है, जिसका बड़ा उदाहरण उनके द्वारा अब तक 15 से अधिक जांच आयोग गठित करना है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री बनने के छह साल के भीतर विभिन्न मामलों की जांच के लिए ममता बनर्जी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अलग अलग 13 आयोग गठित किए थे, जिस पर अब तक 33 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में इनमें से केवल तीन ही आयोग की रिपोर्ट पेश हुई है। इन तीन रिपोर्टों में से दो लो-प्रोफाइल खुदकुशी की और तीसरी ममता शासन में हुए आमरी अस्पताल अग्निकांड की है, जिसमें 92 लोगों की जान गई थी। इन तीनों घटनाओं पर आयोग ने जो रिपोर्ट दी, वह पुलिस के पहले के ही निष्कर्षों के अनुरूप थी।

पेगासस प्रकरण की जांच के लिए आयोग की घोषणा के दौरान अपने फोन के कैमरे को कवरकर मीडिया को दिखातीं ममता बनर्जी। फाइल

चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक 2011 में ममता ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद आठ आयोगों का गठन किया था। बाद में उनके शासन के दौरान हुई पांच और घटनाओं की जांच के लिए आयोगों का गठन किया गया। उनके सत्ता में आने से पहले हुई घटनाओं में से पांच हाई-प्रोफाइल मामले थे जिसमें 1971 में कोलकाता के काशीपुर-बरानगर में करीब 150 नक्सलियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों के नरसंहार, 1970 में बर्धमान जिले में कांग्रेस समर्थक सेन परिवार के तीन सदस्यों की हत्या, 1982 में कोलकाता के बिजन सेतु पर 16 आनंद मार्गी साधुओं की हत्या, 21 जुलाई 1993 को ममता के नेतृत्व में राइटर्स अभियान के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत और 1999 में मेदिनीपुर में 23 आदिवासियों की ट्रक से कुचल कर हुई मौत का मामला शामिल था। इन सभी मामलों में आरोप माकपा और कांग्रेस पर लगा था। इसके बाद ममता सरकार के सबसे हाई-प्रोफाइल मामले में सारधा-रोजवैली समेत एक दर्जन से अधिक चिटफंड कंपनियों से जुड़ा घोटाला था, जिसमें तृणमूल के कई नेता-मंत्री मुख्य आरोपित हैं। इनमें से चार जांच आयोगों की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है। चिटफंड घोटाले पर अवकाश प्राप्त जस्टिस श्यामल कुमार सेन आयोग ने 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 21 जुलाई की पुलिस फायरिंग पर जस्टिस सुशांत कुमार चटर्जी आयोग ने 2014 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन अब तक कोई भी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई। काशीपुर-बरानगर नरसंहार पर पूर्व जज डीपी सेनगुप्ता आयोग ने सितंबर, 2017 में रिपोर्ट जमा की थी। पर अब तक सच सामने नहीं आया। इसी तरह आदिवासियों की मौत की एनएन भट्टाचार्जी आयोग की रिपोर्ट 2018 के शुरू में ही सौंपी गई, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार किसी भी आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के छह महीने के भीतर राज्य सरकार को कार्रवाई के साथ पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी होती है। जिस आयोग को वास्तव में कार्यकाल के विस्तार की आवश्यकता थी, वह चिटफंड घोटाले की जांच करने वाला जस्टिस सेन आयोग था, क्योंकि यह जमाकर्ताओं के पैसे लौटा रहा था, लेकिन जिस तरह से इसके विस्तार से इन्कार किया गया और सेन परिवार हत्याकांड तथा बिजन सेतु की घटना पर आयोगों को बार-बार विस्तार दिया जाता रहा, इसे ममता की जांच आयोग वाली सियासत की बानगी ही कहा जा सकता है।

मंथन

मौद्रिक समीक्षा पर महंगाई का साया

सप्लाइ चेन के बाधित रहने और बेरोजगारी दर बढ़ी होने के कारण आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भी नीतिगत दरों में कटौती की संभावना कम है। वैसे शहरी मांग में सुधार होने के बावजूद आगामी कुछ माह महंगाई कम होने की संभावना कम ही है

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के छह सदस्यों ने सामूहिक रूप से नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है। इस तरह, अगली मौद्रिक समीक्षा तक रेपो दर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर साढ़े तीन प्रतिशत पर बना रहेगा। यह लगातार सातवीं बार है, जब एमपीसी ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एमपीसी ने विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से नरम रुख को अपना रखा है। चूंकि अभी महंगाई में निरंतर वृद्धि हो रही है और बाजार में कोरोना महामारी की वजह से उधारी का उठाव भी कम है, इसलिए एमपीसी ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही महंगाई दर में इजाफा होने के बावजूद रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी वैश्विक स्तर पर महंगाई दर में वृद्धि हो रही है। फिर भी, विश्व के अधिकांश देशों में नीतिगत दरों में कटौती नहीं की जा रही है। अमेरिका में फेड दर, जो भारत के रेपो दर के समान है, मार्च 2020 से ही 0.25 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है। ब्रिटेन में भी वहां का रेपो दर जनवरी 2020 में 0.75 प्रतिशत था और अभी भी यह 0.1 प्रतिशत है। इसमें मामूली बढ़ोतरी की गई है। यूरो जोन में वहां का रेपो दर वर्ष 2016 से ही शून्य प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है।

विकसित देशों में भी बेरोजगारी दर कोरोनाकाल से पहले वाली अवस्था में अभी तक नहीं आ सकी है। भारत की तरह विदेशों में भी महंगाई दर में बढ़ोतरी का कारण सप्लाइ चेन का बाधित होना है, जिसका तात्कालिक कारण कोरोना महामारी है। आज भारत के साथ-साथ दुनिया के विकसित देशों में भी महंगाई बढ़ रही है। जून में अमेरिका में महंगाई दर 5.4 प्रतिशत थी, जबकि ब्रिटेन में 0.5 प्रतिशत और यूरो जोन में 1.9 प्रतिशत थी। फिर भी, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इन देशों ने नीतिगत दरों में कोई वृद्धि नहीं की। इन देशों का मानना है कि महंगाई स्थायी रूप से नहीं रहने वाली है। इसके कारक क्षणिक हैं और जल्द ही महंगाई दर में कमी आएगी। वैसे, महंगाई में बढ़ोतरी का कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना भी है। कोर मुद्रास्फीति में तेजी बनी हुई है। इसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति के आकलन में वैसे मदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो किसी अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन के पारंपरिक ढांचे के बाहर हों, जैसे पर्यावरणीय समस्यायों के कारण उत्पादन में होने वाली कमी।

महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण 'बेस इफेक्ट' भी है। दो डाटा बिंदुओं के बीच तुलना के लिए अलग अलग संदर्भ बिंदु चुनने के कारण तुलना के परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव को बेस इफेक्ट कहा जाता है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 21 जुलाई को जारी अपने आर्थिक परिदृश्य में महंगाई का एक कारक बेस इफेक्ट को माना था। मई, 2021 में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 6.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि जून में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 6.26 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। जून में हुई पिछली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीआइ के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था और जुलाई से सितंबर 2021 के दौरान इसके 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। चूंकि पिछली मौद्रिक समीक्षा के दौरान भी महंगाई दर ज्यादा थी, इसलिए उस समय भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

फिलहाल, महंगाई के कम होने के आसार कम हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) के अनुमान को संशोधित कर 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार मई में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी अस्वाभाविक थी, क्योंकि उस समय समग्र मांग में सुधार दिख रहा था, लेकिन तेल और खाद्य वस्तुओं की कीमत ज्यादा होने की वजह से महंगाई दर में कमी नहीं आई।

मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के आलोक में केंद्रीय बैंक ने अप्रैल से जून 2021 तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 21.4 प्रतिशत, जुलाई से सितंबर 2021 के लिए 7.3 प्रतिशत, अक्टूबर से दिसंबर 2021 के लिए 6.3 प्रतिशत और जनवरी से मार्च 2022 के लिए 6.1 प्रतिशत कर दिया है। अभी भी ज्यादातर क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही, कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आने की आशंका को अभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है। पिछले वर्ष से ही कोरोना महामारी का नकारात्मक प्रभाव तमाम देशों में देखा जा रहा है। इसकी वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है और इसमें फिर से जान फूंकने के लिए सभी देशों की सरकारों ने अपनी क्षमता के अनुसार राहत पैकेज की घोषणा की।

अर्थव्यवस्था पर महामारी का असर। प्रतीकात्मक

आने वाले दिनों में शहरी मांग में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी खपत में वृद्धि हो रही है और इसमें सुधार का अनुमान है। हालांकि देश के अनेक राज्यों में आई बाढ़ से फसल और सब्जियां बर्बाद हुई हैं और तेल की कीमतों में भी फिलहाल कमी आने का अनुमान नहीं है। सितंबर से त्योहारों का मौसम भी शुरू हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में आगामी कुछ महीनों तक महंगाई में कमी आने की उम्मीद न्यून है।

50 विशिष्ट महिलाओं में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की चार प्रोफेसर हैं। इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली 50 महिलाओं के संग्रह में शामिल किया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 10 अगस्त, 2021

उत्तराखंड

जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की महत्ता

उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव की आहट महसूस होने लगी है। चुनाव को महज छह-सात महीने ही शेष हैं तो राजनीतिक दलों को एक बार फिर जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे याद आने लगे हैं। विपक्ष स्वाभाविक रूप से ऐसे मुद्दे तलाश कर सत्तापक्ष की घेराबंदी में जुट गया है। लगातार धरने-प्रदर्शन के अलावा बयानों के जरिये आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में भू-कानून की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद कई बार भू-कानून में संशोधन किए गए। इस बार स्थानीय निवासियों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भू-कानून में सख्त प्रविधानों की जरूरत पर सियासी दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं।

मौका चुनाव का है तो अब राजनीतिक दलों को मलिन बस्तियों की भी सुध आने लगी है। मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए आवाज उठाई जा रही है। सत्तापक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ से गरीब तबके के लिए आवास की बात की जाने लगी है। सरकारी कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक होता है तो भला राजनीतिक दलों को उनकी याद चुनाव के मौके पर कैसे न आए। यही वजह है कि उपनल, मनरेगा और अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। महंगाई भत्ते को फिर से बहाल करने की कर्मचारियों की मांग को राजनीतिक दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पर्वतीय जिलों के गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय रहा है। अब एक बार फिर पलायन को लेकर चिंता जताई जा रही है।

> राजनीतिक दल चुनाव से ठीक पहले जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर मुखर हैं। अगर मुद्दों पर गंभीरता शुरुआत से ही होती तो अब तक इनका समाधान निकाल लिया गया होता

राजनीतिक दलों की इस तरह की चिंता जायज है। यह उनका कर्तव्य भी है कि सरकार के सामने जन सरोकार से जुड़े मसलों को उठाएं और इनके समाधान के लिए दबाव डालें, लेकिन इसके साथ ही एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। वह यह कि आखिर ये सभी मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों याद आते हैं। राजनीतिक दल यदि शुरुआत से ही इन मुद्दों पर गंभीर होते तो शायद इनका अभी तक समाधान निकाल लिया गया होता। चुनाव निपटते ही जनता से जुड़े मुद्दे भी पार्श्व में चले जाते हैं। इसे उचित नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के वक्त ही जनभावनाओं के दोहन के लिए खुद को जन हितैषी साबित करने के लिए ऐसा किया जाए। अगर राजनीतिक दल इन मुद्दों पर पूरे पांच साल सक्रियता दिखाएं तो निश्चित रूप से समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनेगा, चाहे सरकार किसी भी दल की हो।

हिमाचल प्रदेश

बेटियों की शिक्षा की पहल

शिक्षा को जीवन जीने का सबसे अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। शिक्षित व्यक्ति निपुणता से नई चीजें सीखने के साथ दुनिया के बारे में जान सकता है। बेटियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही अहम है, जितनी बेटों के लिए। कहा भी गया है कि जब आप एक महिला को शिक्षित करोगे तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। समय बदला है और बेटियों के सपनों को पूरा करने की दिशा में अभिभावक भी आगे आए हैं। बेटियों ने भी यह साबित किया है कि उन्हें सिर्फ मौका मिलना चाहिए, वे अपनी प्रतिभा साबित करने में पीछे नहीं रहेंगी। विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम में बेटियों की उपलब्धि से इसकी झलक देखने को मिलती है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने भी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

यही कारण है कि बेटियां अब परिवार का साथ मिलने से गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन देखने में आया है कि कई बार वित्तीय संकट के कारण बेटियों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई रुकवा दी जाती है। कोरोना काल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई। इनमें वित्तीय संकट के साथ पारिवारिक कारण भी शामिल हैं। ऐसी बेटियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पढ़ाई छोड़ चुकी छात्राएं फिर से स्कूल जा सकेंगी।

जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए पढ़ाई-लिखाई हेतु बेटियों को भी करें प्रेरित। फाइल

> पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान की पहल उनके सपनों को पंख लगाएगी

समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ऐसी छात्राएं एवं ट्रांसजेंडर की पहचान करेगा और उनसे स्कूल छोड़ने का कारण पूछेगा। माता-पिता को बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें फिर से स्कूल पहुंचाया जाएगा। उनकी पढ़ाई फिर शुरू करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इसके लिए शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान की जिम्मेदारी तय कर दी है। निश्चित तौर पर यह पहल बेटियों के सपने पूरे करने में मददगार साबित होगी। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का भी यह दायित्व है कि वे बेटियों की शिक्षा में बाधा न बनें, बल्कि उन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करें।

बिहार

तैयारी के साथ निगरानी जरूरी

बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जल्द तिथियां घोषित हो जाएंगी। छठ पर्व के पहले चुनाव संपन्न करा लेने की कोशिश है। सब कुछ तय हो गया है। बैलेट पेपर तैयार हैं। उन्हें प्रकाशित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। विभिन्न प्रदेशों से ईवीएम मंगा ली गई हैं। उन्हें भी क्षेत्र के अनुसार तैयार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में चुनाव को लेकर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों की पहचान की जा रही है। पिछले चुनावों के अनुभव के आधार पर पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से भी सुरक्षा बलों की जरूरत का आकलन कर रहा है। यह तो सामान्य तैयारियां हैं। बड़ी चुनौती है कोरोना। यह जरूर है कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं। संक्रमित होने वाली संख्या सीमित हो गई है, लेकिन सभी जानते हैं कि खतरा टला नहीं है। जरा सी लापरवाही दूसरी लहर की तरह भारी पड़ सकती है। यह ठीक बात है कि कोरोना के खतरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने का अनुभव प्रशासन को है, जिसका तैयारियां में लाभ मिल रहा है, लेकिन

राज्य में जोर-शोर से चल रही पंचायत चुनाव की तैयारी। प्रतीकात्मक

> पंचायत चुनाव, रक्षा बंधन, दुर्गापूजा से लेकर छठ तक कोरोना संक्रमण रोकने के लिए संवेदनशील रहने की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि होली जैसी गलती हुई तो दिक्कत बढ़ेगी

तैयारियों और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। राज्य चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकाल के पालन को लेकर सतर्क है। वैसे अधिकारियों और कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जो टीका लगवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान यह शिकायत आम हुई थी कि चुनाव की ड्यूटी करने के दौरान पीठासीन अधिकारी और अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित हुए थे। बिहार में ऐसा नहीं हो, इसके लिए पहले से पूरी तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि इन तैयारियों के अनुसार काम होता है कि नहीं।

निगरानी की व्यवस्था भी करनी होगी। पंचायत चुनाव के दौरान अधिकारी, कर्मचारी और मतदाता सख्ती से नियमों के पालन को लेकर सजग रहें, इसकी निगरानी के लिए अलग व्यवस्था बनानी होगी। रक्षाबंधन से लेकर छठ पूजा तक बिहार में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा रहेगा। इसी वर्ष होली के पहले संक्रमितों की संख्या एकदम कम थी। होली के बाद तेजी से बढ़ी।

बंगाल

परिवहन विभाग का फरमान

बंगाल में कोरोना महामारी के चलते कुछ प्रतिबंधों के साथ लाकडाउन अब भी जारी है। लोकल ट्रेनें बंद हैं। रात नौ बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी है। हालांकि इस समय कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई, लेकिन संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। इस समय औसतन सात सौ से आठ सौ के बीच कोरोना के नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, इतने ही मरीजों में लगभग 15 मौतें हर दिन हो रही हैं।

राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी संबंधित आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,701 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 749 लोग कोरोना पाजिटिव पाए गए। एक दिन पहले 728 लोग पाजिटिव मिले थे। इसके मद्देनजर राज्य प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने की बात कही है। दिन में निजी और सरकारी बसों में काफी भीड़ हो रही है, जिसके चलते कोरोना वायरस के फैलने की आशंका काफी रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि 50 फीसद से अधिक यात्रियों को लेकर चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बसों में मौजूदा क्षमता से आधे से अधिक यात्री होंगे तो मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि न केवल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और बसों का परमिट भी रद किया जा सकता है। परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि यह कौन तय करेगा कि बस में पचास फीसद से अधिक यात्री सवार हैं? डीजल-पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वैसे ही बस मालिक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। आधिकारिक तौर पर भले ही बस किराया नहीं बढ़ा हो, लेकिन बसों का न्यूनतम किराया दस रुपये हो चुका है।

> राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बसों में मौजूदा क्षमता से आधे से अधिक यात्री होंगे तो मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

इस बाबत परिवहन मंत्री से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि अधिक किराया लेने पर यात्री बस टिकट के साथ थाने में शिकायत कर सकते हैं। क्या यह भी व्यावहारिक है? न्यूनतम किराया सात रुपये के बदल दस रुपये कंडक्टर ने लिया है तो क्या यात्री अपना काम-धंधा छोड़कर तीन रुपये के लिए थाने में जाकर शिकायत करेंगे?

इस समस्या का यह ऐसा सुझाव एवं निदान है जिसे व्यावहारिक रूप से अमल में लाना तारे तोड़ने के समान है। इसी तरह यह पचास फीसद यात्री सवार करने के फरमान पर भी अमल आसान नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि फरमान जारी करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाए।

श्रद्धा का महासावन

शिव के विविध रूप

हमारी संस्कृति में शिव के कई रूपों की कल्पना की गई है। वह गूढ़ और समझ से परे यानी ईश्वर हैं, वह मंगलकारी यानी शंभो हैं, वह बहुत नादान यानी भोलेनाथ हैं, वह वेद, शास्त्र और तंत्र के महान गुरु यानी दक्षिणामूर्ति हैं, वह आसानी से माफ कर देने वाले यानी आशुतोष हैं, वह सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव हैं, वह संपूर्ण रूप से स्थिर यानी अचलेश्वर हैं और वह सबसे जादुई नर्तक नटराज भी हैं। जीवन के जितने पहलू हैं, उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। योग संस्कृति में शिव को आदि-गुरु और आदि-योगी माना जाता है। आम तौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, लोग जिसे ईश्वरीय मानते हैं, उसे हमेशा अच्छा दर्शाया जाता है, लेकिन अगर आप शिव पुराण को पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या खराब के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ हैं, वह सबसे बदसूरत हैं और सबसे खूबसूरत भी हैं। वह सबसे अच्छे और सबसे खराब हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं, मगर मदहोश भी। तो शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधी पहलुओं से बनी है। उन्हें सभी गुणों का एक अनोखा मेल माना गया है, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आप जीवन को जान चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या खराब, लेकिन अगर आप इस ईश्वरीय स्वरूप को, जो जीवन के हर पहलू का एक जटिल संगम है, स्वीकार कर सकते हैं, तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी।

सद्गुरु
ईशा फाउंडेशन, कोयंबटूर

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

अब आदिवासियों का सेटेलाइट चैनल, संताली में होगा प्रसारण

प्रदीप सिंह, रांची

- बंगाल में मुख्यालय, पांच से अधिक आदिवासी बहुल राज्यों में विस्तार
- संताली के बाद अन्य जनजातीय भाषाओं में भी होगी लांचिंग

ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति और खेल के मैदान से लेकर ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ रहे जनजातीय समुदाय के लिए एक और अच्छी खबर है।

आदिवासी समुदाय के लिए उनकी अपनी भाषा का पहला सेटेलाइट टीवी चैनल 'ट्राइब टीवी' होगा। इस न्यूज टीवी चैनल का प्रसारण लाइसेंस निर्गत होने के बाद परीक्षण (टेस्ट रन) चल रहा है। 15 दिनों के भीतर यह विभिन्न सेटेलाइट प्लेटफार्म पर दर्शकों के लिए सुलभ होगा। फिलहाल संताली भाषा में इस चैनल को लांच किया गया है। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में इस चैनल का मुख्यालय है, जहां से इसकी तमाम संचालन संबंधी गतिविधियों समेत सीधा प्रसारण होगा। इंफोटेंमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली कल्याणी सोल्वेक्स नामक संस्था इसका संचालन करेगी। चैनल से जुड़े अधिकांश पेशेवर भी जनजातीय समुदाय के हैं। संताली भाषा आदिवासी समुदाय की सबसे प्रचलित और अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है। यह देश की 22 अधिसूचित भाषाओं में एक है। संताली के बाद ट्राइब टीवी की योजना अन्य लोकप्रिय जनजातीय भाषाओं मुंडारी, कुड़ुख में भी टीवी चैनल लांच करने की है। फिलहाल ट्राइब टीवी का फोकस बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार में होगा। इन प्रदेशों में संताली आदिवासियों की बड़ी तादाद है। असम में भी विस्तार करने का लक्ष्य है, जहां झारखंड से गए आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं।

अपनी भाषा में बेहतर सूचनाएं परोसना लक्ष्य : ट्राइब टीवी की अग्रिम कतार में कार्य कर रहे पेशेवरों की टीम ने बेहतर संस्थानों से सूचना एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम करने वाले प्रतिभावान लोगों की टीम बनाई है। बनारस हिंदू विवि के छात्र रहे सुरेंद्र सोरेन संपादकीय टीम को लीड कर रहे हैं। सोरेन पाकुड़ के रहने वाले हैं और विभिन्न मीडिया संस्थानों में उन्हें कार्य करने का अनुभव है। उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों को सेवाएं दी हैं। संताली भाषा पर भी उनकी गहरी पकड़ है। सोरेन ने कहा कि संताली भाषा में टीवी चैनल लांच करना एक अभिनव और चुनौती भरा प्रयोग है। अभी कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, लेकिन पहला सेटेलाइट चैनल होने के कारण मुकाबला मुख्य धारा के चैनलों से होगा। कोशिश होगी कि संताली भाषा में बेहतर समाचार और कार्यक्रम पेश कर अपनी जगह बनाई जाए। सोरेन कहते हैं कि यह गर्व का विषय है कि उन्हें संताली के पहले टीवी चैनल की अग्रिम टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला है।

अब काकोरी कांड नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन

राब्यू, लखनऊ : योगी सरकार उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर भावनात्मक मंथन करने में भी जुटी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काकोरी कांड में से कांड शब्द को हटा दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन की उस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। इसके पीछे सीएम की सोच है कि वह देश की आजादी के संघर्ष की गौरवशाली घटना थी, जबकि कांड से नकारात्मक संदेश जाता है। यह शहीदों का अपमान है। इसी तरह चौरी चौरा कांड को भी अब चौरी चौरा क्रांति कहा और लिखा जाने लगा है।

राष्ट्रपति 29 को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से जाएंगे अयोध्या

जागरण संवाददाता, लखनऊ

एक बार फिर से देश की लग्जरी प्रेसिडेंशियल ट्रेन लखनऊ होकर गुजरेगी। इस बार राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर करेंगे। वह रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा को प्रेसिडेंशियल ट्रेन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रपति का पहले संभावित कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त तक था, लेकिन अब वह 26 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। राष्ट्रपति बीबीएयू और कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगले दिन गोरखपुर जाएंगे। वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति राजभवन में ठहरेंगे। 29 अगस्त को लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वह अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। उनकी प्रेसिडेंशियल ट्रेन दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से लखनऊ आएगी। राष्ट्रपति 29 अगस्त की सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से ट्रेन के प्रेसिडेंशियल सुइट से वह सुबह 9:10 बजे लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति इससे पहले 25 जून को दिल्ली सफदरजंग से कानपुर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ आए थे।

पिता ने पढ़ाई बंद कराई तो बेटी ने छोड़ा घर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पिता ने जब बड़ी बेटी की पढ़ाई बंद करवा दी तो नाराज होकर वह छोटी बहन को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस को सूचना मिलने पर छह दिन बाद ही दोनों को ढूंढकर स्वजन को सौंप दिया गया। बेटी इस शर्त पर घर लौटने को तैयार हुई कि पिता उसकी आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी युवती को अपनी युवा योजना के तहत उनकी पढ़ाई में मदद करने व रोजगार दिलाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया।

> दोनों बहनें सकुशल मिल गई हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी युवा योजना के तहत दोनों बहनों को उनकी पढ़ाई में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
> –मोनिका भारद्वाज, उपायुक्त, अपराध

दिल्ली के उत्तरी द्वारका थाने में तीन अगस्त को दो बहनों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इनमें एक की उम्र 19 व दूसरे की 16 वर्ष है। बड़ी बहन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, जिससे दोनों की लोकेशन की जानकारी नहीं मिल रही थी।

युवती के कमरे को खंगालने पर एक पर्ची मिली, जिसमें एक फोन नंबर मिला। वह नंबर बड़ी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ चुके एक किशोर का था। इससे बात की गई तो उसने बताया कि किशोरी ने एक नए नंबर से काल किया था। सर्विलांस से पता चला कि वह नंबर उत्तराखंड के हरिद्वार का है। उक्त नंबर की लोकेशन कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास मिली। पुलिस टीम वहां पहुंची तो छोटी बहन वहां पर मिली। उसने पूछताछ में बताया कि पिता से मतभेद होने से बड़ी बहन ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह नौकरी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती है। हरिद्वार में उन्हें दो किशोर मिले जो खुद भी नौकरी की तलाश में थे। जब हरिद्वार में नौकरी नहीं मिली तो उक्त किशोरों के साथ वह हरियाणा के झज्जर आ गई। वहां सभी का साथ रहना मुश्किल था ऐसे में बड़ी बहन, छोटी बहन को कश्मीरी गेट छोड़कर वापस झज्जर चली गई थी। पुलिस टीम ने किशोर से बात कर कहा कि उसकी नौकरी एक ट्रैक्टर शोरूम लगवा दी जाएगी। किशोरी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह सिरसा में है और जल्द रोहतक पहुंच जाएगी। सोमवार को वह रोहतक में एक बस में मिल गई। दोनों बहनों को स्वजन को सौंप दिया गया।

पटना हाई कोर्ट के पास बनाया जा रहा वक्फ बोर्ड कार्यालय टूटेगा

राज्य ब्यूरो,पटना

- अदालत के शताब्दी भवन से सटाकर हो रहा था निर्माण, बिहार सरकार को दिया तोड़ने का आदेश

पटना हाई कोर्ट की नई इमारत (शताब्दी भवन) के पास मजार से सटे वक्फ बोर्ड के चार मंजिला कार्यालय को तोड़ने का आदेश अदालत ने बिहार सरकार को दिया है। हाई कोर्ट इस निर्माण को अवैध मानता है। न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। इससे पहले इस इमारत के निर्माण पर रोक लगाते हुए अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या इसके निर्माण को लेकर पटना हाई कोर्ट और पटना नगर निगम से भी अनुमति ली गई थी। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि शताब्दी भवन से सटी मजार के करीब वक्फ बोर्ड का चार मंजिला कार्यालय बन रहा है। कार्यालय के सबसे नीचे मुसाफिरखाना का निर्माण हो रहा। यह भवन तीन तल का है। नई इमारत के निर्माण में किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी।

खंडपीठ ने कहा था कि निर्माण गलत तरीके से किया गया है। बिल्डिंग बायलाज की धारा-21 में स्पष्ट कहा गया है कि विधानसभा, राज्यपाल और हाई कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसर से सटाकर कोई दूसरी इमारत नहीं बनाई जा सकती है। साथ ही ऐसी किसी इमारत की ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। इस साल एक मार्च को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। खंडपीठ ने पूछा था कि आखिर यह कैसी इमारत है और किसकी अनुमति से बनी है? महाधिवक्ता ने बताया कि यह वक्फ बोर्ड कार्यालय का भवन है, जिसे राज्य सरकार की अनुमति के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया गया था। बिहार राज्य निर्माण निगम द्वारा इमारत बनाई जा रही है। खंडपीठ का सवाल था कि क्या इसके निर्माण को लेकर हाई कोर्ट और पटना नगर निगम से भी अनुमति ली गई थी? जवाब में महाधिवक्ता ने कहा था कि राज्य सरकार को इस प्रकार के भवन निर्माण के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तब खंडपीठ ने कहा था कि नवनिर्मित कार्यालय के बीच की दूरी 35-36 फीट और इमारत की ऊंचाई करीब 40-45 फीट है। खंडपीठ ने पूछा था कि क्या हाई कोर्ट की दीवार से सटे शौचालय का निर्माण होना सही है? बिल्डिंग बायलाज में तो इस तरह से निर्माण के लिए अनुमति ही नहीं है। फिर क्यों नहीं सरकार ने वक्फ बोर्ड कार्यालय को विधानसभा के बगल में बनवा लिया? इस तर्क के साथ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया और बाद में सर्वसम्मति से निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने का आदेश दिया।

तट पर लौटा विक्रांत...

भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत (आइएसी) विक्रांत अपनी पहली समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कोच्चि तट पर लौट आया है। परीक्षण के दौरान यह सभी मानकों पर खरा उतरा है। आने वाले समय में इसे और परीक्षणों से होकर गुजरना होगा। प्रेट्र

कोई भी मत संकीर्ण मानसिकता की शिक्षा नहीं देता : हाई कोर्ट

फैसला

- तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को हिंदू धार्मिक विभाग की एक समिति से हटाने की मांग खारिज
- पीठ ने याचिका को बताया 'निहायत शरारतपूर्ण', याचिकाकर्ता पर लगाया पांच साल का प्रतिबंध

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोई भी मत संकीर्ण मानसिकता या दूसरे को चोट पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ अनुदान (एचआर एंड सीई) विभाग की सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी व जस्टिस पीडी आदिकेशवुलु की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पांच साल तक कोई भी जनहित याचिका दाखिल करने से प्रतिबंधित कर दिया। पीठ ने कहा कि धर्म के मामले में पूर्वाग्रह व बदले की भावना को छोड़ना होगा। भारत पंथनिरपेक्ष देश है। इसका संविधान भगवान या संविधान के नाम पर शपथ लेने की इजाजत देता है। पीठ ने कहा, 'कोई भी मत संकीर्ण मानसिकता या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। याचिकाकर्ता की भावनाओं की न तो सराहना की जा सकती है, न ही उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। यह निहायत शरारतपूर्ण याचिका है। प्रार्थना में पूर्वाग्रह निहित है।' वकील एस. श्रीधरन की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि स्टालिन को इस पद पर तब तक नहीं रहना चाहिए, जब तक वह देवी-देवता के सामने हिंदू धर्म पालन की शपथ नहीं ले लेते। इसमें दावा किया गया था कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ अनुदान विभाग की व्यवस्था के अनुरूप उसके सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को पदभार संभालने से पहले देवी-देवताओं के सामने हिंदू धर्म के पालन की शपथ लेनी होती है।

80 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है जो चीन के शिजुआन प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के चलते वहां फंसे हुए थे। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डाझाऊ शहर के रिजर्व में प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ गया है।

तालिबान के हमले तेज, दो और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा

अफगान संकट ▶ सर–ए–पुल और तालोकान से पहले जरंज, शबरगान और कुंदुज पर हो चुका है नियंत्रण

काबुल में एक संपादक की हत्या, दूसरे का हेलमंद से अपहरण

काबुल, एपीः आक्रामक तालिबान अब अफगानिस्तान में तेजी से दबदबा बढ़ा रहा है। तीन दिनों में तीन प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा चुके आंतकियों ने दो और राजधानियों सर-ए-पुल और तखार प्रांत की राजधानी तालोकान को नियंत्रण में ले लिया है। सामंगन के एबक शहर पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। राजधानी काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री को मारने की कोशिश के बाद अब एक रेडियो स्टेशन के संपादक की हत्या कर दी गई जबकि एक संपादक का हेलमंद प्रांत से अपहरण कर लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के दौरान 570 आतंकियों को मारने का दावा किया है।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जे के बाद अब शहरों में भी तालिबान ने तेजी से अपना नियंत्रण किया है। गत दिनों उसने जौजान प्रांत की राजधानी शबरगान, निमरुज की राजधानी जरंज और कुंदुज प्रांत की राजधानी कुंदुज पर कब्जा किया था। अब तालिबान ने सर-ए-पुल पर कब्जा कर लिया है। यहां के प्रांतीय परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी के अनुसार सुरक्षा बलों ने सात दिनों तक प्रतिरोध करने के बाद सर-ए-पुल को तालिबान के हवाले कर दिया है। यहां से सुरक्षा बल पूरी तरह हट गए हैं। कई सरकार समर्थक मिलीशिया कमांडरों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आइएएनएस के अनुसार, आतंकियों ने तखार प्रांत की राजधानी तालोकान पर भी अपने नियंत्रण में ले लिया। यहां जेल पर कब्जा कर लिया और सभी कैदियों को छोड़ दिया। एएनआइ के अनुसार, आतंकियों ने सामंगन प्रांत के एबक शहर पर कब्जा कर लिया है।।

हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में अफगान सेना और तालिबान आतंकी दोनों ही शहर में हैं और पिछले दस दिनों से संघर्ष चल रहा है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने कहा है कि हमारी सेना लश्करगाह को आतंकियों से खाली करा रही हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से आधे प्रांतों की राजधानियों पर कब्जे को लेकर भीषण संघर्ष चल रहा है।

राजधानी काबुल में रहने वाले पाक्तिआ प्रांत के रेडियो स्टेशन घाग के संपादक तूफान उमरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमरी बगराम जिले में जुडिशियल एंड जस्टिस सेंटर के अटार्नी भी थे। इसके अलावा बूस्ट रेडियो स्टेशन के संपादक नियामतुल्लाह हेमत का हेलमंद प्रांत के नावा जिले से अपहरण कर लिया गया। नियामतुल्लाह का अपहरण उनके घर से किया गया है। अभी तक किसी भी संगठन ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली है।

570 तालिबान आतंकी मारने का रक्षा मंत्रालय का दावा

अफगानिस्तान के कुंदुज में कब्जे के बाद शहर के मुख्य चौक पर लहराता तालिबान का झंडा। तालिबान आतंकी व अफगान सुरक्षा बल के बीच हुए संघर्ष के बाद गवर्नर आफिस और पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। एपी

अफगानिस्तान पर कतर में कई देशों की दो महत्वपूर्ण बैठक

आइएएनएस के अनुसार कतर में इस सप्ताह अफगानिस्तान पर दो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही हैं। पहली बैठक में अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला और शांति के लिए नियुक्त राज्य मंत्री सैयद सादात मंसूर नादेरी भाग लेंगे। दूसरी बैठक में अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद और पाकिस्तान, रूस व चीन के राजनयिक भाग लेंगे।

पाकिस्तान से आ रहे हैं आतंकवादी और हथियार

आइएएनएस के अनुसार, अफगानिस्तान सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रमुख अहमद शुजा जमाल ने कहा है कि पाकिस्तान यहां चल रहे युद्ध के लिए अपने आतंकी भेजने के साथ हथियारों भी सप्लाई कर रहा है।

अफगानिस्तान के मामले पर क्षेत्रीय बैठक करेगा पाकिस्तान

प्रेट्र के अनुसार, तालिबान को खुला समर्थन देने वाला पाकिस्तान भी अफगान समस्या पर अपने यहां क्षेत्रीय देशों की बैठक करेगा। पाकिस्तान के एक अधिकारी के अनुसार विदेश मंत्री स्तर की इस बैठक में अफगानिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की शामिल हो सकते हैं।

तालिबान कर रहा कत्लेआम और महिलाओं पर बर्बर अत्याचार

एएनआइ के अनुसार, तालिबान जैसे–जैसे बढ़त बनाकर नए जिलों और शहरों पर कब्जा कर रहा है, उसके बर्बर कानून लागू हो रहे हैं। वह नए स्थानों को कब्जे में कर पहले नागरिकों की हत्या, लूटपाट और महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करता है, फिर अपने जुल्मी कानूनों को थोप देता है। इटली के अखबार इनसाइड ओवर में तालिबानी अत्याचारों के बारे में जानकारी दी गई है। अखबार ने लिखा है कि सबसे ज्यादा बर्बरता का शिकार महिलाएं और मासूम लड़कियां हो रही हैं। तालिबान आतंकियों की बात न मानने पर उनको घोर यातनाएं दी जा रही हैं। अमेरिका की सेना के वहां रहने के दौरान महिलाओं को जो स्वतंत्रता दी गई थी, अब उन पर पाबंदी लगाकर उनका जीवन फिर नरक में तब्दील कर दिया है।

तालिबान बोला, युद्ध विराम नहीं करेंगे, अमेरिका रहे दूर

रायटर के अनुसार, तालिबान ने कहा है कि अफगान सेना के साथ युद्ध विराम पर न तो कोई समझौता हुआ है और न ही इस पर कोई विचार चल रहा है। अलजजीरा टीवी के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने काहिरा में अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वह अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध में कोई हस्तक्षेप न करे।

27 बच्चों की आतंकियों ने की हत्या

रायटर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की देखरेख करने वाली एजेंसी यूनीसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान हिंसा के दौरान अब तक 27 बच्चों की हत्या कर दी गई है। 136 बच्चे घायल हुए हैं।

दोस्तम के घर पर तालिबान का हमला, हथियार लूटे

एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के पूर्व उप–राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल राशिद दोस्तम के जौजान प्रांत के ख्वाजा दू कोह स्थित घर में तालिबान ने तोड़फोड़ की और उनके हथियार लूट लिए। दोस्तम ने हाल ही में कहा था कि उनका मिलीशिया ग्रुप तालिबान का सफाया करेगा।

सैमसंग के मालिक ली को पेरोल पर छोड़ेगा दक्षिण कोरिया

सियोल, एपी : दक्षिण कोरिया इसी शुक्रवार को सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स के अरबपति मालिक ली जेई योंग को पेरोल पर छोड़ देगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में 18 महीने बिताए हैं। ली विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर मेमोरी चिप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स के वाइस चेयरमैन हैं।

दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए बताया कि ली की तीस महीने की सजा में अब केवल एक साल बाकी रह गया है। इस मामले में सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ ऐतिहासिक ढिलाई बरती गई थी और इसीलिए भ्रष्टाचार के इस मामले के खिलाफ जनता में इतना रोष भड़का था कि वह विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए थे।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स के वाइस चेयरमैन ली जेई योंग को ढाई साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 52 साल के योंग को 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गियून-हाय के एक सहयोगी को रिश्वत देने के मामले में दोषी पाया गया था। योंग ने इन आरोपों से इन्कार किया था। उनकी अपील पर एक साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उसने मामले को सियोल के हाईकोर्ट में वापस भेजा, जिसने यह सजा सुनाई।

पाकिस्तान में आठ वर्षीय हिंदू लड़के पर ईशनिंदा का आरोप

▶ एक सप्ताह जेल में रखा, बच्चे के स्वजन सहित दूसरे हिंदू परिवार घर छोड़ भागे

नई दिल्ली, आइएएनएसः पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला एक आठ वर्षीय हिंदू लड़के से जुड़ा है। ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए उसे एक सप्ताह तक जेल में रखा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से डरकर पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में रहने वाले बच्चे के स्वजन सहित दूसरे हिंदू परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं। बच्चे पर मदरसे के पुस्तकालय में बिछी कालीन पर जानबूझकर पेशाब करने का आरोप है। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया था।

अज्ञात स्थान पर छिपे लड़के के एक रिश्तेदार ने ब्रिटिश समाचार पत्र गार्जियन को बताया, 'ना तो बच्चे को ईशनिंदा के आरोपों के बारे में कुछ पता है और ना ही वह यह समझ पा रहा है कि आखिर उसका अपराध क्या है। हम अपनी जान बचाकर किसी तरह भागने में कामयाब रहे। हमें नहीं लगता है कि दोषियों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी।' उधर, एक बच्चे के खिलाफ ईशनिंदा के आरोपों को लेकर कानून के जानकार हैरान हैं।

पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख और सांसद रमेश कुमार ने कहा, 'मंदिर पर हमले और बच्चे के खिलाफ ईशनिंदा के आरोपों ने मुझे झकझोर दिया है। कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने वाले हमले के डर से हिंदू समुदाय के लोग घर छोड़कर चले गए हैं।' मानवाधिकार कार्यकर्ता कपिल देव ने कहा कि बच्चे के खिलाफ आरोपों को तुरंत वापस लिया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बीच रहीम यार खान जिला पुलिस के प्रवक्ता अहमद नवाज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। यह देश में बढ़ती कट्टरता को दर्शाता है। पाकिस्तान में ईशनिंदा में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है।

नीरव मोदी को मिली भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति

लंदन, प्रेट्र : पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित नीरव मोदी को लंदन के हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव को मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में उसे भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। ताकि वहां जाकर भारतीय कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर सके। इसी फैसले के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने डिप्रेशन और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दी है। नीरव के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनका मुवक्किल गंभीर डिप्रेशन में है और वह खुदकुशी कर सकता है। हाई कोर्ट के जज मार्टिन चेंबरलेन को वकीलों ने यह भी बताया कि नीरव को भारत

नीरव मोदी जागरण आर्काइव

ब्रिटिश हाई कोर्ट ने डिप्रेशन और मानवाधिकार को बनाया आधार

प्रत्यर्पित किए जाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। ऐसे में इस बात पर बहस अवश्य होनी चाहिए कि जेल में आत्महत्या को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय हैं या नहीं। नीरव के वकीलों की दलील सुनने के बाद जज चेंबरलेन ने कहा, इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि याचिकाकर्ता का मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। मै ग्राउंड तीन और चार के आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत देता हूं। ग्राउंड तीन और चार यूरोपियन कंवेंशन आफ ह्यूमन राइट्स का अनुच्छेद तीन जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। ब्रिटेन के क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 के अनुच्छेद 91 के तहत भी उसे अपील का अधिकार मिलता है। अब इस मामले में लंदन का हाईकोर्ट ग्राइंड तीन और चार के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने मिलकर पीएनबी के साथ धोखाधड़ी की है। सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक घोटाला और मनी लांड्रिंग के तहत दो मामले दर्ज किए हैं। 2018 में मनी लांड्रिंग मामले में नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया था। नीरव मोदी को 20 मार्च, 2019 में लंदन में गिरफ्तार करने के बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया था। यहां उसे जमानत नहीं दी गई और फिर उसी दिन वैंड्सवर्थ जेल भेज दिया गया। इसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसकी दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। फिलहाल वह लंदन की जेल में बंद है।

भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में चीन ने किया हवाई अड्डे का विस्तार

▶ सैनिकों और हथियारों की त्वरित आपूर्ति के लिए उठाए रणनीतिक कदम

▶ पहले ही शुरू हो चुकी है हाई स्पीड ट्रेन

बीजिंग, प्रेट्रः चीन रणनीतिक कारणों से भारत से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को तेजी से विस्तार दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने के बाद अब उसने तिब्बत के ल्हासा गोंगर हवाई अड्डे को बड़ा विस्तार दे दिया है। इस हवाई अड्डे पर भारी-भरकम व्यवस्थाओं के साथ एक नया टर्मिनल बनाया गया है।

60.3 करोड़ डालर (करीब 4500 करोड़ रुपये) खर्च करके हवाई अड्डे पर 80 हजार मीट्रिक टन कार्गो क्षमता बढ़ाई गई है। यात्रियों की क्षमता भी इस टर्मिनल के बनने से 75 फीसद बढ़ गई है। चीन को हवाई अड्डे के विस्तार से अपनी सेना और हथियारों की त्वरित आपूर्ति में मदद मिलेगी। तिब्बत में ल्हासा गोंगर हवाई अड्डे के साथ ही यहां निंगची, शिगात्से और नगारी हवाई अड्डे भी हैं। ये सभी भारत और नेपाल सीमा के निकट हैं।

अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट होने के कारण तिब्बत में चीन तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। उसने पूर्व में ही ल्हासा से निंगची के लिए हाई स्पीड ट्रेन शुरू कर दी है। भारत की सीमा से लगे शहरों में चीन हवाई, सड़क और रेल परिवहन में तेजी से विस्तार कर रहा है।

चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को तेजी से दे रहा है विस्तार। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार से दक्षिण एशिया के लिए लाजिस्टिक हब बनाने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि तिब्बत में चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। विगत 23 जुलाई को राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी बिना पूर्व घोषणा के तिब्बत का दौरा किया था।

बिलावल का दावा– बलूचिस्तान में अगली सरकार पीपीपी की होगी

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख बिलावल भुट्टो-जरदारी का कहना है कि उनकी पार्टी ही बलूचिस्तान में अगली सरकार बनाएगी।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल ने कहा कि अगली सरकार यहां पीपीपी ही बनाएगी। वही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रांत की सभी मुश्किलों को दूर कर सकती है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान समेत समूचे पाकिस्तान में अगली सरकार बनाने वाली पार्टी पीपीपी ही होगी। साथ ही पीपीपी के जियाला (समर्थक) बलूचिस्तान के अगले सीएम होंगे।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले पांच सालों में बहुत बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। अगर देश में कोई राजनीतिक दल है जो गरीबों के हितों की चिंता करती है तो वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर बलूचिस्तान के लोगों ने पार्टी का समर्थन किया तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। ज्ञात हो, बलूचिस्तान में लोग लंबे समय से सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी। जागरण आर्काइव

'पाक सरकार शाहबाज शरीफ को जेल भेजना चाहती है'

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) का कहना है कि इमरान सरकार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शाहबाज को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता के खिलाफ नए सिरे से जांच बैठाई जाने वाली है। द न्यूज इंटरनेशनल ने सोमवार को पीएमएल–एन के नेता अताउल्ला तरार और आजमा बुखारी के हवाले से बताया कि नेशनल एकाउंटबिल्टी ब्यूरो ने नेशनल एसेंबली के उनके नेता को गिरफ्तार करने की तैयारी की है। वह शाहबाज शरीफ को फिर जेल भेजना चाहते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू की गई है। हालांकि उन्होंने यह चेतावनी दी कि वह किसी भी हालात में पीएमएल–एन नेता की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही भ्रष्टाचार के मामलों में पीएम इमरान खान और एनएबी के चेयरमैन घेरे में होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

दक्षिण पूर्व एशिया में संबंधों को प्रगाढ़ करने ब्रुनेई पहुंचे नौसेना के जहाज

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत नौसेना के जहाज शिवालिक व कदमत रविवार को ब्रुनेई के मुआरा पहुंचे। दोनों जहाजों के पदाधिकारी द्विपक्षीय पेशेवर बातचीत में हिस्सा लेंगे। भारतीय जहाज रायल ब्रुनेई नेवी के साथ साझा अभ्यास भी करेंगे।

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'शिवालिक व कदमत दक्षिण पूर्व एशिया में नौ से 21 अगस्त तक तैनाती के क्रम में ब्रुनेई के मुआरा पहुंच चुके हैं। यहां होने वाला सैन्य अभ्यास दोनों नौसेनाओं की अंतर अभियान क्षमता को बढ़ाने, उत्तम अभ्यास को अपनाने और समुद्री सुरक्षा अभियान के संबंध में समान समझ विकसित करने में मदद करेगा। भारतीय जहाज विस्तृत रेंज के हथियारों से सुसज्जित हैं और वे मल्टी-रोल हेलीकाप्टर का परिवहन कर सकते हैं। ये जहाज युद्धपोत निर्माण की भारत की परिपक्व क्षमता का भी परिचय देंगे।' बयान में कहा गया है कि बंदरगाहों पर होने वाली बातचीत व समुद्री अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के संबंधों को और घनिष्ठ करेंगे।

परमाणु हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि...

जापान के नागासाकी में सोमवार को परमाणु बम गिराए जाने की 76वीं बरसी पर पीस पार्क में आयोजित समारोह में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस तबाही को याद करके पूरा देश शोकमग्न रहा। उल्लेखनीय है अमेरिकी वायुसेना ने छह अगस्त, 1945 को पहले हिरोशिमा पर परमाणु बम 'लिटिल ब्वाय' गिराया गया और उसके तीन दिन बाद नौ अगस्त को नागासाकी शहर पर 'फैट मैन' परमाणु बम गिराया गया। जापान इन हमलों में लगभग ढाई लाख लोगों के मारे जाने का दावा करता रहा है। एपी

न्यूज गैलरी

पोप को लिफाफे में भेजे पिस्टल के तीन कारतूस

रोम : इटली के शहर मिलान में एक लिफाफे में पोप फ्रांसिस को भेजे जा रहे पिस्टल के तीन कारतूसों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के अनुसार मिलान में पार्सल भेजने वाले केंद्र से जानकारी मिलने के बाद इन कारतूसों को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि यह लिफाफा फ्रांस से भेजा गया है। इसमें पता द पोप, वेटिकन सिटी, सेंट पीटर्स स्कवायर लिखा गया है। (रायटर)

फ्रांस में कैथोलिक पादरी की हत्या, हत्यारे ने किया समर्पण

पेरिस : फ्रांस के पश्चिमी क्षेत्र में रवांडा के एक प्रवासी ने एक कैथोलिक पादरी की हत्या कर दी। हत्यारा खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने कैथोलिक पुजारी के शव को वेंडी क्षेत्र से बरामद कर लिया है। पकड़ा गया हत्यारा पूर्व में एक गिरजाघर में आग लगाने का भी दोषी ठहराया जा चुका है। (रायटर)

अमेरिकियों का प्रोफाइल बनाने के लिए चीन ने चुराया डाटा

वाशिंगटन, एएनआइः प्रत्येक अमेरिकी नागरिक का प्रोफाइल तैयार करने के लिए चीन ने देश से पर्याप्त डाटा चोरी किया है। यह जानकारी ट्रंप प्रशासन के दौरान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम करने वाले मैथ्यू पोटिंगर ने पिछले सप्ताह सीनेट की खुफिया समिति को दी।

वाशिंगटन एक्जामिनर के मुताबिक, 'पोटिंगर ने समिति के सदस्यों से कहा कि दूसरे देश के लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना हमेशा से लेनिनवादी शासन की विशेषता रही है। चीन ने जिस तरह से 5जी नेटवर्क समेत डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके इस तरह की जानकारी जुटाई है, वह चौंकाने वाला है।' चीन दुनियाभर के लाखों नागरिकों के बारे में प्रोफाइल तैयार करता है। इसका प्रयोग वह दूसरे देशों को धमकाने व ब्लैकमेल करने में करता है। बीजिंग ने जो डाटा चुराया है, उससे वह ना सिर्फ प्रत्येक अमेरिकी बल्कि बच्चों का भी प्रोफाइल तैयार कर सकता है।

ईरान में हालात बेकाबू, हर दो मिनट में एक मौत

दुबई, रायटर : ईरान में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। यहां हर दो मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आस्ट्रेलिया में डेल्टा वैरिएंट के कारण लाकडाउन को बढ़ा दिया गया है।

ईरान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि सबसे ज्यादा लापरवाही शारीरिक दूरी के नियम का पालन न करने की हो रही है। अब यहां मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हर दो मिनट में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो रही है। मरने वालों की संख्या अब तक 94603 तक पहुंच गयी है। हर दो सेकेंड में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 40808 नए मरीज मिले हैं। इस कारण से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। वैक्सीन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। ईरान की आठ करोड़ तीस लाख की आबादी में अब तक 4 फीसद लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है।

रायटर के अनुसार, आस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण सिडनी से निकलकर अन्य छोटे शहरों और कस्बों में भी फैल रहा है। इसको देखते हुए कुछ छोटे शहरों में लाकडाउन लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार संक्रमण बढ़ने का कारण डेल्टा वैरिएंट है। विक्टोरिया प्रांत में प्रतिबंधों में ढील पर विचार किया जा रहा है। मेलबर्न में अभी 12 अगस्त तक लाकडाउन लगा रहेगा। आस्ट्रेलिया में वैक्सीन लगाने की गति धीमी होने के कारण यहां के प्रधानमंत्री स्काट मारिसन के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ रही है।

इटली और फ्रांस में हेल्थ पास और वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किए गए। हर सप्ताह हो रहे प्रदर्शनों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस बार दो लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया।

एएनआइ के अनुसार पाक में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण ब्रिटेन ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे रेड लिस्ट में डाल दिया है।

- आस्ट्रेलिया में अब छोटे शहरों में भी लगा दिया गया लाकडाउन
- संक्रमण बढ़ने पर ब्रिटेन ने पाक पर लगाए यात्रा प्रतिबंध

इजरायल में बढ़ा संक्रमण : इजरायल में वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इससे यहां जांच का काम शुरू हो गया है। तेल अवीव में एक टेस्टिंग सेंटर पर जांच के लिए बच्चे का स्वैब सैंपल लेती हेल्थ वर्कर। सरकार ने 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। एपी

चीन : कोरोना के तेजी से फैलने के बाद वुहान शहर में एक करोड़ 28 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है। अब टेस्टिंग का काम अन्य शहरों में भी तेज किया जा रहा है। यहां डेल्टा वैरिएंट के कारण कोरोना के मरीज तेजी बढ़ते जा रहे हैं।

रूस : हर रोज 22 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं।

बांग्लादेश : यहां बुधवार से लाकडाउन को हटाया जा रहा है।

चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का प्रमुख बदला

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान ने चीन को लुभाने के लिए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रमुख को बदल दिया है। निके एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन अगस्त को पाक ने बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से सेवानिवृत्त आर्मी जनरल आसिम सलीम बाजवा को हटाकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) के सर्वोच्च पद के लिए खालिद मंसूर को नियुक्त कर दिया है। यह परियोजना 50 अरब डालर की बतायी जाती है। 32 साल के कैरियर वाले खालिद मंसूर ने सिंध एनग्रो कोल माइनिंग कंपनी एंड हब पावर कंपनी लिमिटेड जैसी ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों में सर्वोच्च प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर काम किया है।

ट्विटर पर असद उमर ने कहा, 'मैं सीपेक की टीम में बतौर एसएपीएम खालिद मंसूर का स्वागत करता हूं। उनके व्यापक अनुभव व चीनी कंपनियों के साथ किए गहन कामकाज का स्वागत करता हूं।

सोमवार को खेल मंत्रालय के सम्मान समारोह के दौरान मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक, कानून मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि दहिया, आइओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और भारतीय पुरुष हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह • खेल मंत्रालय

खेल मंत्रालय ने टोक्यो में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों को भारत पहुंचने पर किया सम्मानित

नायकों के लिए बिछाए पलक पांवड़े

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

टोक्यो ओलिंपिक से वापस लौटे ओलिंपिक पदक विजेताओं का सरकार द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन खिलाड़ियों की यात्रा खेल उत्कृष्टता और जज्बे की अविश्वसनीय कहानी रही है। दिल्ली के पांच सितारा अशोका होटल में आयोजित समारोह में खेल मंत्री के अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक, खेल सचिव रवि मित्तल और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान भी शामिल रहे। हालांकि सभी की निगाहें एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर टिकी थी। सम्मान समारोह में खेल मंत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह और शाल भेंट की। समारोह में नीरज के अलावा रजत पदक विजेता रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया, कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, कांस्य पदक विजेता पुरुष हाकी टीम और चौथे नंबर पर रही महिला हाकी टीम के साथ अन्य एथलीटों का भी स्वागत हुआ। टोक्यो में चोपड़ा ने जहां भारतीय अभियान में स्वर्णिम चमक डाली तो वहीं मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीते। शटलर पीवी सिंधू ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह भारत के अभियान में कई चीजें पहली बार हुई, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा 128-सदस्यीय खिलाड़ियों का दल, सात ओलिंपिक पदक, एथलेटिक्स स्पर्धा में पहला ओलिंपिक स्वर्ण पदक, सिंधू द्वारा लगातार खेलों (रियो और टोक्यो) में पदक व भारतीय पुरुष हाकी टीम का 41 साल के बाद पदक (कांस्य) जीतना शामिल है।

"मैं घर वापस आकर बहुत खुश हूं। मुझे पता था कि भारत में लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन यहां वापस आने के बाद पहली बार इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह के और पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी।
लवलीना बोरगोहाई, कांस्य पदक विजेता

यह बहुत अच्छा लगता है, मैं सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) को हमारे क्वरांटाइन के दौरान मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। **मनप्रीत सिंह,** कांस्य पदक विजेता, पुरुष हाकी कप्तान

1 करोड़ की इनामी राशि खाड़ी देशों में रहने वाले एक भारतीय व्यवसायी ने भारतीय हाकी टीम के गोलकीपर पी आर श्रीजेश को देने का एलान किया

83 करोड़ रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय महिला और पुरुष हाकी टीम पर खर्च किए

55 अंतरराष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट (पुरुषों के लिए 29, महिलाओं के लिए 26) भारत व विदेश में कराए आयोजित

393 दिनों तक विदेशी सरजमीं पर पुरुषों के लिए 106 और महिलाओं के लिए 287 दिन तक अभ्यास कराया गया

केक काटते भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ी और सदस्य • प्रेट्र

सूबेदार नीरज को चाहकर भी कमीशंड आफिसर नहीं बना सकती है सेना

संजय मिश्र • नई दिल्ली

टोक्यो में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा का कमीशंड आफिसर के तौर पर प्रमोशन का रास्ता नहीं खोला जा सकता। सेना में जेसीओ रैंक के अधिकारियों के लिए कमीशंड आफिसर बनने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अनिवार्य है। इस लिहाज से सेना के पास नीरज को फिलहाल सूबेदार मेजर या फिर मानद आनरेरी मेजर के तौर पर प्रमोशन देने का ही विकल्प है। नीरज इन दोनों में से जो भी विकल्प चुनेंगे सेना उन्हें पदोन्नति देगी।

नीरज की उपलब्धि पर सेना भी गदगद है और खेल जगत के अपने हीरो को पदोन्नति देने के लिए तैयार भी है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के आधार पर ही उन्हें सीधे कमीशंड अधिकारी बनाने की चर्चाओं पर सैन्य सूत्रों ने कहा कि चाहकर भी सेना यह नहीं कर सकती। सेना में अधिकारी को राष्ट्रपति की ओर से कमीशन प्रदान किया जाता है। इसके लिए अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जिन्हें बाइपास करना संभव नहीं है। सेना के जेसीओ भी लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के जरिए ही कमीशंड अफसर बनते हैं। नीरज भी इस समय सेना में जेसीओ रैंक पर ही हैं और ऐसे में कमीशंड अधिकारी बनने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया के रास्ते ही जाना होगा। नीरज अब अगले पेरिस ओलिंपिक पर निगाहें लगा रहे हैं और ऐसे में उनके पास सेना का कमीशन हासिल करने के लिए शायद ही वक्त हो। सैन्य सूत्रों ने कहा कि नीरज सूबेदार मेजर बनते हैं तो चार साल बाद रिटायर हो जाएंगे और यदि मानद रूप से मेजर की पदोन्नति का विकल्प चुनते हैं तो नियमों के अनुसार उन्हें एक साल के भीतर ही रिटायर होना पड़ेगा। इस लिहाज से सूबेदार मेजर का विकल्प बेहतर है क्योंकि प्रमोशन के चार साल बाद जब चोपड़ा रिटायर होने वाले होंगे तब सेना के पास उन्हें मानद मेजर का प्रमोशन देने का विकल्प भी रहेगा और तब उन्हें छह महीने का कार्यकाल मिल जाएगा।

"मुझे पता था कि मैंने कुछ विशेष कर दिया है, असल में मैंने सोचा कि मैंने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। स्वर्ण पदक हासिल करने के अगले दिन मेरे शरीर ने महसूस किया कि वह प्रदर्शन इतना विशेष था, शरीर दुख रहा था लेकिन यह दर्द सहन करने में कोई समस्या नहीं थी। यह पदक पूरे देश के लिए है। मुझे लंबे बाल पसंद हैं लेकिन मैं गर्मी से परेशान हो रहा था,इसलिए मैंने बाल कटवा दिए।
नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक विजेता

पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि मिली या नहीं, यह जांचा जाए

सुनील गावस्कर
कलम से

टोक्यो ओलिंपिक के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसे प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और हर तरह के मीडिया ने शानदार कवरेज दी है। महामारी के दौरान कई अखबारों के पत्रकार इसकी कवरेज के लिए टोक्यो नहीं जा सके, लेकिन उन सभी ने सर्वश्रेष्ठ अंदाज में अपनी कवरेज का प्रस्तुतिकरण दिया। महामारी के समय इन लोगों ने हो सकता है कि टेलीविजन पर देखकर ही अपनी खबरों को शानदार तरीके से तैयार किया हो, लेकिन मेरे विचार से भविष्य में भी ऐसा जारी रह सकता है।

मुझे इस बात की इतनी जानकारी नहीं है कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में पत्रकार का आयोजन स्थल पर होना कितना महत्वपूर्ण होता है। मुझे सिर्फ क्रिकेट के दौरान पत्रकार के मैदान में होने की उपयोगिता के बारे में पता है। क्रिकेट के खेल में पिच, मैदान की आउटफील्ड, हवा के बहाव की दिशा व गति, इसके अलावा कहीं-कहीं पर सीमा रेखा का छोटा और बड़ा होना। यह सभी ऐसे कारक हैं जो क्रिकेट के दौरान स्टूडियो की तुलना में मैदान पर खेल पत्रकार की उपयोगिता के महत्व को बताते हैं।

क्रिकेट में जब भी एक बल्लेबाज गेंद को हवा में मारता है तो स्टूडियो में कमेंट्री के दौरान अक्सर हम यही कहते हैं कि बहुत ही शानदार शाट मारा है। जबकि थोड़े समय में ही देखते हैं कि उसकी कैच मैदान के अंदर ही पकड़ ली गई। इस तरह कई बार स्टूडियो से गलतियां होती रहती हैं। वहीं, अगर कैच छूट जाता है तो सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि यह कैच पकड़ा जा सकता था। जबकि उसके पीछे मैदान में हवा का बहाव और उसकी दिशा, बल्लेबाज के शाट की टाइमिंग या उसने कितनी ताकत से वह शाट मारा था या नहीं। इसके अलावा गेंदबाजी के किस छोर से हवा का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। यह सभी कारक मैदान पर होने के साथ ही पता चलते हैं।

इस ओलिंपिक की मीडिया कवरेज ने दिखाया है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट के अलावा विभिन्न खेलों को कवर करने के लिए आलराउंडर कहा जा सकता है, जिनमें से कुछ भारत में भी मौजूद हैं।

भारत-इंग्लैंड सीरीज ओलिंपिक के अंतिम कुछ दिनों में शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी कवरेज मुख्य रूप से ओलिंपिक ही रहा। यह बात उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है जो हमेशा सिर्फ क्रिकेट कवरेज के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना करते रहे हैं। कई पुरस्कारों की घोषणा भी हुई है जो शानदार है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वादे पूरे होते हैं या नहीं। बैंडबाजे पर कूदना और प्रचार या ब्रांड प्रायोजक प्राप्त करना एक पुरानी चाल है और यह मीडिया के लिए है कि वह आगे बढ़े और यह सुनिश्चित करे कि जो भी वादे किए जा रहे हैं वह पूरे हो रहे हैं कि नहीं। हमारे पास 1983 क्रिकेट विश्व कप जीत का अनुभव हैं कि उस समय कितने पुरस्कार, राशि और न जाने किन-किन चीजों को देने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, करीब 95 प्रतिशत से अधिक खिलाड़ियों को वादे के अनुसार कुछ भी नहीं मिला। कुछ कंपनियों ने अपना वादा पूरा किया एक दशक या उसके बाद उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जबकि कुछ ब्रांड बाजार से गायब हो गए, लेकिन कम से कम उन्होंने उन शुरुआती वर्षों के लिए अपने वादे को तो पूरा किया। बाकी कुछ लोगों ने सिर्फ खुद के प्रचार के लिए पुरस्कार का एलान किया और उसके बाद उनसे कोई पूछने नहीं गया कि आपने अपने वादे का क्या किया। यहां तक कि राज्य सरकार के स्तर पर भी कई विजेताओं को पुरस्कार की घोषणा के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कार्यालयों में कई चक्कर लगाने पड़ते है।

अब युवा क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की ओर भी रुख करेंगे, जो की एक अद्भुत बात है। लेकिन अगर इस उत्साह को बनाए रखना है और आगे ले जाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि पुरस्कार विजेताओं को उनके पुरस्कार या राशि मिले या नहीं। अन्यथा लोग सोचेंगे दूसरे खेल में खेलने का क्या मतलब है जब वह आपका और आपके परिवार का पेट नहीं भर सकता है। मेरा यही मानना ही कि इस बार मीडिया को खिलाड़ियों से किए जाने वाले वादे की तह तक जाना चाहिए।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना : बजरंग पूनिया

एक पहलवान को देश के खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वर्षों की मेहनत व त्याग के बाद ओलिंपिक में कुछ ही मिनट मिलते हैं जिसमें वह देश का नाम रोशन करे। टोक्यो में देश के कई अच्छे पहलवान व मुक्केबाज पदक से चूक गए, लेकिन चोटिल होने के बाद भी भारत का पहलवान 65 किग्रा में देश का नाम रोशन करने में कामयाब रहा। ओलिंपिक में मुकाबलों और पदक जीतने के सफर को लेकर पहलवान **बजरंग पूनिया** से **अनिल भारद्वाज** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

साक्षात्कार

• टोक्यो में देश को बजरंग से स्वर्ण पदक की आस थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया?
-मैं देशवासियों से वायदा करता हूं कि पेरिस में आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। टोक्यो में चोट के कारण स्वर्ण पदक से चूक गया हूं।

• टोक्यो में बजरंग पर देशवासियों की आस का दबाव था या कोई और कारण थे?
-जब एक खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले में उतरता है तो उसे पता होता है कि देश को उनसे आस है। मेरे पर दबाव नहीं था, लेकिन मैं चोटिल जरूर था। मुझे तो स्वयं देश के लोगों की आस को पूरा करने का जनून था।

• क्या बजरंग की चोट मुकाबले शुरू होने से पहले उभर गई थी जिस कारण दुनिया के नंबर एक पहलवान की टोक्यो में शुरुआत बहुत हल्की रही थी?
-टोक्यो जाने से डेढ़ माह पहले रूस में चोट लग गई थी, लेकिन डाक्टरों का कहना था कि गंभीर नहीं है। प्री-क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के पहलवान के साथ घुटने में दर्द था, लेकिन मैंने अच्छा मुकाबला किया। जब स्कोर तीन-तीन की बराबरी पर था तो मुझे पता था कि नियम में मैं जीत रहा हूं। इसी कारण किर्गिस्तानी पहलवान को किसी तरह का मौका नहीं दिया।

• कांस्य पदक के मुकाबले में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। आपकों नहीं लगता ऐसा प्रदर्शन सेमीफाइनल में होता तो पदक का रंग बदला हुआ होता?
-मेरा प्लान था कि चोट को फाइनल मुकाबले तक गंभीर नहीं होने देना है। इसी कारण हर मुकाबला संभलकर लड़ रहा था। अगर मैं चोटिल नहीं होता तो आक्रामक मुकाबले लड़ता। सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान का पहलवान फायदा उठाने में कामयाब रहा। यही सही है कि अगर मैं आक्रामक कुश्ती लड़ता तो वह कहीं नहीं ठहरता। जब मैं हारा तो मुझे पता था कि मेरे परिवार व देश के लोगों को कितना दुख हुआ होगा। देश के लोगों को मेरे से बहुत आस है यह टोक्यो जाने से पहले मुझे पता था। जब मैं कांस्य पदक के मुकाबले में उतरा तो किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं यही सोचकर मुकाबले में उतरा की अगर अब चोट गंभीर होती है तो होने दे, लेकिन कांस्य हर हाल में जीतना है। यही कारण है कि मैं कजाखस्तान पहलवान को हराने में कामयाब रहा।

• अगर बजरंग सेमीफाइनल मुकाबले यह सोच लेते कि चोट गंभीर होती है तो होने दो, यह मुकाबला जीतना है तो क्या आज उन के पास रजत पदक होता?
-जब मैंने फाइनल मुकाबला बेहतर लड़ने का प्लान बनाया है तो सेमीफाइनल में हारने की बात ही नहीं थी, लेकिन सच यह है कि मैं मुकाबला हार गया। अब जब सेमीफाइनल हार गया तो यह विचार सभी को आते हैं कि सेमीफाइनल मुकाबला जीत लेते।

• कुछ लोग कह रहे हैं कि हारने के कारण चोट का नाम लिया जा रहा है?
- ऐसे लोगों को कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। खेल प्रेमी स्वयं उनका जवाब देंगे। यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बेहतर लड़ता हूं ओर देश के लिए पहले भी पदक जीते हैं तभी तो लोग मुझ से स्वर्ण पदक की आस लगाए हुए थे। मुझे उन लोगों की परवाह रहती है जो मेरे पर विश्वास रखते हैं।

• आप सेमीफाइनल में हारे, तो पिता जी भावुक हुए। हर कोई हार से परेशान था, उस समय खुद को कैसे संभाला?
-मेरे परिवार को पता था कि मैं चोटिल हूं। हार के बाद मैंने अपने पिता से बात की और उन्होंने देश के लिए पदक लाने को कहा। तभी मैंने अपने पिता से कांस्य पदक लाने का वायदा किया। मेरे पिता व प्रशिक्षकों ने यही कहा था कि देश के लिए पदक जीतना अहम है। पदक का रंग मत देखों। तभी मैंने सोच लिया था कि अब कांस्य भारत का है।

• अब क्या आपको अपने घुटने की सर्जरी करानी होगी?
- अब डाक्टर को दिखाना है। उसके बाद डाक्टर ही कुछ तय करेगा। मुझे नहीं लगता कि सर्जरी करानी होगी। क्योंकि टोक्यो से पहले डाक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी लेकिन आराम करने का समय नहीं मिला। मैं टोक्यो को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि ओलिंपिक में पदक जीतने का सपना हर खिलाड़ी को होता है। मुझे लगता है डाक्टर की सलाह पर आराम करने से चोट ठीक हो जाएगी।

आस्ट्रेलिया 62 पर ढेर, बांग्लादेश ने 4-1 से जीती टी-20 सीरीज

क्रिकेट डायरी

ढाका, प्रेट्र : मैन आफ द मैच और मैन आफ द सीरीज शाकिब अल हसन व मुहम्मद सैफुद्दीन की अगुआई में बांग्लादेश ने सोमवार को यहां पांचवें और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आस्ट्रेलिया को उसके न्यूनतम स्कोर पर समेटने के साथ 60 रन की जीत से सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

शाकिब अल हसन • एएफपी

बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हालात के बीच बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नाथन एलिस (2/16) और डैन क्रिस्टियन (2/17) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 122 रन का स्कोर ही खड़ा कर सकी। मेजबान टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज मुहम्मद नईम (23 रन) ही 20 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे। शाकिब अल हसन (4/9), सैफुद्दीन (3/12) और नासुम अहमद (2/8) की सटीक गेंदबाजी के सामने आस्ट्रेलिया के लिए यह छोटा लक्ष्य भी एक बार फिर पहाड़ जैसा साबित हुआ और टीम 13.4 ओवर में 62 रन पर ढेर हो गई। आस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मैथ्यू वेड ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। उनके अलावा बेन मैकडर्मोट (17) ही दोहरे अंक में पहुंचे।

62 रन पर ढेर हो गई आस्ट्रेलियाई टीम जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसका न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले आस्ट्रेलिया का न्यूनतम स्कोर 79 रन था जो उसने जून 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था

100 विकेट आलराउंडर शाकिब अल हसन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर हुए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के पहले और दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। शाकिब के नाम अब 102 विकेट दर्ज हैं। उनसे अधिक विकेट सिर्फ श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसित मलिंगा (107 विकेट) ने चटकाए हैं

पूर्व कप्तान शरत का राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष बनना तय

नई दिल्ली, प्रेट्र : तमिलनाडु के पूर्व कप्तान और लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले श्रीधरन शरत का बीसीसीआइ की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनना तय है जिसे कि अगले साल होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम का चयन करना है। बीसीसीआइ में जिन कुछ नामों पर सहमति बनी है उनमें पंजाब के कृष्ण मोहन भी शामिल हैं जिन्होंने 1987 से 1995 के बीच 45 प्रथम श्रेणी मैच खेले। मोहन उत्तर क्षेत्र से उम्मीद्वार हैं। मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाजी आलराउंडर हरविंदर सिंह सोढ़ी मध्य क्षेत्र से मुख्य दावेदार हैं। उन्होंने 76 प्रथम श्रेणी मैचों में 2000 से अधिक रन बनाए और 174 विकेट लिए। वह बीसीसीआइ के मैच रेफरी भी हैं। बंगाल के तेज गेंदबाज राणादेव बोस अपने पूर्व साथी शुभमय दास को चयनकर्ता बनने की दौड़ में पीछे छोड़ सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का निधन

दिलीप कुमार • खूंटी

हाकी का एक सितारा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा गुमनाम जिंदगी जीते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। ब्रेन हेमरेज से जूझते हुए सोमवार को गोपाल का रांची के गुरुनानक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें खूंटी स्थित उनके गांव में दफना दिया गया। इस अवसर पर उन्हें सम्मान देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर उनके दर्द को जरूर समझते थे। इस खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद सुनील हर महीने चुपचाप गोपाल के अकाउंट में 15 हजार रुपये भेज देते थे। 1978 में अर्जेंटीना में आयोजित विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में गोपाल ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। उसी वर्ष उन्होंने पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच में भी भाग लिया था। कई वर्षों तक वे पश्चिम बंगाल टीम के कप्तान भी रहे। 1979 में बैंकाक में हुई दक्षिण एशिया हाकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल थे।

पूर्व खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं गावस्कर

जेएनएन, नई दिल्ली : भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज व कप्तान सुनील गावस्कर के चैंप्स फाउंडेशन ने अपनी नई वेबसाइट चैंप्सइंडियाडाटओआरजी लांच की है। गावस्कर का यह फाउंडेशन साल 1999 में स्थापित हुआ था और तब से भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद करता आ रहा है। अपनी नई वेबसाइट के बारे में बताते हुए गावस्कर ने कहा, 'अब तक, फाउंडेशन तभी मदद कर पाता था, जब उसे मीडिया के माध्यम से भारत के एक पूर्व खिलाड़ी के संघर्ष के बारे में पता चलता था। अब हमारे पास नियमित रूप से वेबसाइट है। जिसमें जाकर पूर्व खिलाड़ी खुद अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारा लक्ष्य बस खेल से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों की जिंदगी को आसान बनाना है।'

पहले टेस्ट की टीम आदर्श : कोहली

इंग्लैंड दौरे पर भारत

नाटिंघम, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्षा से प्रभावित पहले टेस्ट के रविवार को ड्रा होने के बाद कहा कि यह टीम आगे बढ़ते हुए हमारे लिए आदर्श टीम होगी। इसका मतलब है कि भारत पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे मैचों में भी चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के संयोजन के साथ उतर सकता है।

विराट कोहली • एपी

ऐसे में बाकी बचे चार मैचों में रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से किसी एक को ही खेलने का मौका मिलेगा। पहले टेस्ट में अश्विन पर जडेजा को तरजीह दी गई। पांचवें और अंतिम दिन बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी जिससे भारत से जीत का मौका छिन गया।

कोहली ने कहा, 'हम तीसरे और चौथे दिन बारिश की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह पांचवें दिन आ गई। खेलना और मैच को देखना मजेदार होता, लेकिन यह शर्मनाक है। हम यही करना चाहते थे, मजबूत शुरुआत। पांचवें दिन हमें पता था कि हमारे पास मौका है। हम निश्चित तौर पर महसूस कर रहे थे कि हम अपने खेल के शीर्ष पर हैं।' उन्होंने कहा, 'हम 40 रन के आसपास की बढ़त ही बात कर रहे थे, लेकिन 95 रन की बढ़त हासिल करने में सफल रहे और यह रन सोने की तरह थे। पूरी संभावना है कि यह इस सीरीज में हमारे लिए आदर्श रहेगा, लेकिन सामंजस्य बैठाना हमारा मजबूत पक्ष है। हालात और विकेट की गति को देखने की जरूरत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक होते हैं और अगले टेस्ट को लेकर बेताब है।'

नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की अंक प्रणाली के तहत दोनों टीमों को चार-चार अंक मिले। भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि बारिश ने खलल डाल दिया नहीं तो अंतिम दिन का खेल बेहद रोमांचक होता। रूट ने कहा, 'खेलने और देखने के लिहाज से शानदार टेस्ट मैच। सीरीज की शानदार शुरुआत और उम्मीद करते हैं कि अगले मैचों में भी यही देखने को मिलेगा। हमें निश्चित तौर पर विश्वास था कि हम जीत सकते हैं।'

भारतीय टीम लाड्र्स टेस्ट के लिए लंदन रवाना

लंदन, प्रेट्र : इंग्लैंड के खिलाफ लाड्र्स मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच केलिए भारतीय टीम लंदन रवाना हो गई जबकि चोटिल खिलाड़ियों की जगह लेने वाले सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शा नाटिंघम में ही अपना क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली के भी लाड्र्स टेस्ट के दौरान मौजूद रहने की खबर है क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने भारत से आने वाले लोगों को लाल सूची से हटा दिया है। दूसरा टेस्ट 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। शा और सूर्यकुमार तीन अगस्त को नाटिंघम में टीम से जुड़े थे।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
मंगलवार, 10 अगस्त, 2021

कोरोना के दौर में हम अगर यह सोच रहे हैं कि उन्मुक्त होकर जी नहीं पा रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो यह मान लें कि स्वतंत्रता शरीर की नहीं, बल्कि मन की होती है। मन से स्वाधीन होकर ही हम सही ढंग से सोच पाते हैं और सोच की स्वतंत्रता से हम संपूर्ण स्वाधीनता की ओर बढ़ते हैं...

फोटो : इमेजेज बाजार

मन की स्वाधीनता

स्वतंत्रता दिवस विशेष

अशोक जमनानी
साहित्यकार व धार्मिक विषयों के अध्येता

एक बार जंगल से गुजरते हुए एक ऋषि ने अपने शिष्यों को बहेलिए द्वारा बिछाया हुआ जाल दिखाकर पूछा कि यह जाल बहेलिए ने क्यों बिछाया है? शिष्यों ने उत्तर दिया कि पक्षियों को बंदी बनाने के लिए। उनका उत्तर सुनकर ऋषि ने पूछा कि और ये दाने यहां क्यों फैलाए हैं? तब शिष्यों ने कहा कि पक्षियों को ललचाने के लिए। ऋषि ने कहा कि इससे क्या सिद्ध होता है? शिष्यों ने कहा कि लालच के कारण पक्षी बंदी बनेंगे। तब ऋषि ने पूछा कि पक्षियों के बंदी बनने से पूर्व कौन बंदी बनेंगे? जब शिष्य कोई उत्तर नहीं दे पाए तो ऋषि ने कहा कि पक्षियों के बंदी बनने से पूर्व उनके मन बंदी बन जाएंगे, इसलिए सदैव याद रखो कि अपने मन की स्वतंत्रता को किसी भी तरह नहीं खोना है। क्योंकि यदि मन स्वतंत्रता खो देता है, तो शेष को गुलाम बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जो लोग किसी को बंधन में डालना चाहते हैं, वे पहले उनके मन को बांधते हैं। मन की परतंत्रता स्वीकार करते ही गुलामी का आरंभ हो जाता है और मन के स्वतंत्र होते ही स्वतंत्रता का आगमन निश्चित हो जाता है। गांधी जी ने भी कहा था कि, 'जब गुलाम यह संकल्प कर लेता है कि वह अब गुलामी नहीं करेगा तो उसी समय उसकी जंजीरें टूट जाती हैं।'

कहते हैं कि सूक्ष्म अस्तित्व का प्रतिनिधि मन है। इसलिए मन ही स्थूल को निर्देशित करता है। विनोबा भावे जी ने भी कहा था, 'मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी होता है, वह मन के द्वारा ही होता है। तो जिसके द्वारा काम होता है, वह इकाई ही बिगड़ी हुई हो तो सारा काम बिगड़ जाएगा।' इसलिए विनोबा जी सदैव मन को सही दिशा देने के लिए संकल्पित करते रहे।

मन के केंद्र में होने के कारण भारतीय मनीषा ने भी इसके महत्व को सदैव स्वीकारा है। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त का धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में एक बहुत विशिष्ट स्थान है तो उसका कारण है कि यह सूक्त मन को 'तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु' कहकर शिव संकल्पित करने का आग्रह तो है ही, साथ ही साथ यह मन के सामर्थ्य को भी रेखांकित करता है और इसे कर्म, यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्य, वर्तमान, ज्ञान, विज्ञान, धृति से लेकर जगत के समस्त विस्तार का कारण बताते हुए अमृतमय कहकर भी संबोधित करता है। ऐसे में जब स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो मन की स्वतंत्रता की बात के बिना संभवतः संपूर्ण स्वतंत्रता की बात संभव नहीं होगी।

क्या है यह संपूर्ण स्वतंत्रता? इस संपूर्णता के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व चलिए हम एक महान व्यक्तित्व के अनुभव को स्पर्श करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में एक अद्भुत व्यक्तित्व का उल्लेख होता है, जो बाद में हमारे देश की महान आध्यात्मिक विभूति के रूप में जाने गए। वे थे श्री अरविंद घोष (महर्षि अरविंद)। इंग्लैंड से लौटे श्री अरविंद के मन में कभी अंग्रेजी सभ्यता का गहरा प्रभाव रहा, लेकिन फिर वे क्रांतिकारी बने और जेल भी गए, लेकिन जेल से बाहर निकले तो उनका पथ अध्यात्म की ओर मुड़ गया और साधना पथ पर चलते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे अंदर का मनोमय पुरुष विराट मन बन गया, जो विचारों के कारखाने में एक मजदूर की भांति वैयक्तिक विचार के संकुचित घेरे में बंधा नहीं था, बल्कि सत्ता के सैकड़ों स्तरों से ज्ञान ग्रहण करने लगा तथा इस विशाल दर्शन साम्राज्य एवं विचार साम्राज्य में से अपनी इच्छा के अनुसार विषयों और विचारों का चुनाव करने में स्वतंत्र था।' उन्होंने बताया कि जो मन मजदूर था, वह मालिक बन गया और यह स्वतंत्रता ही संपूर्ण स्वतंत्रता के मूल में है।

एक समय था, जब दुनिया के अधिकांश देश गुलाम थे। वह समय बीत गया है और वे देश स्वतंत्र हो गए, लेकिन पूरी दुनिया की मनुष्य जाति के सामने अब भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या किसी भी देश को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली है? असल में अधिकांश देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है और उन सबने मान लिया है कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन यह आधी-अधूरी स्वतंत्रता है। संपूर्ण स्वतंत्रता को हासिल करना अब भी शेष है। यह किसी एक देश या क्षेत्र का प्रश्न नहीं है, यह पूरी दुनिया की मनुष्य जाति का प्रश्न है कि उसे संपूर्ण स्वतंत्रता कब मिलेगी? भारत की मनीषा ने युगों-युगों से अपने चिंतन में संपूर्ण स्वतंत्रता को एक समाधान के रूप में देखा है। वह स्वतंत्रता, जिसमें मनुष्य अपने मन का मजदूर नहीं, बल्कि स्वामी बन जाए। ऐसा स्वामी, जिसे दर्शन और विचार की विराट सत्ता में से अपने मनचाहे पथ पर आगे चलकर उस विराट को पा लेना है, जो परम स्वतंत्र है। वैसे यह केवल अध्यात्म जगत का समाधान नहीं है, बल्कि भौतिक जगत में भी स्वतंत्रता को संपूर्ण स्वतंत्रता तक का मार्ग तय करना ही होगा।

भारत का चिंतन संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का पथ प्रशस्त कर उसे स्वामी होने का सुख और आनंद देना चाहता है। उसे मजदूरी से मुक्त कर उसे उसके वास्तविक अधिकारों को सौंपना चाहता है। वे मनुष्य, जो दानों के लालच में पक्षियों की तरह पहले अपने मन को बंदी बनाकर फिर स्वयं भी बंदी बन बैठे हैं और उन्होंने एक सीमित स्वतंत्रता को संपूर्ण स्वतंत्रता मान लिया है, उनके मन को स्वतंत्रता का संपूर्ण सौंपकर उन्हें अमृत पथ का अधिकारी होने का गौरव सौंपना भारत के चिंतन में सदियों से संकल्पित होता रहा है।

श्री अरविंद हों या महात्मा गांधी अथवा भारत के चिंतन को धारण करने वाला लोक मन, सबने सीमित स्वतंत्रता को संपूर्ण स्वतंत्रता तक पहुंचने का स्वप्न संजोया है। वह स्वतंत्रता, जो केवल वैयक्तिक नहीं है। वह स्वतंत्रता, जो केवल किसी एक देश की नहीं है। वह स्वतंत्रता, जिसमें मनुष्य का मन मजदूर नहीं, स्वामी है। वह स्वतंत्रता, जिसमें मनुष्य मन विराट की अनंत संभावनाओं के द्वार खोलेगा। वह स्वतंत्रता, जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति के मन से सारे भेद मिट जाएंगे। वह स्वतंत्रता, जिसमें मन उस शिव संकल्प से युक्त होगा, जो अमृत-पथ प्रशस्त करेगा। वह अमृत पथ, जो मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाता है। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करें।

निर्झरिणी

यह जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वे ही वास्तव में जीते हैं।

–स्वामी विवेकानंद

विपरीत परिस्थितियों पर विजय का दिन

नाग पंचमी पर

सलिल पांडेय
धर्म-संस्कृति के अध्येता

नागपंचमी के दिन नागों की पूजा का विधान है। यह प्रतीकात्मक रूप में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक संदेश भी देता है। मनुष्य का जीवन भी विपरीत परिस्थितियों के नागों की उपस्थिति में व्यतीत होता है। आत्मा यदि परमात्मा का अंश है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि किसी विषैले सर्प से कम नहीं हैं, जो हमें आत्मरूप परमात्मा तक पहुंचने नहीं देते। हमें विपरीत परिस्थितियों के नागों को भी स्वीकार करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, क्योंकि वे ही हमें सबल बनाते हैं। साथ ही उनसे बचने या पार पाने के उपाय हमें अपने विवेक द्वारा ढूंढ़ने होंगे।

पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग के अंतिम राजा परीक्षित को तमाम यज्ञ, अनुष्ठान के बावजूद तक्षक नामक सर्प ने मार डाला था। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, जिन्हें अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ही मार डाला था, लेकिन मृत रूप में जन्मे परीक्षित को योग-शक्ति से कृष्ण ने बचा लिया था। परीक्षित का आशय ही परीक्षण से है। संसार, आत्मा, परमात्मा के परीक्षण में अविवेकरूपी सर्प के डसने की आशंका निरंतर बनी रहती है। विकार रूपी कलियुग जब विवेक रूपी परीक्षित के राज्य में घुसने की कोशिश करने लगा तो दयाभाव में आकर परीक्षित ने सोना, जुआ, मद्य, स्त्री और हिंसा में कलियुग को स्थान दे दिया। इन्हीं पंचस्थलों से निकलने वाले सर्प मनुष्य के सुखद जीवन को डसते हैं।

नागपंचमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार, नागों की माता कद्रू ने अपनी सौत विनता को धोखा देने के लिए अपने पुत्रों से कहा, लेकिन पुत्रों ने सौतेली मां को धोखा देने से मना कर दिया, जिससे माता के शाप से नाग जलने लगे। वे भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने श्रावण मास की पंचमी को नागों को वरदान दिया कि तपस्वी जरत्कारु नाम के ऋषि का पुत्र आस्तिक नागों की रक्षा करेगा। जब परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने इंद्र सहित तक्षक को अग्निकुंड में आहुति के लिए मंत्रपाठ किया, तब आस्तिक ने तक्षक की प्राण-रक्षा की। यह तिथि भी पंचमी ही थी। मान्यता है कि नागों की ज्वलनशीलता कम करने के लिए उन्हें दूध से स्नान कराने एवं पूजा करने का विधान बना।

विकारों का सर्प हमेशा सकारात्मक परिस्थितियों को डसता रहता है। द्वापर में कालिया नाग ने यमुना के जहर को प्रदूषित कर जहरीला बना दिया था। उस कालिया नाग का वध करने कृष्ण को यमुना में कूदना पड़ा।

देखा जाए, तो सावन के महीने में महादेव की पूजा में जहरीली व विषम परिस्थितियों को गले लगाने और उनसे पार पाने का भी संदेश निहित है। आज के समय में कोरोना के कारण ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। आखिर श्रीहनुमान जी लंका की विषैली परिस्थितियों में भी विभीषण रूपी सकरात्मकता ढूंढ़ लेते हैं।

प्रेरक प्रसंग

मेहनत और निष्ठा से करें अपना काम

एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे, तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर जी शंख बजाएंगे तभी वर्षा होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। एक दिन भगवान शंकर-पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान कड़ी धूप में खेत जोत रहा है। पत्थर की तरह सख्त जमीन पर वह जी-जोड़ मेहनत कर रहा था। उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा- 'अरे भाई! तू क्यों कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती।' किसान ने जवाब दिया- 'हां, श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं पूरी लगन से जुताई करता हूं। मेहनत का अपना ही आनंद है।' किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मुझे भी शंख बजाये एक बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर घटाएं घुमड़ पड़ीं और बारिश होने लगी।

कथा-मर्म : हमें अपने काम को पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ-लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है।

प्रस्तुति : सूर्यदीप कुशवाहा

हिंडोले में झूलें राधा-कृष्ण...

ब्रज में श्रावण

गोपाल चतुर्वेदी
सांस्कृतिक विषयों के अध्येता

ब्रज में श्रावण मास की छटा अद्भुत होती है। वर्षा की फुहारों के मध्य समूचा ब्रज प्रिया-प्रियतम में भाव निमग्न होकर झूमने लगता है। यहां श्रावण का अर्थ है- झूले, कजरी, बरसते मेघ, भीगता मन, खनकती चूड़ियां और खिलती मेंहदी। यहां के विभिन्न मंदिरों में झूलों, हिंडोलों, रासलीला, मल्हार गायन व सत्संग-प्रवचन आदि की विशेष धूम रहती है। मंदिरों में ठाकुर जी (श्रीकृष्ण) के झूलने के लिए हिंडोले सजाये जाते हैं। 'भक्ति रसामृत सिंधु' के अनुसार, भक्ति के 64 अंगों में एक हिंडोला उत्सव भी है। मंदिरों को केले के पत्तों, फूल-पत्तियों, पर्दों आदि से सजाया जाता है, जिन्हें घटा कहते हैं। हिंडोलों में ठाकुर विग्रह विराजित कर उनका मालपुए, घेवर आदि से भोग लगाया जाता है। वहीं श्रीधाम वृंदावन के गोपीश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर पूजा-अर्चना करते हैं।

हरियाली तीज : ब्रज में श्रावण शुक्ल तृतीया (11 अगस्त) को हरियाली तीज का त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में मां पार्वती की पूजा का विधान है। ब्रज में यह त्योहार भगवान श्रीकृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के 'झूलनोत्सव' के रूप में तीज से लेकर रक्षाबंधन तक 13 दिनों तक मनाया जाता है। यहां हिंडोला उत्सव की बहार आ जाती है। इस उत्सव में मंदिरों में झूले के पदों का गायन होता है। मान्यता है कि ब्रज के मंदिरों में हिंडोला उत्सव या झूलनोत्सव का शुभारंभ महाप्रभु वल्लभाचार्य के समय में हुआ था। वृंदावन का ठाकुर बांके-बिहारी मंदिर आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। यहां हरियाली तीज पर ठाकुर बांके बिहारी को सोने-चांदी से बने 218 किलो वजनी हिंडोले में झुलाया जाता है।

झूलन यात्रा महोत्सव : वृंदावन के ठाकुर राधादामोदर मंदिर में हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक झूलन यात्रा महोत्सव की धूम रहती है। इस दौरान ठाकुर जी को काष्ठ से सुसज्जित हिंडोले में झुलाया जाता है। वृंदावन के ठाकुर रंगलक्ष्मी मंदिर में चांदी और शाहजी मंदिर में सोने के हिंडोले में ठाकुर जी को झुलाया जाता है।

राधारानी की क्रीड़ा स्थली बरसाना के श्रीजी मंदिर में भी हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। राधारानी के श्रीविग्रह को स्वर्ण हिंडोले में झुलाया जाता है, जबकि नंदगांव के नंदबाबा मंदिर में ठाकुर जी को विशालकाय चांदी के हिंडोले में झुलाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण के अग्रज ठाकुर दाऊदयाल की नगरी बल्देव के दाऊजी मंदिर में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा (रक्षाबंधन) तक भगवान श्रीकृष्ण के अग्रज दाऊजी व उनकी भार्या रेवती मैया के श्रीविग्रहों के समक्ष जगमोहन में 15-15 फीट के स्वर्ण व रजत जड़ित हिंडोले स्थापित कर दिए जाते हैं। साथ ही स्वर्ण जड़ित दर्पण में पड़ने वाले दाऊजी और रेवती मैया के प्रतिबिंबों को हिंडोलों में झुलाया जाता है। इन दोनों के विग्रह बड़े होने के कारण हिंडोलों में विराजित नहीं हो सकते।

मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर एवं गोकुल के वल्लभकुलीय मंदिरों में श्रावण भर ठाकुर जी को सोने चांदी के हिंडोले में झुलाया जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर में हिंडोला उत्सव प्रायः श्रावण कृष्ण द्वितीया से भाद्र कृष्ण द्वितीया तक चलता है। इस दौरान श्रावण शुक्ल अष्टमी (16 अगस्त) को लाल घटा, दशमी (17 अगस्त) को गुलाबी घटा, द्वादशी (19 अगस्त) को काली घटा व चतुर्दशी (21 अगस्त) को लहरिया घटा सजाई जाती है। लोग यहां के विभिन्न मंदिरों में सजाये गए हिंडोलों और घटाओं (परदों) के मध्य राधा-कृष्ण के अद्भुत रूप-माधुर्य का दर्शन सुख प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। समूचा ब्रज श्रावण मास में श्यामा-श्याम मय रहता है।

सप्ताह के पर्व-त्योहार

11 अगस्त : मधुश्रवा तृतीया व्रत, हरि तृतीया, हरियाली तीज
13 अगस्त : नाग पंचमी व्रत, कल्कि जयंती
15 अगस्त : गोस्वामी तुलसीदास जयंती, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ

जीवन मूल्यों के प्रतिस्थापक

तुलसी जयंती पर

प्रातः स्मरणीय कवि कुल के महानायक संत शिरोमणि महाकवि संत तुलसीदास जी युगबोध के द्रष्टा थे। उनका आविर्भाव उस समय हुआ था, जब जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा था। समाज में विघटन की प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं। मुगलों के शासन में सनातन संस्कृति के प्रतीक चिह्नों को मिटाने के प्रयास चल रहे थे। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को राम नाम की संजीवनी बूटी दी, जिसे हृदय में बसाकर सनातन धर्म की ध्वजा घर-घर में लहराने लगी। श्रीरामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि चरित्रों को जीवंत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया तथा प्रत्येक परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करने का बल प्रदान किया। उन्होंने ब्रह्म तत्व को समझने का संकेत दिया। निराकार ब्रह्म जब साकार होता है, तब वह राम के रूप में आता है, इसीलिए श्रीराम महान आदर्श हैं और अनुकरणीय हैं। श्रीराम में मानव जाति के लिए अपेक्षित सभी गुण विद्यमान हैं। वे शीलवान हैं, उदार हैं, करुणासिंधु हैं और पापियों को दंड देने में कठोर भी हैं। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे हम हर कालखंड में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनके आदर्श चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन-जन तक पहुंचा दिया।

संत शिरोमणि तुलसी ने राम की भक्ति ही नहीं की, उन्हें जिया और स्वयं भी राममय हो गए। उन्होंने अपना अस्तित्व, अपनी कृति और अपना जीवन सब कुछ श्रीराम को सौंप दिया।

राजापुर (चित्रकूट धाम) में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने जन्म लिया और अपनी कृति श्रीरामचरितमानस से हमें जीने की राह दिखाई, जीवन को मर्यादित तरीके से जीना सिखाया। संस्कार और मूल्यों का महत्व बताया। इस प्रकार उन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा और पुनर्स्थापना की।

सरिता पाण्डेय

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 10 अगस्त, 2021 मंगलवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: उत्तर।
पर्व एवं त्योहार: मंगलागौरी व्रत।

मेष: दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। संयम से काम लें। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे।

वृष: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। भागदौड़ रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा।

मिथुन: शुक्र का परिवर्तन निजी सुख में वृद्धि कराएगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कर्क: किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक योजना फलीभूत होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

सिंह: मंगल और बुध की युति व्यावसायिक मामलों में सफलता देगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपसी संबंध मधुर होंगे।

कन्या: शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उदर विकार या रक्तचाप के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

तुला: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृश्चिक: आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जीविका के क्षेत्र में किया गया प्रयास फलीभूत होगा।

धनु: महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

मकर: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। दांपत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। संयम से काम लें। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

कुंभ: विरोधी परास्त होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मधुमेह के रोगियों को विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है।

मीन: दांपत्य जीवन सुखद होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कल 11 अगस्त का पंचांग

कल का दिशाशूल: उत्तर।
पर्व एवं त्योहार: हरियाली तीज।
विशेष: शुक्र कन्या राशि में।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तत्पश्चात् चतुर्थी पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र तत्पश्चात् उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शिव योग 18 घंटे 27 मिनट तक, तत्पश्चात् सिद्धि योग सिंह में चंद्रमा तत्पश्चात् कन्या में।

वर्ग पहेली-1663

बाएं से दाएं
1 [illegible] [3]। 3 [illegible] [3]। 5 [illegible] [2]। 6 [illegible] [2]। 8 [illegible] [4]। 10 [illegible] [4]। 13 [illegible] [2]। 14 [illegible] [3]। 16 [illegible] [3]। 20 [illegible] [2]। 21 [illegible] [4]। 24 [illegible] [2,2]। 25 [illegible] [2]। 26 [illegible] [2]। 27 [illegible] [4]। 28 [illegible] [3]।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] [4]। 2 [illegible] [4]। 4 [illegible] [3]। 7 [illegible] [3]। 9 अंधा [2]। 11 [illegible] [2]। 12 [illegible] [2]। 13 [illegible] [3]। 15 [illegible] [3]। 17 [illegible] [2]। 18 [illegible] [2]। 19 [illegible] [2]। 20 [illegible] [3]। 22 [illegible] [4]। 23 [illegible] [4]। 24 [illegible] [3]।

कल का हल

जागरण सुडोकू-1663

		8	3		1			2
1		2		7	5		4	
						1		
		5			6		3	
9	3		2	8			7	1
2			9				6	
		9				4		8
	6				8		2	
	8		5					3

कल का हल

8	2	5	1	9	3	4	7	6
7	6	3	2	4	8	5	1	9
1	9	4	7	5	6	3	8	2
9	1	2	4	6	7	8	5	3
3	7	6	8	1	5	9	2	4
4	5	8	9	3	2	1	6	7
6	8	9	3	2	1	7	4	5
2	4	7	5	8	9	6	3	1
5	3	1	6	7	4	2	9	8

मौसम

कल पढ़ें

माइग्रेन के बारे में जरूरी है जागरूकता

दुनिया ने पहली बार कामिक बुक के जरिये देखा स्पाइडरमैन

वर्ष 1962 में आज ही बच्चों का चहेता आभासी कैरेक्टर स्पाइडरमैन कामिक बुक अमेजिंग फैंटेसी के जरिये दुनिया के सामने आया था। यह सुपरहीरो बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। लोकप्रियता को देखते हुए इस पर कई फिल्में भी बनी हैं।

इसरो ने प्रक्षेपित किया 17 टन वजन वाला एसएलवी-3 राकेट

1979 में आज ही इसरो ने एसएलवी-3 (सेटेलाइट लांच व्हीकल) को प्रक्षेपित किया था। चार चरणों वाले एसएलवी-3 का वजन 17 टन था। उड़ान आंशिक सफल रही थी। 317 सेकेंड बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। सालभर बाद इसने सफल उड़ान भरी।

निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहले राष्ट्रपति बने वीवी गिरी

भारत के इकलौते निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म आज ही 1894 में ओडिशा के बरहामपुर में हुआ था। पहली लोकसभा में चुनाव जीतकर नेहरू कैबिनेट में मंत्री बने। उप्र, केरल, कर्नाटक के राज्यपाल रहे। 1967 में उपराष्ट्रपति बने। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उस दौरान 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को मंजूरी दी। पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर इस्तीफा दिया और निर्दलीय के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में पर्चा भरा और देश के चौथे राष्ट्रपति बने। 1974 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 23 जून, 1980 को निधन हो गया।

जलवायु परिवर्तन की तस्वीरें डरा रही हैं

कहीं जंगल में धधकती आग, कहीं बाढ़ में डूबा शहर और कहीं तूफान से हलकान लोग, पूरी दुनिया में लोग ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से दो-चार हो रहे हैं। सोमवार को जारी हुई यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्म हवाओं का जो दौर 50 साल में एक बार आता था, अब हर दशक में एक बार आने लगा है। यदि दुनिया का औसत तापमान एक डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, तो हर सात साल में दो बार इनका सामना करना पड़ेगा। औसत तापमान बढ़ने से बस अप्रत्याशित मौसम का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन अपने साथ और भी कई आपदाएं लाता है।

औद्योगिक विकास की राह पर बढ़ते ही धरती के औसत तापमान ने लगाई छलांग

ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसानी गतिविधियां किस तरह जिम्मेदार हैं, इसका प्रमाण आंकड़े भी देते हैं। यह ग्राफ 2000 साल में औसत तापमान में वृद्धि को दर्शा रहा है।

1850 से 2020 के बीच की तस्वीर दिखाती है कि जैसे-जैसे उद्योग बढ़े, तापमान बढ़ता गया।

तेजी से गर्म हो रहा हिंद महासागर

रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इससे आने वाले वर्षों में भारत में गर्म हवाओं और बाढ़ का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तापमान बढ़ने से महासागर का जल स्तर भी बढ़ेगा, जो तटीय इलाकों में बाढ़ का कारण बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में मानसून का चक्र लंबा होगा। माडल बताते हैं कि डेढ़ से दो डिग्री सेल्सियस तक की ग्लोबल वार्मिंग से भारत और दक्षिण एशिया में मानसूनी बारिश बढ़ेगी। ज्यादा बारिश, बाढ़ और सूखा का सिलसिला भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को थामना किसी एक देश के वश में नहीं।

इंसानी गतिविधियों और लापरवाही के कदमों की कीमत चुका रही है दुनिया

बेहद गर्म हवाएं : इस बार कनाडा और पैसिफिक नार्थवेस्ट में जानलेवा गर्म हवाओं का दौर दिखा। ऐसी परिस्थितियां अब पांच गुना ज्यादा आने लगी हैं। तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हुई तो इनके आने का सिलसिला 14 गुना तक हो जाएगा।

सूखा : जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की भयावहता और इनके आने का क्रम बढ़ा है। पहले आमतौर पर एक दशक में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता था। अब इनके आने का सिलसिला 70 फीसद बढ़ गया है। तापमान और बढ़ा तो यह सिलसिला तीन से चार गुना हो सकता है।

बाढ़ : बढ़ता औसत तापमान पूरे जल चक्र को प्रभावित करता है। एक ओर ज्यादा वाष्पीकरण से सूखा पड़ता है, तो दूसरी ओर गर्म हवाएं ज्यादा वाष्प रोककर रख पाती हैं, जिससे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और बाढ़ की स्थिति बनती है। पश्चिमी यूरोप और चीन में हाल में अप्रत्याशित बाढ़ देखी गई है।

समुद्र का बढ़ता जल स्तर : सागर का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी सदी में एक बार आने वाली तटीय बाढ़ सन 2100 तक हर साल आने लगेगी। इसका सामना दुनिया के आधे से ज्यादा तटीय क्षेत्र करेंगे।

"वैश्विक स्तर पर बिजली क्षेत्र कुल उत्सर्जन के 73 फीसद के लिए जिम्मेदार है। यही बिजली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का भी मूल आधार है। ऐसे में हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत अपनाने की जरूरत है, जिनसे कार्बन डाई आक्साइड का उत्सर्जन न हो। सौर ऊर्जा इसका आदर्श समाधान उपलब्ध कराती है। तकनीक उपलब्ध है। हमें वैश्विक स्तर पर सहयोग के साथ इस दिशा में बढ़ना होगा।

अजय माथुर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और टेरी के महानिदेशक

इंसानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण हैं। दुनिया को 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 2010 की तुलना में 45 से 50 फीसद पर लानी होगी और 2050 तक इसे शून्य पर पहुंचाना होगा। इसके लिए परिवर्तनकारी कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर कदम उठा रही है।"

सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

जागरण रिसर्च

इधर-उधर की

दुनिया की सबसे छोटी बच्ची ठीक होकर घर लौटी

जन्म के समय सिर्फ 212 ग्राम था बच्ची का वजन। इंटरनेट मीडिया

सिंगापुर, एजेंसी : प्रकृति की लीला और विज्ञान की ताकत, इन दोनों का अनूठा प्रमाण बनी है सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में सालभर पहले जन्मी एक बच्ची। प्रकृति की लीला ही है कि जन्म के समय बच्ची का वजन मात्र 212 ग्राम था, जो बमुश्किल किसी बड़े सेब का वजन होता है। अब विज्ञान की ताकत से 13 महीने बाद वह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आई है। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जन्म के समय उसे दुनिया की सबसे छोटी बच्ची माना गया है। अस्पताल की नर्स ने इस बारे में कहा, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। बच्ची अब स्वस्थ है। उसका वजन 6.3 किलोग्राम हो गया है।

आइएसएस में हुआ अंतरिक्ष ओलिंपिक

अद्भुत ▶ अंतरिक्ष यात्रियों ने ओलिंपिक समापन समारोह देखने के साथ किया खेलों का आयोजन

जीरो ग्रैविटी में तैराकी, जिमनास्टिक्स और शार्प शूटिंग के वीडियो किए गए ट्वीट

नई दिल्ली, आइएएनएस : अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) में अंतरिक्ष यात्रियों ने टोक्यो ओलिंपिक-2020 के समापन समारोह को देखते हुए 'जीरो ग्रैविटी' में ओलिंपिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इस दौरान उन्होंने तैराकी की। बिना जमीन के जिमनास्टिक्स किए। इस संबंध में फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री थामस पेसिक्वे ने रविवार को ट्विटर पर कई वीडियो साझा किए।

फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री पेसिक्वे यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) से हैं। उनके ट्वीट किए वीडियो में आइएसएस के अंतरिक्ष यात्री बिना गुरुत्वाकर्षण के अपने प्रिय खेलों का मजा ले रहे हैं। उन्होंने शार्प शूटिंग का भी सत्र रखा जिसमें लक्ष्य अपना स्थान बदलता रहता है। उन्होंने रबर बैंड जैसी दिखने वाली एक वस्तु से निशाना लगाया और इसे 'वेटलेस शार्प शूटिंग' का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस खेल में ध्यान केंद्रित करने और कौशल (जीरो ग्रैविटी के संदर्भ में) की आवश्यकता होती है।

उन्होंने वीडियो के परिचय में लिखा कि तैराकी में अंतरिक्ष यात्रियों ने बिना पानी के ही जीरो ग्रैविटी में गोताखोरी की। इसके लिए उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ी। उनके लिए यह टीमवर्क दिखाने का एक बेहतरीन अवसर था। पेसिक्वे ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना हैंडबाल के खेलने में उन्हें खेल के कुछ नियम बदलने पड़े, लेकिन दोनों टीमों ने जीतने के लिए काफी मेहनत की। अंतरिक्ष यात्रियों ने खेल प्रतियोगिता के अंत में अपने-अपने देशों के झंडों को भी स्पेस स्टेशन में लगाया। आखिर में जापान स्पेस एजेंसी (जाक्सा) के अकी होशाइड ने समापन समारोह की परंपरा का निर्वाह करते हुए ओलिंपिक फ्लैग को पेसिक्वे को सौंपा, क्योंकि 2024 में अगला ओलिंपिक फ्रांस में होने वाला है।

अंतरिक्ष में ओलिंपिक... अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) में अंतरिक्ष यात्रियों ने टोक्यो ओलिंपिक-2020 के समापन समारोह के दौरान 'जीरो ग्रैविटी' में अंतरिक्ष ओलिंपिक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने शून्य में तैराकी के साथ ही अन्य खेलों में भी हाथ आजमाए। सौ. ट्विटर

कोविड-19 से बचाव में कारगर हैं सर्दी के खिलाफ बनने वाली एंटीबाडी

अनुसंधान

स्वास्थ्यकर्मियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि संक्रमण के सात महीने बाद भी न केवल आइजीजी एंटीबाडी शरीर में बनी रहती हैं, बल्कि कुछ लोगों में इसका स्तर बढ़ भी जाता है। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में सामने आया है कि सामान्य सर्दी से जुड़े कोरोना वायरस (ह्यूमन कोल्ड कोरोना वायरस-एचसीओवी) के खिलाफ शरीर में जो एंटीबाडी बनती हैं, वह कोविड-19 से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह अध्ययन बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फार ग्लोबल हेल्थ के साथ मिलकर किया गया है। आने वाली महामारी और उसके खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए शरीर में मौजूद इम्युनिटी को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर आइएसग्लोबल के शोधकर्ता कार्लोटा डोबानो के नेतृत्व वाली टीम ने विभिन्न कोरोना वायरस के खिलाफ स्वास्थ्यकर्मियों के शरीर में बनने वाली एंटीबाडी का अध्ययन किया। परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं की टीम ने मार्च और अक्टूबर 2020 के बीच चार अलग-अलग समय पर 578 स्वास्थ्यकर्मियों के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया। रक्त के एक ही नमूने में छह अलग-अलग प्रकार के कोरोना वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबाडी (आइजीए, आइजीजी और आइजीएम) के स्तर को मापने के लिए ल्यूमिनेक्स तकनीक का उपयोग किया। अध्ययन के सह लेखक जेमा मोनक्यूनिल के मुताबिक, सामान्य फ्लू से जुड़े कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबाडी बनती हैं, वे कोविड-19 के खिलाफ महामारी में भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

मैं कौन सी तोप हूं : कृति खरबंदा

कृति की हालिया रिलीज फिल्म थी 14 फेरे। इंस्टाग्राम

शोबिजनेस में काम करना आसान नहीं। कई बार इस इंडस्ट्री के मुताबिक अपना स्वभाव भी बदलना पड़ता है। कुछ लोग दूसरों के मुताबिक बदलते हैं, कुछ कलाकार अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। बात करें अगर 14 फेरे, शादी में जरूर आना फिल्मों की अभिनेत्री कृति खरबंदा की तो वह काफी मिलनसार हैं, लेकिन वह अपने स्वभाव को किसी के लिए भी बदलने में यकीन नहीं रखती हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में कृति ने कहा कि मैं इतनी मिलनसार इसलिए हूं, क्योंकि मैं दूसरों से भी इस तरह के स्वभाव की उम्मीद करती हूं। किसी के साथ हंसकर मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं किस बात का एटीट्यूड दिखाऊं, मैं कौन सी तोप हूं। हम सब इंसान हैं। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। कई लोगों ने मुझे अपने इस मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव को बदलने के लिए भी कहा है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं बदलूंगी। मैंने उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जो मुझे बदलने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई बदलाव मेरी बेहतरी के लिए है तो शायद मैं उस बारे में सोच भी सकती हूं, लेकिन अगर मेरा स्वभाव मिलनसार है, दूसरों को खुशी देता है तो इसे बदलने की क्या जरूरत है।

मैंने अपनी फिल्म शमशेरा देख ली है : वाणी

<< पीरियड फिल्म शमशेरा में नजर आएंगी वाणी ● इंस्टाग्राम

शमशेरा पिछले साल से बनकर तैयार है। हालांकि कोरोना के चलते रिलीज नहीं हो पाई। अब भी रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है।

महामारी की वजह से रिलीज की बाट जोह रही फिल्मों में पीरियड फिल्म शमशेरा भी शामिल है। यह फिल्म पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई फिल्मों की तरह इसकी रिलीज भी महामारी के चलते बंद पड़े सिनेमाघरों की वजह से रुकी हुई है। अब धीरे-धीरे कई जगहों पर सिनेमाघर खुल रहे हैं। उसके साथ फिल्म की रिलीज डेट भी घोषित हो रही हैं। वाणी की आगामी फिल्म बेल बाटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि शमशेरा की रिलीज को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यशराज फिल्म्स की पीरियड फिल्म शमशेरा में वाणी कपूर के अपोजिट रणबीर कपूर हैं। रणबीर के साथ काम करने के अनुभवों को लेकर वाणी ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, मैंने फिल्म देखी है, मुझे खुशी है कि मैं शमशेरा का हिस्सा हूं। फिल्म का निर्देशन करण मल्होत्रा ने किया है। मुझे उनकी फिल्म अग्निपथ पसंद आई थी, जिसमें रितिक रोशन थे। जब शमशेरा फिल्म का आफर मिला तो काम करना ही था। दूसरा सबसे बड़ा कारण रणबीर कपूर थे। वह बहुत ही जमीन से जुड़े इंसान हैं। उन्हें कहीं भी बिठा दो, धूप हो, गर्मी हो, किस होटल में ठहराया है, कमरा कैसा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस अपने काम से लगाव है। वह सेट पर अपनी पूरी तैयारी करके आते थे। मैंने जब फिल्म देखी तो उनके कई शाट्स देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कब कर लिया। वह बहुत ही नैचुरली सीन कर जाते हैं। उन्हें देखकर काफी कुछ सीखा है। सुलझे हुए एक्टर हैं, उन्हें पता है फोकस कहां रखना है, अपने किरदार को अलग रखने की कोशिश करते हैं। बेल बाटम में वाणी अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी।

जल्द ही शुरू करूंगा भौकाल 2 की शूटिंग : सिद्धांत कपूर

चेहरे फिल्म में नजर आएंगे सिद्धांत। इंस्टाग्राम

स्टार किड्स के लिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री की राहें आसान होती हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर के लिए यह राहें आसान नहीं रही हैं। सिद्धांत अपने लिए अच्छे किरदार की तलाश कर रहे हैं। शूटआउट एट वडाला, जज्बा जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके सिद्धांत अपने फैंस के साथ लाइव जुड़े। लाइव के दौरान उनके फैंस ने उनसे कई सवाल किए। एक यूजर ने पूछा कि आप किस तरह के किरदारों की तलाश में हैं। इस पर सिद्धांत ने कहा कि मेरी तलाश अलग-अलग किरदारों को करने की है। मैं एक ही तरह के किरदार नहीं कर सकता हूं। खुद के लिए अच्छे किरदारों की तलाश करना चुनौतीपूर्ण है। एक फैन ने जब उनसे पूछा कि आप किस तरह के इंसान हैं। इस पर सिद्धांत ने कहा कि मैं आध्यात्मिक इंसान हूं। हर इंसान की इज्जत करता हूं। मेरा मानना है कि सबको एक-दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक-दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सिद्धांत की आगामी फिल्म चेहरे होगी। फिल्म बनकर तैयार है और रिलीज के इंतजार में है। वहीं, सिद्धांत ने बताया कि जल्द वह अपनी आगामी वेब सीरीज भौकाल के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू करेंगे।

मैं करियर के शुरुआत से ही निर्देशन करना चाहता था : अरविंद स्वामी

अरविंद ने की बतौर निर्देशक अपने सफर की शुरुआत। इंस्टाग्राम

हिंदी सिनेमा में अजय देवगन, कंगना रनोट और सनी देओल जैसे कई एक्टर अभिनय के साथ-साथ निर्देशन भी करते रहते हैं। अब रोजा, बांबे और सात रंग के सपने जैसी फिल्मों के अभिनेता अरविंद स्वामी ने भी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एंथोलाजी वेब सीरीज नवरस से निर्देशन में कदम रख दिया है। नौ अलग-अलग कहानियों के माध्यम से इंसान के करुणा, हास्य, आश्चर्य, वीभत्स, शांत, रौद्र, वीर और श्रृंगार रस को प्रदर्शित करती इस वेब सीरीज में अरविंद ने रौद्रम कहानी का निर्देशन किया है। इस शो का निर्माण फिल्मकार मणिरत्नम ने किया है। ज्यादातर तमिल फिल्मों में सक्रिय रहे अरविंद का निर्देशन के प्रति लगाव कोई नया नहीं है। उनके मुताबिक, उन्हें करियर के शुरुआती दौर से ही निर्देशन में दिलचस्पी रही है। दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में अरविंद ने कहा, 'मेरी दिलचस्पी पिछली सदी के नौवें दशक से ही निर्देशन में थी। जब मणि सर (मणिरत्नम) ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नवरस का हिस्सा बनना चाहूंगा तो मैंने उनसे पूछा कि बतौर एक्टर या डायरेक्टर। फिर उन्होंने इसका चुनाव मेरे ऊपर छोड़ दिया। तीन दशकों से कैमरे का सामना करते हुए निर्देशन को लेकर मुझे अच्छी समझ थी। मैंने अपने तीन दशकों के करियर में देश के कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है। अगर आपको अपनी कला से प्यार है, आप इसे देखते और सीखते हो तो एक दिन आप इसे जरूर परखना चाहेंगे।' नवरस में नौ अलग-अलग कहानियों को नौ अलग-अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया गया है।

यूनिफार्म पहनने के बाद सोच बदल गई : अजय

भुजः द प्राइड आफ इंडिया में सेना के अधिकारी की भूमिका में हैं अजय ● इंस्टाग्राम

युद्ध पर फिल्म बनाना और उसमें काम करना, दोनों ही मुश्किल काम हैं। अभिनेता अजय देवगन साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म भुजः द प्राइड आफ इंडिया में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका निभा रहे हैं। एक लाइव चैट के दौरान गीतकार मनोज मुंतशिर ने विजय कार्णिक और पर्दे पर उनकी भूमिका निभा रहे अजय से बात की। मनोज ने विजय कार्णिक से पूछा कि उन्होंने क्यों इस फिल्म को बनाने की इजाजत दी। इस पर विजय ने कहा कि फिल्म के निर्देशक अभिषेक दुधैया मेरे पास आए और इसको लेकर अपनी रिसर्च की जानकारी दी। वह भुज के माधापुर के गांव की महिलाओं से भी मिले थे। मैं समझ गया था कि इसे वह जरूर दर्शा पाएंगे। एक सवाल पर अजय ने कहा कि देश में असली हीरोज ने बहुत त्याग किए हैं। दिमाग में यही था कि यह कहानी सभी लोगों को पता चले। वैसे भी यूनिफार्म में इतनी ताकत है कि उसे पहनने के बाद सोच बदल जाती है। खुद में कोई पावर सी महसूस होती है। इस फिल्म की कहानी इस गौरव और जज्बे को दिखाएगी।

अभी लंबा रास्ता तय करना है : संजय लीला भंसाली

भंसाली के प्रोडक्शन हाउस के हुए 25 साल ● इंस्टाग्राम

हम दिल दे चुके सनम, देवदास और पद्मावत जैसी कई फिल्मों का निर्माण कर चुके फिल्मकार संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन कंपनी भंसाली प्रोडक्शंस की स्थापना को सोमवार को 25 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर तमाम हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया पर भंसाली प्रोडक्शन की तमाम फिल्मों के सफर को दिखाते वीडियो को साझा करते हुए शुभकामनाएं दीं। वहीं संजय के साथ बाजीराव मस्तानी और पद्मावत फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे याद है कि मैं सोचा करती थी कि मैं कभी इतनी अच्छी प्रतिभा नहीं हो सकती कि संजय लीला भंसाली के साथ काम कर पाऊं। फिर आते हैं साल 2012 में। मैं बहुत बीमार थी और बेड पर लेटी हुई थी। मुझे अपने मैनेजमेंट से एक काल आया कि भंसाली आपसे मिलना चाहते हैं। वह एक फिल्म कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तो उनसे कार्टव्हील (गुलाटी) करते हुए भी मिलने जाने के लिए तैयार थी। बाद में मुझे पता चला कि वह खुद मुझसे मिलने के लिए रास्ते में हैं।' वहीं संजय ने कहा, 'इन 25 वर्षों में मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उनमें दीवार के रंग, गाने, पृष्ठभूमि, कास्ट्यूम का हर धागा, हर संवाद, लाइट्स, नक्काशी और कला जैसी हर चीज पर बहुत काम किया गया है। मैंने हर पल का आनंद लिया है... अभी और भी लंबा रास्ता तय करना है।' भंसाली फिलहाल गंगूबाई काठियावाड़ी और हीरा मंडी पर काम कर रहे हैं।

'इंडियन आइडल 12 ने हमें प्लेबैक सिंगिंग के लिए तैयार कर दिया है'

इंडियन आइडल 12 के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं पवनदीप। सौ. सोनी पीआर टीम

सिंगिंग हो या डांसिंग, रियलिटी शोज के प्लेटफार्म न सिर्फ नए कलाकारों की कला लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, बल्कि इन मंचों पर कलाकारों की कला में भी निखार होता है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 15 अगस्त को इस शो के फाइनल में शीर्ष छह प्रतिभागी पवनदीप राजन, शन्मुख प्रिया, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले, मोहम्मद दानिश और निखिल तौरो विजेता खिताब हासिल करने के लिए लगातार 12 घंटे प्रतिस्पर्धा करेंगे। फाइनल मुकाबले से पहले सोमवार को सभी प्रतिभागियों के साथ इस शो की वर्चुअल कांफ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर पवनदीप ने शो में आने के बाद खुद में बदलाव को लेकर कहा, 'हम सभी छोटे-छोटे शहरों या गांवों से आए हुए हैं। इस शो ने इस महानगर में हमें इतना बड़ा मौका दिया। इंडियन आइडल वालों ने हम सभी को प्लेबैक के लिए तैयार कर दिया है। हम सभी ने यहां सभी प्रकार के गाने गाए हैं। पुराने गाए हुए गानों को तो हम उनके गायकों को सुनकर सीख सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया गाना मिले तो कैसे गाएं, यह समझना मुश्किल होता है। इंडियन आइडल हमारे लिए एक स्कूल ही है। यहां हम लोगों ने 10 महीने की पूरी क्लास ली है, रोजाना रियाज किया है। अब हमारा म्यूजिक का सेंस थोड़ा सा बढ़ गया है।' वहीं, निखिल तौरो ने कहा कि इस शो में आने से पहले मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। मुझे डर था कि मैं दक्षिण भारत से हूं तो पता नहीं मुझे हिंदी भाषी दर्शक स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन इस शो में न सिर्फ मुझे बहुत प्यार मिला, बल्कि मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई है।

हंसल मेहता की फिल्म से करीना भी बनीं प्रोड्यूसर

आगामी दिनों में फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ नजर आएंगी करीना ● पीआर टीम

हिंदी सिनेमा में दो दशक से ज्यादा समय से सक्रिय अभिनेत्री करीना कपूर खान अब अभिनय के साथ-साथ फिल्म निर्माण में भी उतर गई हैं। वह हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही अनाम फिल्म को एकता कपूर के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रोड्यूस करेंगी। ब्रिटेन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित होगी, जिसमें करीना अभिनय भी करेंगी। इस थ्रिलर फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। इससे पहले करीना ने एकता कपूर के प्रोडक्शन में साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म वीरे दी वेडिंग में बतौर अभिनेत्री काम किया था। अपने इस नए सफर को लेकर उत्साहित करीना का कहना है, 'एकता के साथ इस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर काम करने को लेकर मैं बहुत सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं हंसल की फिल्मों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं और उनके साथ पहली बार इस फिल्म में काम करना खास होगा। इस फिल्म में और भी कई चीजें पहली बार हो रही हैं।' वहीं निर्देशक हंसल मेहता ने कहा, 'इस फिल्म के जरिये हमारा उद्देश्य करीना के साथ एक ताजा, मनोरंजक और मुड़ी थ्रिलर बनाना है। मुझे उम्मीद है कि बतौर अभिनेत्री उनकी प्रतिभा इस फिल्म के साथ न्याय करेगी। एकता और करीना के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूं।'